

In Pursuit of Truth

वर्ष 19, अंक-21
1 से 15 अगस्त 2021
पृष्ठ-48
मूल्य 25 रूपये

आक्ष



- मेट्रो ट्रैक का निर्माण अब पकड़ेगा रफ्तार
- इमोशनल कार्ड या सक्रियता पर दांव...?



जासूसी का जाल देशभर में बवाल

पेगासस जासूसी मामले को लेकर
सड़क से संसद तक विपक्ष हमलावर

We Deal in Pathology & Medical Equipment

BC-6800

Auto Hematology .



Anu Sales Corporation

Add: Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

☎ M.: 9329556524, 9329556530 ✉ Email : ascbhopal@gmail.com

विधानसभा

9 | हंगामेदार होगा मानसून सत्र

4 दिनी मानसून सत्र के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। सत्तापक्ष जहां महत्वपूर्ण बिलों और विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में लगा हुआ है, वहीं विपक्ष सत्तापक्ष को घेरने की।

राजपथ

10-11 | हम दो...हमारे चाहे जितने...!

उग्र में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा आते ही पड़ोसी राज्य मप्र में शिवराज सरकार के कई मंत्री और विधायक इसकी वकालत करने लगे हैं। विपक्ष कह रहा है भाजपा आबादी पर काबू पाने के नाम पर सियासत...

मुद्दा

13 | मंत्री की मनमानी पड़ेगी भारी...

कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने गरीबों को हर माह 10 किलो अनाज देने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत 7 अगस्त को अन्न उत्सव से होगी। मप्र में उस दिन एक साथ 30 लाख परिवारों को मुफ्त अनाज बांटा जाएगा।

अवैध खनन

15 | टारगेट पूरा करने का टशन

मप्र देश में सबसे अधिक खनिज संपदा वाले राज्यों में से एक है। लेकिन यहां सरकार को उससे अधिक आय नहीं हो पाती है। जानकारों का कहना है कि प्रदेश में सरकार से अधिक तो माफिया खनिज संपदा से कमाई करते हैं। खासकर रेत का खेल तो निराला है। यहां वैध से अधिक अवैध...



भारत सहित दुनियाभर में इन दिनों पेगासस जासूसी कांड छाया हुआ है। देशभर में सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। जहां तक जासूसी का सवाल है तो यह कोई नई बात नहीं है। शायद मानव इतिहास के प्रारंभ से ही जासूसी चलती आ रही है। प्राचीन काल में चाहे राजा रहे हों या आज की सरकारें, उन्हें जनता की टोह लेने या पड़ोसी देश की सैन्य शक्ति की जानकारी हासिल करने के लिए जासूसी का सहारा लेना पड़ता है। जासूसी के बल पर न जाने कितने युद्ध जीते गए होंगे।

30-31



34



39



45



सियासत

32-33 | 2024 में खेला होगा!

जो आरजेडी-कांग्रेस न कर पाई वो ममता बनर्जी ने किया और जो एनसीपी-कांग्रेस-शिवसेना ने मिलकर किया, वो ममता बनर्जी ने अकेले कर दिखाया। पश्चिम बंगाल में भाजपा को हराकर तीसरी बार सत्ता को हासिल कर लिया। शायद यही वजह है कि देश की राजनीति के सबसे...

महाराष्ट्र

35 | बन रहे नए समीकरण

देश के प्रधानमंत्री के साथ हुई हर मुलाकात महत्वपूर्ण होती है - और जब ये किसी विपक्षी नेता से तो हर किसी के कान खड़े हो ही जाते हैं। वो भी तब जब उस नेता के साथ मुलाकात हो जो सत्ताधारी दल के गठबंधन साथी को छीन कर अपने साथ सरकार बना लिया हो-और अगले आम चुनाव...

बिहार

38 | लालू ने जगाई उम्मीदें...

तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने अच्छी कामयाबी अर्जित की है। राजद अकेले सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है, परंतु नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू से विरोधी दल हमेशा सशक्ति रहते आए हैं।

6-7 | अंदर की बात

41 | महिला जगत

42 | अध्यात्म

43 | कहानी

44 | खेल

45 | फिल्म

46 | व्यंग्य



हम सबकुछ बेचते हैं...खरीदार तो मिले

कि सी शायर ने लिखा है...

जुर्म वही बख्श फिरदार बदल गया, ख़बर वही बख़्श अख़बार बदल गया।

सत्ता आज भी ख़रेआम नीलाम है, कीमत वही बख़्श ठेकेदार बदल गया।।

ऐसा ही कुछ फसाना पिछले दिनों सामने आया जब देश के सबसे बड़े मीडिया समूह में से एक दैनिक भास्कर समूह पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। छापे को लेकर तरह-तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन आयकर छापे के बाद जो तथ्य सामने आया उसमें यह बात सामने आई कि दैनिक भास्कर गुप जनहित की पत्रकारिता के साथ ही डीबी पावर प्लांट चला रहा है। तेल बेच रहा है। नमक बेच रहा है। कोयला घोटाले कर रहा है। मांस-मछली बेच रहा है। यानी भास्कर सबकुछ बेच रहा है बख़्श ख़रीदार की जरूरत है। आयकर विभाग के नीति निर्धारक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किए गए दावे में अब तक छापे में 2200 करोड़ रुपए का सदिग्ध लेनदेन सामने आना बताया गया है। अब इस समूह से जब दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हद तो यह हो गई कि इस समूह द्वारा अपने कई कर्मचारियों के नाम पर भी थोख़रे से कई शैल कंपनियां बनाई जाने की बात सामने आई है। इसके अलावा कई अन्य तरह का फर्जीवाड़ा करने का भी खुलासा हुआ है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस समूह के भोपाल मुख्यालय से मीडिया, ऊर्जा, टेक्स्टाइल और रियल एस्टेट जैसे कई क्षेत्र में कारोबार किया जा रहा था। इस समूह का सालाना टर्नओवर 6000 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है। अब तक छापे में मिले समूह की कंपनियों के कारोबार में कर चोरी और अन्य कानूनी उल्लंघन का पता लगाने का काम जारी है। उधर सीबीडीटी भी कंपनी कानून के खंड 49 के कुछ हिस्सों व सेबी के नियमों के उल्लंघन की पड़ताल कर रही है। इसके अलावा अब समूह के बेनामी लेनदेन कानून के तहत भी जांच शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। सीबीडीटी के दावे के मुताबिक इस गुप द्वारा मीडिया के अलावा ख़नन, अस्पताल, शराब, ऊर्जा और रियल एस्टेट का भी कारोबार किया जा रहा है। हकीकत क्या है यह तो भास्कर समूह और सीबीडीटी ही जानते हैं लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि हिंदी के सबसे बड़े इस अख़बार को बेचने के लिए दबाव स्वरूप यह छापेमारी की गई थी। कहा जा रहा है कि देश का एक बड़ा औद्योगिक घराना इस अख़बार को ख़रीदना चाहता है। वह घराना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में दस्तक दे चुका है। ख़ैर अख़लियत क्या है, यह तो वही जाने लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मीडिया समूह पर छापे के विरोध में मद्रास का कोई भी मीडिया समूह खड़ा नजर नहीं आया। इसकी वजह भी साफ है। जब भी किसी मीडिया समूह पर छापा पड़ा है या आरोप लगा है भास्कर ने कसीदें गढ़-गढ़कर उक्त संस्थान की भद्र पिटवाई है। दरअसल, भास्कर समूह जैसे-जैसे बड़ा होता गया, वह अपनी बिरादरी (अख़बारों) को बदनाम करने का कोई मौका नहीं चूका। इसी का परिणाम रहा कि जब भास्कर समूह पर छापा पड़ा तो हर छोटे-बड़े अख़बार ने नमक-मिर्च मिलाकर संस्थान की ख़ामियां छापना शुरू कर दिया। अगर शुरू से ही भास्कर अन्य अख़बारों को साथ लेकर चलता तो आज उसके पक्ष में बड़ा माहौल निर्मित हो सकता था। लेकिन बड़े-बड़ों का ख़ेल बिगाड़ने वाला भास्कर अकेला पड़ गया है और तिनके की भांति डूबता जा रहा है। भास्कर समूह पर छापा क्यों पड़ा है यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन हकीकत जानते हुए भी कोई भी उसके समर्थन में खड़ा होने को तैयार नहीं है।

- राजेन्द्र आगाल

आख़बार

वर्ष 19, अंक 21, पृष्ठ-48, 1 से 15 अगस्त, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लॉट नम्बर 150, ज़ोन-1 मनोरमा कॉम्प्लेक्स,

एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर

भोपाल- 462011 (म.प्र.),

फोन नं. 0755-2557777, टेलीफैक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com

Website : www.akshnews.com

RNI NO. HIN/2002/8718

MP/PL/642/2021-23

ब्यूरो

मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, कोलकाता:- इंद्रकुमार,

जयपुर:- आर.के. बिनानी, छत्तीसगढ़:- संजय शुक्ला,

मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, लखनऊ :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे

098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया

094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार

098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इन्क्लेव

मायापुरी-फोन : 9811017939

जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर

(रामस्थान) मोबाइल-09829 010331

रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,

फोन : 0771 2282517

भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला,

रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015

इंदौर : 39 श्रुति सिल्टर निगमिया, इंदौर

मोबाइल - 7000123977

स्वातधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 150, ज़ोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।



महंगाई की मार

कोरोना ने जिंदगी को तबाह कर दिया है। मजदूरी का ग्राफ नीचे आ गया है, काम-धंधा चौपट है। जिंदगी को पटरी पर आने में समय लगेगा लेकिन लगता नहीं कि महंगाई ऐसा करने देगी। क्योंकि जिस रफ्तार से लोगों का रोजगार जा रहा है, महंगाई भी उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है।

● **श्रीरंभ सोनी**, ग्वालियर (म.प्र.)

विपक्ष की दरकार

देश में अशक्त विपक्ष की दरकार है, जो भाजपा को दमदार चुनौती दे सके। लेकिन जनता का दुर्भाग्य है कि विपक्ष खंड-खंड बंटा हुआ है। सब के सब महत्वकांक्षी हैं, जो प्रधानमंत्री पद के मंसूबे पाले हुए हैं। आम जनता को विपक्षी दलों से ही आशा है। विपक्ष को इस बारे में सोचना चाहिए।

● **रवि माथुर**, शिवपुरी (म.प्र.)

गांवों पर ध्यान दे सरकार

देश की राज्य सरकारें ग्रामीण अंचलों की ओर ध्यान ही नहीं दे रही हैं। प्रथमदृष्टि में ग्रामीण अंचल की स्थिति को बड़े सटीक रूप में दर्शाया गया है। लेकिन आज भी यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अकाल पड़ा हुआ है। यही कारण है कि शहर से गांव तक कोरोना इतना फैल रहा है।

● **पवन झाबिया**, रीवा (म.प्र.)



कांग्रेस को ऑक्सीजन की जरूरत

गांधी परिवार का दरबार बन चुकी सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस नाए भारत में मजाक बनकर रह गई है। सफल राजनीतिक पार्टियां अपने प्रतिभाशाली नेताओं को मौके देती हैं। वक्त की नजाकत भांप उन्हें आगे करती हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। इसीलिए उस पर परिवारवाद का आरोप लगता आ रहा है। कांग्रेस को इंदिरा गांधी के दौर से ही परिवार भक्त नेता पसंद हैं। ऐसे नेता जो गांधी परिवार की हां में हां मिलाते रहे। हालांकि इंदिरा गांधी खुद भी एक बड़ी नेता थीं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1971 का युद्ध और जनता के बीच जाकर राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल उन्होंने बखूबी किया। आज के समय में कांग्रेस पार्टी को ऑक्सीजन की जरूरत है।

● **सुरभि सिंह**, भोपाल (म.प्र.)

आमजन के लिए सस्ती बिजली

प्रदेश सहित देशभर के कई गांवों में आज भी बिजली नहीं है। लाखों लोगों को आज भी अंधेरे में रहना पड़ता है। मप्र में अभी बिजली के लिए जल विद्युत परियोजना, कोयला आधारित पावर प्लांट पर ही अधिक निर्भर रहना पड़ता था। सोलर प्लांट से मिलने वाली सस्ती बिजली का फायदा आने वाले समय में प्रदेश के आम लोगों को भी मिलेगा। जिससे लोगों की जिंदगी में उजाला होगा।

● **रंजीत खेर**, जबलपुर (म.प्र.)

रोजगार देने की पहल

कोरोनाकाल में लाखों लोगों का रोजगार छिन चुका है। मप्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अब प्रदेश में शिक्षा समाप्त होते ही युवाओं को रोजगार मिलने की अबूटी पहल शुरू की गई है। मुख्यमंत्री की पहल पर शिक्षा समाप्त होने के बाद पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए सरकार सभरी 52 जिलों में प्लेसमेंट अधिकारी नियुक्त करेगी। प्रदेश के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। जिससे उनके लिए रोजगार का द्वार खुलेगा।

● **पंकज शिवदत्ते**, इंदौर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल



ठिकाने लगे सभी बारी-बारी

केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में काबिज भाजपा अब पूरी तरह से मोदी-शाह की भाजपा में तब्दील हो चुकी है। अटल-आडवाणी काल के ज्यादातर प्रमुख चेहरे या तो मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बन चुके हैं या फिर राज्यों में राज्यपाल बनाकर एक्टिव राजनीति से दूर कर दिए गए हैं। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तो अब गिने-चुने ही ऐसे नेता मंत्री पद पर बचे हैं जिनका पहले वाली भाजपा में खासा कद हुआ करता था। पार्टी के दो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी अकेले ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी कुर्सी हाल फिलहाल तक सलामत है। नए मंत्रिमंडल में 30 कैबिनेट मंत्री हैं जिनमें से अधिकांश या तो आयातित चेहरे हैं या फिर जनाधार विहीन हैं। 5 कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जिनका राजनीति से दूर-दूर तक का कोई नाता नहीं रहा है। ये पांचों आईएएस अथवा आईपीएस अफसर रह चुके हैं। दो मंत्री कांग्रेसी मूल के हैं तो अन्य ऐसे चेहरे हैं जिनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर कभी नहीं रही। राज्य मंत्रियों में तो अधिकांश ऐसे ही चेहरों की भरमार है। पुरानी भाजपा के कई दिग्गज हालिया फेरबदल में पैदल किए जा चुके हैं। इनमें कई बार के सांसद संतोष गंगवार, डॉ. हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद्र गहलोत, डीवी सदानंद गौड़ा, प्रकाश जावेडकर आदि शामिल हैं।

पायलट के बहुरेंगे दिन

राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की खबर इन दिनों 24 अकबर रोड में कही-सुनी जा रही है। अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले सचिन पायलट को राहुल गांधी का अत्यंत करीबी माना जाता है। पार्टी सुप्रीमो का विश्वसनीय होते हुए भी राजस्थान सरकार में उनकी सुनवाई न होना और उनके समर्थक विधायकों को अशोक गहलोत द्वारा लगातार इनोरे करना अब एक बार फिर से गर्माने लगा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार लेकिन पार्टी आलाकमान सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा। जल्द ही राजस्थान कैबिनेट का विस्तार कर पायलट समर्थक विधायकों में कुछेक को मंत्री बनाया जा रहा है तो सचिन को दोबारा उपमुख्यमंत्री बनाने के बजाय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के आसार हैं। जानकारों का दावा है कि अगली बार पार्टी यदि चुनाव जीतती है तो सचिन ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे इसलिए संगठन की कमान अभी से उन्हें देने का निर्णय पार्टी आलाकमान ले चुका है। इतना ही नहीं खबरों का बाजार इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि अगले बरस राहुल गांधी यदि दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बने तो गहलोत को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिल्ली बुलाया जा सकता है और राज्य सरकार की कमान सचिन को सौंपी जा सकती है।



छत्तीसगढ़ में भी शुरू रार

कांग्रेस भले ही भाजपा के हाथों पूरी तरह, बुरी तरह परास्त हो चुकी पार्टी बनकर रह गई हो, उसके नेताओं की अक्ल पर लगे ताले अभी तक टूटे नहीं हैं। मात्र तीन राज्यों में उसकी अपने दम पर सरकारें हैं और दो राज्यों में वह गठबंधन सरकारों का हिस्सा है। इसके बावजूद पार्टी के बड़े नेताओं की आपसी रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच पार्टी आलाकमान भरकस प्रयास करने के बावजूद सुलह कराने में पूरी तरह विफल रही है। खबर जोरों पर है कि सिद्धू को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने से कैप्टन अमरिंदर खासे खफा हैं और कांग्रेस के इतर अपनी पार्टी बनाए जाने का विकल्प तलाश रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में जबरदस्त बहुमत वाली भूपेश बघेल सरकार भी अस्थिरता की कगार पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री बघेल को बदले जाने की मांग यहां जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश कांग्रेस में भूपेश बघेल की जगह मुख्यमंत्री बनने की चाह रखने वालों में टीएस सिंह देव, चरणदास महतो और ताम्रध्वज साहू का नाम शामिल है। पार्टी सूत्रों की माने तो बघेल को मुख्यमंत्री बनाते समय कांग्रेस आलाकमान ने सिंह देव से वायदा किया था कि सरकार के ढाई बरस पूरे होने पर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा।

ढाई नेताओं की पार्टी

कांग्रेस के प्रवक्ता अक्सर भाजपा को ढाई नेताओं की पार्टी कह पुकारते हैं। ढाई में दो प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह तो आधा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के लिए विपक्षी दल प्रयोग में लाते हैं। पिछले दिनों हुए मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल बाद अब कई बड़े भाजपा नेता भी विपक्ष की भाषा ऑफ द रिकॉर्ड बोलने लगे हैं। ऐसे नेताओं का मानना है कि पार्टी पूरी तरह से दो नेताओं के हाथों कठपुतली बन चुकी है। अटल-आडवाणी के समय पार्टी का संसदीय बोर्ड खासा ताकतवर हुआ करता था। अब इस पार्टी फोरम की चमक समाप्त हो चली है। हालात इतने खराब हैं कि पिछले कई वर्षों से इसका न तो पुनर्गठन किया गया है न ही इसमें रिक्त हुए पदों को भरा जा रहा है। अरुण जेटली और अनंत कुमार की मृत्यु हुए अरसा हो गया है। दोनों ही इस संसदीय बोर्ड के सदस्य थे। इनकी मृत्यु के चलते रिक्त स्थान अभी तक खाली पड़े हैं। ये पद कब भरे जाएंगे, इसका फिलहाल कोई पता नहीं है, जबकि पार्टी में अन्य पद भी खाली होते जा रहे हैं।

योगीमय होते मोदी

अभी कुछ अरसा पहले तक मुख्यधारा के मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक चौतरफा खबरों की भरमार उग्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा आलाकमान के मध्य चल रही तकरार को लेकर थी। कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह योगी की कार्यशैली के चलते उनसे खासे नाराज हैं। खबरों का बाजार योगी को बदले जाने से लेकर उन पर नकेल डालने के लिए पूर्व नौकरशाह एके शर्मा को प्रदेश का उपमुख्यमंत्री बनाए जाने और उन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दिए जाने का इशारा कर रहा था। फिर खबरें आने और छाने लगी कि योगी बगावत पर उतर आए हैं। वे किसी भी कीमत पर शर्मा को अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाने के लिए रजामंद नहीं हो रहे हैं। संघ के नंबर दो दत्तात्रेय होसबोले और भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष का लखनऊ दौरा भी खासा चर्चा में रहा। इन दिग्गजों की योगी संग लंबी बैठक बेनतीजा रही और योगी के बगावती तेवर बरकरार रहे।

माफ करो मंत्रीजी...

प्रदेश में इस समय लगभग हर मंत्री और उनके परिजन लक्ष्मी की पूजा-अर्चना में जुटे हुए हैं। सबकी एक ही कोशिश है कि लक्ष्मीजी की अधिक से अधिक कृपा हासिल की जाए। इसके लिए वे सारे उपक्रम किए जा रहे हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रदेश के सबसे सशक्त विभाग की कमान संभालने वाले मंत्रीजी के तो कुछ अलग ही रंग-ढंग हैं। वे चाहते हैं कि विभाग में उनके बिना कोई पता भी नहीं हिले। भले ही नियम कुछ और कहे। यानी नियमों को ताक पर रखकर मंत्रीजी हर काम करना चाहते हैं। विगत दिनों विभाग में कनिष्ठ अधिकारियों के तबादले को लेकर मंत्रीजी ने विभाग के मुखिया से जवाब-तलब किया, उस पर विभाग के मुखिया ने उन्हें आईना दिखाते हुए कहा कि माफ करिए मंत्रीजी... यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिए आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। दरअसल, मंत्रीजी जिस विभाग के मुखिया हैं उस विभाग का काम प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। नियमानुसार कनिष्ठ अधिकारियों का तबादला विभाग के मुखिया अपने अनुसार कर सकते हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरस्वती की कृपा पात्र मंत्रीजी इन दिनों लक्ष्मी पूजा में लगे हुए हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि बिना लक्ष्मी दान दिए कोई भी इधर से उधर न हो। ऐसे में वे हर मामले में हस्तक्षेप करने के आदी हो गए हैं। लेकिन गत दिनों विभाग के मुखिया ने उन्हें उनकी हद बता दी।

चिंदी चोरी में जुटे साहब

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में एक प्रमोटी आईएएस अधिकारी की करतूतें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल, इन साहब को रिटायरमेंट के दो माह रह गए हैं। माना जा रहा है कि साहब पर मुख्यमंत्री का वरदहस्त है। शायद यही वजह है कि मामा की लाडलियों का पोषण करने वाले विभाग में भी साहब चिंदी चोरी में जुट गए हैं। दरअसल, पिछले दिनों साहब ने विभाग के जिला अधिकारियों से 30-30 हजार के दो मोबाइल मंगा लिए। साहब ने अधिकारियों से मोबाइल तो मंगा लिया, लेकिन अधिकारी उलझ गए हैं कि वे इसकी भरपाई कैसे करेंगे। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो मुख्यमंत्री का विभाग होने के कारण उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उधर, साहब हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे। विभागीय सूत्रों का कहना है कि साहब हर चीज में कमीशन खोज रहे हैं। गौरतलब है कि इस विभाग में फर्जी बिल का मामला पहले ही दर्ज हो चुका है और ईओडब्ल्यू में जांच चल रही है। उसके बावजूद साहब कमाई का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। साहब की हरकतों को देखकर लोग हैरान-परेशान हैं। उनका कहना है कि अंतिम समय में इस तरह की हरकत कहीं साहब पर भारी न पड़ जाए। उधर, साहब हैं कि रिटायरमेंट के अंतिम दिनों में भी कमाई से मुंह नहीं मोड़ रहे हैं।



दो महिला अधिकारियों में अब नूरा-कुशती

प्रदेश के एक आदिवासी बहुल जिले में इन दिनों पुलिस विभाग की दो अधिकारियों के बीच चल रही नूरा कुशती चर्चा का विषय बनी हुई है। आलम यह है कि जिले से बाहर निकलकर दोनों की लड़ाई राजधानी में चर्चा का विषय बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों पुलिस अधिकारी राज्य पुलिस सेवा में एक ही बैच की थीं। लेकिन इनमें से एक 2011 में आईपीएस बन गई। सूत्र बताते हैं कि तभी से इनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। इत्तेफाक ये रहा कि अब दोनों एक ही जिले में पदस्थ हैं। एक जिले की पुलिस कप्तान हैं तो दूसरी एडिशनल एसपी। अब दोनों खुलकर लड़ रही हैं। आलम यह है कि बड़ी साहिबा ने अपनी पूर्व बैचमेट डीएसपी के खिलाफ पूरी तरह मोर्चा खोल लिया है और उनकी लंबी-चौड़ी शिकायत कर दी है। लेकिन लोगों को अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इन दोनों महिला पुलिस अधिकारियों के बीच ऐसी क्या बात हो गई है कि इनमें नूरा-कुशती शुरू हो गई है। बता दें कि बड़ी साहिबा प्रदेश के एक पूर्व आईपीएस और पूर्व सांसद की सुपुत्री हैं। यही नहीं उन्हें अभिनय का भी शौक है और उन्होंने कुछ फिल्मों में हाथ भी आजमाया है। वैसे तो कहा जाता है कि मैडम काफी मिलनसार हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपनी पूर्व बैचमेट डीएसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है उससे लोग इसकी वजह जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं।

मैं तो विभाग का...

प्रदेश के एक बड़े और कमाऊ विभाग के मंत्री अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। मंत्रीजी के पास जो विभाग है, उसे काली कमाई का समंदर कहा जाता है। मंत्रीजी इस समंदर में गोते लगा रहे हैं या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन विभाग का मंत्री होने के कारण उनके दामन पर दाग जरूर लग रहे हैं। प्रदेश में जब भी कोई दुखद घटनाक्रम होता है, मंत्रीजी उसके दाग से बच नहीं पाते हैं। जब इस संदर्भ में मंत्रीजी से पूछा जाता है कि आखिर आपका विभाग कर क्या रहा है तो वे कहते हैं कि मैं तो विभाग का मोहरा भर हूँ। वे इशारों-इशारों में यह कहने से भी नहीं चूकते हैं कि खाता न बही, चौथी मंजिल कहे वही सही। यानी मंत्रीजी के पास बड़े विभाग की कमान होने के बाद भी वे असहाय हैं। विभाग में उनकी तनिक भी नहीं चल रही है। विभाग का नीति निर्धारण चौथी मंजिल से हो रहा है। इन सबके बावजूद मंत्रीजी को इस बात का संतोष है कि चलो कैबिनेट मंत्री का दर्जा तो मिला है, उसके अनुसार सुविधाएं तो मिली हैं। मंत्रीजी की ये बेचारीगी इन दिनों प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का विषय बनी हुई है।

भतीजे के ओहदे से खफा

राजनीति का रंग ही कुछ ऐसा है कि नेता अपने से आगे निकलता किसी को नहीं देखना चाहते हैं। चाहे वह अपना ही खून क्यों न हो। प्रदेश में ऐसी ही स्थिति से इन दिनों एक वरिष्ठ महिला मंत्री गुजर रही हैं। अपनी कड़क छवि के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाली मंत्री इन दिनों पार्टी में अपने भतीजे के बढ़ते ओहदे से खफा हैं। दरअसल, विरोधी पार्टी से उनकी पार्टी में आए भतीजे को इन दिनों सत्ता और संगठन में हाथों हाथ लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भतीजे को जहां बड़े विभाग का मंत्री पद मिला है, वहीं राज्य में भी भतीजे की खूब चल रही है। उधर, महिला मंत्री की स्थिति यह है कि कैबिनेट बैठकों में उनके व्यवहार का विरोध होने लगा है। इसलिए वे पिछली कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुईं। दरअसल, मैडम की आदत है कि वे सामने वाले को हर बात में टोकती रहती हैं। उनकी इस टोका-टाकी की आदत का विरोध भी होने लगा है। ऐसे में लोगों का मानना है कि मैडम को यह लगने लगा है कि भतीजे के कारण कहीं पार्टी में उनके प्रभाव को सीमित तो नहीं किया जा रहा है।



मैं जब-जब मुख्यमंत्री रहा हूँ, तब-तब मुझे अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा है। लेकिन मैं किसी भी परीक्षा से तनिक भी घबराया नहीं हूँ। पार्टी के लिए मैं ऐसी कई परीक्षाएँ देने को तैयार हूँ। आलाकमान ने जो फैसला किया है, वह मुझे स्वीकार है।

● बीएस चेदियुरप्पा



मेरा इरादा प्रधानमंत्री बनने का नहीं है। मेरा मिशन दिल्ली का एक ही मकसद है कि 2024 में भाजपा को सत्ता से हटाना। इसके लिए मैं पूरे विपक्ष को एकजुट करने के अभियान में जुटी हुई हूँ। 'नो वोट टू बीजेपी' नारे के साथ मैं मैदान में उतरी हूँ। भाजपा के कुशासन से देश में महंगाई और गरीबी बढ़ी है। केंद्र सरकार महामारी रोकने में विफल रही है।

● ममता बनर्जी



राजनीति और क्रिकेट में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों जगह विपक्षी निशाने पर होते हैं और सबको अपनी परफॉर्मेंस की चिंता रहती है। पंजाब में नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही मेरा फोकस पूरी तरह जनता का हित है। इसके लिए मैं अपनी ही सरकार से भिड़ सकता हूँ। मैं जब तक राजनीति में रहूँगा, जनता के लिए ही काम करूँगा।

● नवजोत सिंह सिद्धू



कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी रहेगा। किसान अब दिल्ली ही नहीं हर चुनावी राज्य में भाजपा के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। दिल्ली की तरह लखनऊ, उत्तराखंड और पंजाब भी जाएंगे। जरूरत पड़ी तो घेराव भी किया जाएगा।

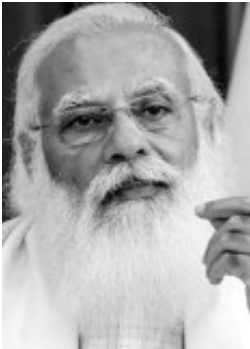
● राकेश टिकैत



मेरी फिल्म शेरशाह 12 अगस्त को अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी। उससे पहले ही फिल्म की चर्चा सुखद अनुभव है। दरअसल, इस फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा की गर्लफ्रेंड डिंपल चीमा का किरदार निभा रही हूँ। डिंपल का रोल करते हुए नायिकाओं के आत्मविश्वास, ताकत और बलिदान का मुझे अहसास हुआ है। मैं उन नायकों की कहानी की सराहना करती हूँ, जिन्हें हम जानते हैं और उन नायकों की कहानी को जो समर्थन देकर सबसे मजबूत स्तंभ साबित होते हैं। डिंपल मेरी तरह ही नायक हैं, उनकी कहानी की प्रशंसा करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह फिल्म दर्शकों को खूब भाएगी।

● कियारा आडवाणी

वाक्युद्ध



संसद में महत्वपूर्ण कार्य होने है, लेकिन कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। इनके ऐसे व्यवहार को मीडिया के सामने बेनकाब करें। जनता को भी यह बताना जरूरी है कि किस तरह विपक्षी पार्टियाँ संसद का बहुमूल्य समय बर्बाद कर रही हैं। विपक्ष पूरी तरह मनमानी कर रहा है।

● नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री जी को यह भी मालूम है कि विपक्ष सदन में हंगामा क्यों कर रहा है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सदन में आकर विपक्ष के सवालियों का जवाब दें। तब पता लगेगा कि सदन में हंगामे की असली वजह क्या है। देश को रसातल में पहुंचाकर आज मोदीजी अपने आप को जनता का शुभचिंतक किस मुंह से बता रहे हैं।

● राहुल गांधी



4 दिनी मानसून सत्र के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। सत्तापक्ष जहां महत्वपूर्ण बिलों और विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में लगा हुआ है, वहीं विपक्ष सत्तापक्ष को घेरने की। विधानसभा के मानसून सत्र में हर दिन विधायक औसतन 300 सवाल पूछेंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस चार दिनी सत्र के लिए कुल 1184 सवाल विधानसभा सचिवालय को मिले हैं। इनके जवाब तैयार करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने संबंधित विभागों को सवाल भेज दिए हैं। विधायकों को ज्यादातर सवालों के लिखित जवाब दिए जाएंगे। प्रश्नकाल में सिर्फ 25 सवालों पर ही चर्चा होगी।

इस मानसून सत्र में कोरोनाकाल के दौरान सरकारी विफलता, लोगों की असमय मौत, ऑक्सीजन की कमी और दवाईयों, इंजेक्शनों के टोटे से जुड़े सवाल भी विधायकों ने बड़ी संख्या में पूछे हैं। वहीं सरकार पहले ही इंकार कर चुकी है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। सरकार इंजेक्शन और दवाओं का टोटा होने से भी इंकार करती रही है। ऐसे में यह सत्र हंगामा खेज होने के आसार हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन में सरकार की घेराबंदी की पूरी तैयारी की है। इसके अलावा किसान कर्ज माफी, किसान आत्महत्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अवैध उत्खनन सहित अन्य मामलों से जुड़े मामलों पर भी शामिल हैं।

विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने के पहले विधानसभा ने विधायकों को उनकी सीमाएं बताई हैं। विधायकों से कहा गया है कि एक दिन में उनकी एक ही स्थगन सूचना स्वीकार की जाएगी। इसी प्रकार ध्यानाकर्षण भी दो से ज्यादा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए विधायक इससे ज्यादा सूचनाएं न दें। विधायकों को भेजे गए परिपत्र में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही कहा गया है कि मानसून सत्र के लिए स्थगन



हंगामेदार होगा मानसून सत्र

मग्न विधानसभा का मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होगा। सत्र वैसे तो मात्र 4 दिन का है, यानी 12 अगस्त तक चलेगा, लेकिन इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिलों को मंजूरी दी जाएगी। वहीं कांग्रेस ने उपचुनावों और नगरीय निकाय चुनाव से पहले आयोजित होने वाले इस विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे एक बात तो साफ है कि 4 दिवसीय यह सत्र हंगामेदार होगा।

प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण एवं शून्यकाल की सूचनाएं 4 अगस्त से स्वीकार की जाएंगी। प्रथम बैठक के लिए 4 अगस्त से 7 अगस्त तक सूचनाएं ली जाएंगी। इसके बाद अन्य दिनों के लिए सूचनाएं स्वीकार होंगी। सूचनाओं के लिए विधायक यदि अपना अधिकृत व्यक्ति भेजते हैं तो उसे मुख्य द्वार पर टोकन प्राप्त करना होगा। उसका क्रम आने पर उसे सचिवालय में प्रवेश मिलेगा। वहीं विधायकों से कहा गया है कि एक बैठक के लिए एक से अधिक स्थगन प्रस्ताव नहीं लिए जाएंगे। यदि विधायक एक साथ एक से अधिक सूचनाएं देना चाहते हैं तो उन्हें तिथि बताना होगी कौन सी सूचना किस दिनांक के लिए है। इसी प्रकार की व्यवस्था ध्यानाकर्षण के लिए की गई है। सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी

ध्यानाकर्षण में एक से अधिक विधायक के हस्ताक्षर होंगे तो यह माना जाएगा कि जिस विधायक ने पहले साइन किए हैं, यह सूचना उसी के द्वारा दी गई है।

विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का फोकस सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर अधिक से अधिक विधायकों के चर्चा में शामिल होने को लेकर है। प्रश्नकाल में भी ज्यादा से ज्यादा सवालों पर सरकार से जवाब लिए जाने का प्रयास होगा। पिछले सत्र में नए विधायकों को मौका दिया गया था, इस बार भी नवाचार की संभावना है।

4 दिवसीय सत्र में विधायक अपने क्षेत्र और विभागों से संबंधित सवाल लगा रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि विभागों की माननीयों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने में रूचि नहीं रही है। इस कारण विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों का अंबार लगा हुआ है। विधायकों द्वारा सदन में पूछे गए 565 सवालों के जवाब विभागों के अफसरों ने अभी तक नहीं दिए हैं। सबसे ज्यादा लेटलतीफ कृषि विभाग है। यहां के 106 सवालों के जवाब अभी तक नहीं आए हैं और कृषि मंत्री के 73 आश्वासन भी पूरे नहीं हो पाए हैं। वहीं सदन के भीतर विधायकों के सवालों पर जवाब देते हुए मंत्रियों ने 572 आश्वासन दिए लेकिन विभागों के अफसरों ने इन आश्वासनों को पूरा करने में रूचि नहीं दिखाई। अब तक मंत्रियों के ये आश्वासन पूरे नहीं हो पाए हैं।

आमतौर पर सदन के भीतर ध्यानाकर्षण सूचना, शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान विधायक अपने क्षेत्र और समूचे प्रदेश से जुड़ी समस्याओं को सदन में उठाते हैं। सवाल-जवाब के दौरान मंत्री इस पर जवाब देते हैं। कई बार मामले ऐसे फंस जाते हैं कि मंत्रियों को सदन के भीतर उन समस्याओं का निराकरण करने, अनियमितता पर कार्यवाही करने, सुविधाएं शुरू करने को लेकर आश्वासन देना पड़ता है। मंत्रियों के द्वारा सदन के भीतर दिए गए ये आश्वासन कई बार व्यावहारिक रूप में पूरे होने मुश्किल होते हैं।

● सुनील सिंह

समय पर सवालों के जवाब ही नहीं देते विभाग

प्रदेश के 37 विभागों के अफसर काफी लेटलतीफ हैं। यहां के 565 सवालों के जवाब अफसरों ने अब तक विधानसभा सचिवालय को नहीं दिए हैं। समय पर जवाब नहीं आने के कारण सदन के भीतर सरकार की किरकिरी होती है। जवाब देने में सबसे अधिक सुस्ती कृषि विभाग की ही सामने आई है। यहां 108 सवालों के जवाब अब तक नहीं दिए हैं। खाद्य विभाग के 83 सवालों के जवाब नहीं आए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 38 सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने 78 और गृह विभाग ने 57 सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। लेखा समिति की 149 सिफारिशों पर विभागों ने कोई कार्यवाही नहीं की है। शून्यकाल की 65 सूचनाओं पर कोई जवाब विभागों ने नहीं दिया है।

हम दो...हमारे चाहे जितने...!

6 उप्र में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा आते ही पड़ोसी राज्य मप्र में शिवराज सरकार के कई मंत्री और विधायक इसकी वकालत करने लगे हैं। विपक्ष कह रहा है भाजपा आबादी पर काबू पाने के नाम पर सियासत कर रही है। अगर दो बच्चों का कानून आज की तारीख में मप्र में लागू हो जाए तो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष कई नेताओं को घर पर बैठना पड़ जाएगा। अगर फौरन अमल के साथ ऐसा कानून बनता है तो मप्र में 227 विधायकों में भाजपा के 39 प्रतिशत विधायक और 38 प्रतिशत मंत्री अयोग्य हो जाएंगे।



3 उप्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून की कवायद के बीच मप्र में भी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कानून बनाने की पैरवी करके नई बहस छेड़ दी है। इस बीच प्रदेश के सभी मौजूदा 227 विधायकों की स्थिति का आंकलन किया गया तो यह तथ्य सामने आया कि अगर दो बच्चे का कानून चुनाव लड़ने के लिए भी लागू हुआ तो मप्र के 82 विधायक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इनमें 13 मंत्री भी शामिल हैं।

गौरतलब है कि उप्र सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कवायद के बाद मप्र की राजनीति भी गर्मा गई है। राज्य में सत्तापक्ष विधायक रामेश्वर शर्मा ने मप्र में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की वकालत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को इसके लिए एक पत्र लिखा है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने भी इसकी वकालत की है। जबकि विधानसभा में मौजूदा समय में भाजपा के जो 125 विधायक हैं, उनमें से 49 ऐसे हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। अगर मप्र में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दिया जाता है तो इन माननीयों का क्या होगा?

एक तरफ भाजपा के कुछ नेता

और सुरेश धाकड़ के 4-4, भूपेंद्र सिंह के 5 बच्चे हैं। यानी हम दो... हमारे चाहे जितने। ऐसे में ये मंत्री दूसरों को जनसंख्या नियंत्रण की सलाह कैसे दे सकते हैं।

जिस शिवराज सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने और लागू करने की मांग की जा रही है, उसके 125 विधायकों में से 49 विधायकों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं। वहीं भाजपा के 30 विधायकों के 3-3 बच्चे हैं। जबकि 8 विधायकों के 4-4 और 5 विधायकों के 5-5 बच्चे हैं। वहीं 4 विधायकों के 6-6 बच्चे हैं।

जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग करने वाली पार्टी के 2 विधायक ऐसे हैं जिनके 8 और 9 बच्चे हैं। इनमें से एक हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल, जिनके 8 बच्चे हैं और दूसरे हैं सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य जिनके 9 बच्चे हैं। विधायकजी कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, लेकिन भाजपा विधायक का निशाना कहीं और होता है। वो कहते हैं हमारा नारा था हम 2 हमारे 2। क्या ये संभव हुआ। हिंदुओं को कह देंगे नसबंदी करा दो, दूसरे भाइयों को कहेंगे फ्री हो जाओ।

प्रदेश में 2 से अधिक बच्चे वाले विधायकों के मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। वर्तमान समय में कांग्रेस के 95 विधायक हैं, इनमें से 33 विधायकों के 2 से अधिक बच्चे हैं। 16 कांग्रेसी विधायकों के 3-3 बच्चे हैं, वहीं 12 विधायकों के 4-4 बच्चे हैं। वहीं प्रागिलाल, हुकुम सिंह कराड़ा और बापूसिंह तंवर के 5-5 बच्चे हैं, जबकि देवेन्द्र सिंह पटेल के 6 बच्चे हैं।

प्रदेश की 230 सीटों वाली विधानसभा में वर्तमान में जो 227 विधायक हैं, उनमें से 2 विधायकों यानी भाजपा के राम लल्लू वैश्य और कांग्रेस के वालसिंह मेड़ा के 9-9 बच्चे हैं। मेड़ा झाबुआ जिले के पेटलावद से विधायक हैं।

मप्र में पिछले 10 सालों के बीच लगभग सवा करोड़ जनसंख्या वृद्धि हुई है। यदि इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो अगले 5 सालों में ही प्रदेश की जनसंख्या 10 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। वर्तमान में मप्र की जनसंख्या 8 करोड़ 45 लाख हो चुकी है। 100 साल पहले 1921 में भोपाल

13 मंत्रियों के 2 से अधिक बच्चे

● नरोत्तम मिश्रा	3
● सुरेश धाकड़	4
● यशोधरा राजे	3
● बृजेन्द्र सिंह यादव	3
● भूपेंद्र सिंह	5
● गोविंद सिंह राजपूत	3
● गोपाल भार्गव	4
● रामखिलावन पटेल	3
● बिसाहूलाल सिंह	6
● डॉ. मोहन यादव	3
● डॉ. प्रभुराम चौधरी	3
● कमल पटेल	3
● प्रेम सिंह पटेल	6

प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में शामिल 31 विधायकों में से 13 के 2 से अधिक बच्चे हैं। इनमें से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह और पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निशक्त जनकल्याण मंत्री प्रेमसिंह पटेल के 6-6 बच्चे हैं। मंत्रिमंडल में शामिल नरोत्तम मिश्रा सहित 8 मंत्रियों के 3-3 बच्चे हैं। वहीं गोपाल भार्गव



की आबादी 1.40 लाख थी। अब 2021 में 21 लाख आबादी पहुंच गई है। जनसंख्या के मामले में देश में छठवें स्थान पर मप्र है। थाईलैंड, फ्रांस, इटली और दक्षिण अफ्रीका से भी ज्यादा प्रदेश की आबादी हैं।

गौरतलब है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने दिग्विजय सिंह सरकार ने भी 2000 में सरकारी सेवाओं और पंचायती राज चुनावों में दो बच्चों का नियम बनाया था। पहले हाईकोर्ट में इसे चुनौती मिली, बाद में 2005 में भाजपा ने इसे वापस ले लिया था। कांग्रेस पूछ रही है कि अब भाजपा किस मुंह से जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण आज की जरूरत है, लेकिन इसकी नीयत राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। मप्र में पंचायत चुनाव में दो बच्चों का कांग्रेस ने निर्णय लिया था लेकिन भाजपा ने उसे समाप्त कर दिया। जब इंदिराजी ने प्रयास किया तो आरएसएस और अटलजी विरोध में थे। जनगणना के मुताबिक मप्र की जनसंख्या 7.27 करोड़ है जिसकी विकास दर 20 फीसदी से ज्यादा है।

उप्र सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कवायद के बाद मप्र की राजनीति भी गर्मा गई है। राज्य में सत्तापक्ष विधायक रामेश्वर शर्मा ने मप्र में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की वकालत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को इसके लिए एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि 10 सालों में लगभग डेढ़ करोड़ से अधिक जनसंख्या बढ़ोतरी हुई है और जो पश्चिमी देशों से अधिक है।

उन्होंने शिवराज चौहान को लिखे पत्र में कहा कि मप्र में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की जरूरत है। बढ़ती जनसंख्या से विकास, सुशासन और सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। मप्र में एक दशक पहले 7.25 करोड़ की आबादी थी, जबकि 2021 में प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या लगभग 8 करोड़ 75 लाख है।

विधायक ने तो निशाना साधा मगर हिंदुस्तान की आबादी पर काबू पाने के लिये मप्र के पंचायत मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने तो विवादित बयान दे दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी सिसोदिया ने तो यहां तक कह दिया कि मुसलमानों में दो-तीन शादियां होती हैं और वो दस-दस बच्चे पैदा कर लेते हैं, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन समान नागरिक संहिता कानून लागू होना चाहिए जिसमें हर जाति के व्यक्ति के लिए बच्चे पैदा करने की संख्या भी सुनिश्चित होनी चाहिए। मुस्लिमों में ये सुनिश्चित नहीं है। उधर, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जनसंख्या नियंत्रण कानून के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वे कहते हैं कि भाजपा एक वर्ग पर दबाव बनाने के लिए इस कानून की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस के कई अन्य नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ऐसा कानून लागू होना चाहिए।

● कुमार राजेन्द्र

कांग्रेस के इन विधायकों के 2 से अधिक बच्चे

कांग्रेस के बाबू जंडेल के 3 बच्चे हैं, वहीं अजबसिंह कुशवाह के 4, गोविंद सिंह के 3, लाखनसिंह यादव के 3, प्रागीलाल के 5, निरज दीक्षित के 3, आलोक चतुर्वेदी के 3, शिवदयाल बागरी के 3, सुनील शराब के 3, विनय सक्सेना के 3, तरुण भनोट के 4, मुरली मोरवाल के 3, रामलाल मालवीय के 4, महेश परमार के 4, दिलीप सिंह गुर्जर के 3, जीतू पटवारी के 3, पांचीलाल मेड़ा के 3, वालसिंह मेड़ा के 9, वीरसिंह भूरिया के 4, ग्यारसी लाल रावत के 3, सज्जन सिंह वर्मा के 4, हुकुम सिंह कराड़ा के 5, बापूसिंह तंवर के 5, आरिफ मसूद के 4, आरिफ अकील के 4, देवेंद्र सिंह पटेल के 6, धरमसिंग सिरसाम के 4, ब्रह्मा भलावी के 4, सोहनलाल वाल्मीकि के 3, संजय शर्मा के 4, अर्जुन सिंह काकोड़िया के 3, टामलाल रघुजी सहारे के 4, नारायण सिंह पट्टा के 3 बच्चे हैं।

भाजपा के इन विधायकों के 2 से अधिक बच्चे

● सीताराम आदिवासी	4
● सूबेदार सिंह सिकरवार	3
● सुरेश राजे	3
● रक्षा सरोलिया	3
● नरोत्तम मिश्रा	3
● सुरेश धाकड़	4
● यशोधरा राजे	3
● गोपीलाल जाटव	4
● बृजेंद्र सिंह यादव	3
● महेश राय	3
● भूपेंद्र सिंह	5
● गोविंद सिंह राजपूत	3
● हरिशंकर खटीक	4
● गोपाल भार्गव	4
● पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय	3
● प्रहलाद लोधी	3
● नारायण त्रिपाठी	5
● रामखिलावन पटेल	3
● प्रदीप पटेल	3
● गिरीश गौतम	3
● पंचूलाल प्रजापति	6
● राजेंद्र शुक्ल	3
● केदारनाथ शुक्ल	8
● अमरसिंह	3
● राम लल्लू वैश्य	9
● कुंवर टेकराम सिंह	4
● बिसाहूलाल सिंह	6
● शिवनारायण सिंह	3
● अजय विश्‍नोई	3
● अशोक रोहाणी	3
● देवीलाल धाकड़	4
● डॉ. राजेंद्र पाडेय	3
● डॉ. मोहन यादव	3
● बहादुर सिंह चौहान	3
● मालिनी गौड़	3
● नीना विक्रम वर्मा	3
● प्रेम सिंह पटेल	6
● पहाड़सिंह कौजे	3
● कुंवरजी कोठार	3
● करण सिंह वर्मा	4
● रघुनाथ सिंह मालवीय	5
● विष्णु खत्री	3
● हरीसिंह सप्रे	5
● लीना संजय जैन	3
● रामपाल सिंह	6
● डॉ. प्रभुराम चौधरी	3
● प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा	5
● कमल पटेल	3
● देवसिंह सैयाम	3

बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार की कोशिश है कि इस साल के अंत तक निविदा की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि भोपाल, इंदौर मेट्रो रेल का सपना जल्द साकार हो सके।

मेट्रो ट्रैक का निर्माण अब पकड़ेगा रफ्तार

म प्र सरकार की कोशिश है कि वर्ष 2025 तक राजधानी भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल पर सफर करने का सपना साकार हो जाए। राजधानी में मेट्रो रेल परियोजना का काम तेजी से हो रहा है। मेट्रो के एलिवेटेड रूट, डिपो के लिए जमीन के बाद अब मेट्रो स्टेशनों का मामला भी सुलझ गया है। मेट्रो के लिए 369 करोड़ रुपए से 8 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके डिजाइन और निर्माण कार्य के लिए निविदा जारी हो गई है। 25 सितंबर तक इसके आदेश जारी हो सकते हैं। मेट्रो के डिजाइन और निर्माण के लिए ईआईबी ने यह अनुमानित राशि बताई है। इधर, जिला प्रशासन से मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए जमीन आवंटन करने के प्रस्ताव बनाकर भेज दिए गए हैं। जल्द ही स्टेशन के लिए जमीन भी आवंटित कर दी जाएगी। इधर, मेट्रो के लिए डिपो बनाने के लिए भी काम तेजी से चल रहा है।

एलिवेटेड स्टेशनों का निर्माण नवंबर में शुरू होने की संभावना है। इसमें सवा दो साल का समय लग सकता है। एम्स से सुभाष नगर फाटक के बीच के हिस्से में स्टेशन बनाए जाएंगे। मप्र मेट्रो रेल कंपनी ने स्टेशन के लिए निर्माण एजेंसी का चयन करने मार्च में टेंडर जारी किए थे। अधिकारी अक्टूबर में एजेंसी फाइनल होने की बात कह रहे हैं। चयनित कंपनी स्टेशन का डिजाइन भी बनाएगी। ये स्टेशन एम्स, अलकापुरी, हबीबगंज नाका, हबीबगंज, एमपी नगर जोन 1, डीबी मॉल, केंद्रीय विद्यालय और सुभाष नगर में बनेंगे।

मेट्रो का डिपो में काम तेजी से चल सके, इसके लिए बिजली कंपनी से 132 केवी की हाईटेंशन लाइन बिछाई जाएगी। मप्र की मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के लिए मेट्रो रेल डिपो की पाँवर कनेक्टिविटी के लिए 39.57 करोड़ रुपए की लागत से जमीन के अंदर से खोदकर डिपो तक पहुंचाया जाएगा। चंबल से मेट्रो रेलवे सर्विस स्टेशन सुभाष नगर तक अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि डिपो में इतनी बिजली लगेगी, जिससे करीब दो लाख घर रोशन हो सकते हैं। बिजली कंपनी के मुताबिक शुरुआती दौर में मेट्रो सिर्फ



15 अगस्त के बाद इंदौर मेट्रो के काम तीव्र गति से शुरू होंगे

नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इंदौर मेट्रो के सभी आवश्यक कामों के टेंडर कर दिए गए हैं और 15 अगस्त के बाद सभी काम शुरू किए जाएंगे। स्टेशन, अंडरग्राउंड स्टेशन, एलिवेटेड स्टेशन, डिपो, विद्युत लाइन ट्रांसमिशन, और कनेक्टिविटी स्टेशन की ड्राइंग और निर्माण के लिए टेंडर कर अनुबंध किया जा रहा है। मेट्रो के प्रथम चरण में 3.1 किलोमीटर लंबाई की मेट्रो ट्रैक निर्माणाधीन है। जिसमें 2.4 किलोमीटर से अधिक लंबाई में एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक और 7.48 किलोमीटर लंबाई का अंडरग्राउंड रेलवे मेट्रो ट्रैक बनाया जाना है जिसकी लागत 7500 करोड़ की है। जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 50:50 के अनुपात में वित्तीय भार आना है। लगभग 440 करोड़ के काम पीपीपी मोड पर किए जाना प्रस्तावित है।

7-8 किमी लंबे रूट पर भी सफर तय करती हो तो भी प्रतिमाह 4 से 5 करोड़ रुपए की बिजली की खपत होगी। यानी भोपाल मेट्रो शुरुआत से ही सालाना करीब 50 करोड़ रुपए की बिजली पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से खरीदेगी। बिजली की यह खपत और राजस्व का आंकड़ा एक छोटे जोन के बराबर है।

भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट में एम्स टू करोंड रूट पर 180 से ज्यादा पिलर खड़े करने और गर्डर लांचिंग के बीच अब मेट्रो डिपो बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। डिपो सुभाष नगर रेलवे फाटक, इनकम टैक्स ऑफिस के पीछे व आसपास करीब 80 एकड़ जमीन पर बनेगा। यहीं से कोच मॉटेन्स से लेकर चलने तक का मैनेजमेंट

होगा। यहां एक समय में 4 मेट्रो ट्रेन खड़ी की जा सकेंगी।

भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला रूट 16.05 किमी लंबा है। यह एम्स टू करोंड तक जाता है। फिलहाल रूट निर्माण हो रहा है। अब तक एम्स, होशंगाबाद रोड, सुभाष नगर, एमपी नगर जैसे क्षेत्र में पिलर खड़े किए गए हैं। करीब 8 किमी हिस्से में काम हो रहा है। हालांकि, अब असली चुनौती सुभाष नगर रेलवे फाटक से करोंड के बीच है, क्योंकि यहां से मेट्रो अंडरग्राउंड गुजरेगी। इन सभी कामों में 4 साल और लग जाएंगे और मेट्रो 2025 तक ही दौड़ पाएगी।

रोहित गुप्ता एंड एसोसिएट्स ने भोपाल व इंदौर की मेट्रो की डीपीआर बनाई है। राजधानी की योजना में हबीबगंज स्टेशन के नीचे ही मेट्रो के लिए स्टेशन बनाने का प्लान दिया था। इसे बदलना पड़ा। कारण यह रहा कि करीब 100 करोड़ रुपए खर्च कर हबीबगंज स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का काम किया गया है। ऐसे में वहां मेट्रो का स्टेशन बनाना संभव नहीं था। अब यह स्टेशन के बाहर बनाया जाएगा। आधे रूट के लिए अब तक नहीं हुए टेंडरमेटो प्रोजेक्ट की शुरुआत करोंड से एम्स तक के पहले रूट से की गई है। फिलहाल करोंड से सुभाष नगर तक करीब सवा छह किमी लंबा एलिवेटेड रूट बनाया जा रहा है। इसका जिम्मा दिलीप बिल्डकॉन को सौंपा गया है। इसमें स्टेशन और डिपो शामिल नहीं हैं। इस पर 247.06 करोड़ खर्च होगा। कंपनी ने नवंबर, 2019 में कार्य शुरू किया था। फिलहाल इस रूट के लिए 150 से अधिक पिलर खड़े किए जा चुके हैं। गवर्नमेंट प्रेस चौराहा से सुभाष नगर के बीच गर्डर लांच किए जा चुके हैं। पहले रूट के बाकी हिस्से सुभाष नगर से करोंड के बीच रूट निर्माण के लिए अब तक टेंडर ही जारी नहीं हो पाए हैं।

● लोकेंद्र शर्मा

7 अगस्त को अन्न उत्सव के अवसर पर मद्र में 25 हजार राशन दुकानों से मुफ्त अनाज का वितरण शुरू होगा। सरकार की योजना है कि प्रदेश के 1 करोड़ 12 लाख हितग्राहियों को जूट के थैले में 10-10 किलो अनाज दिया जाएगा। लेकिन प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह इस जिद पर अड़े हैं कि हितग्राही परिवार में जितने सदस्य हैं, उतने थैले दिए जाएं। अगर सरकार मंत्री की मनमानी पूरी करने की कोशिश करेगी तो उस पर करोड़ों रुपए का भार पड़ेगा।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने गरीबों को हर माह 10 किलो अनाज देने का निर्णय लिया है।

इसकी शुरुआत 7 अगस्त को अन्न उत्सव से होगी। मद्र में उस दिन एक साथ 30 लाख परिवारों को मुफ्त अनाज बांटा जाएगा। 25 हजार से अधिक राशन दुकानों

से यह वितरण होगा। उसके बाद भी यह अभियान जारी रहेगा और मद्र में 1 करोड़ 11 लाख 32 हजार लोगों को 10-10 किलो अनाज दिया जाएगा। यह अनाज एक थैले में दिया जाएगा, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर रहेगी। इस दिन उचित मूल्य की दुकानों पर मंत्री, सांसद, विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। सभी दुकानों की रंगाई-पुताई और सफाई कराने को कहा गया है, लेकिन किसी प्रकार का बजट नहीं दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बैनर लगाने को भी कहा गया है।

मद्र सरकार की तैयारी है कि पात्र 1 करोड़ 12 लाख हितग्राहियों को थैले में 10-10 किलो अनाज दिया जाए। लेकिन प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह की मंशा है कि एक कार्ड में जितने सदस्य हैं, उतने थैले दिए जाएं। यानी मंत्री के अनुसार करीब 4 करोड़ 89 लाख 89 हजार 855 थैले वितरित किए जाएं। इसके पीछे मंत्री की मंशा क्या है यह तो पता नहीं लेकिन सरकार पर 5 गुना भार बढ़ना तय है। मद्र सरकार पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है। सरकार हर माह करीब 1 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। उस पर कोरोना संक्रमण के कारण राजस्व संग्रह कम हो रहा है। अगर ऐसे में सरकार मंत्री की बात मानती है तो उस पर और भार बढ़ेगा। सूत्रों का कहना है कि मंत्री की मंशा सरकार और भाजपा की ब्रांडिंग नहीं बल्कि कुछ और है।

दरअसल, केंद्र और राज्य सरकार की मंशा यह है कि कोरोना संक्रमण, महंगाई, आर्थिक मंदी के कारण भाजपा को जो क्षति हुई है, उसकी भरपाई की जाए। इस अभियान के साथ अब मोदी और शिवराज राशन दुकानों से बाटे जाने वाले थैले के माध्यम से घर-घर पहुंच बनाएंगे। यानी जब भी थैला थामने वाला घर की खूटी पर



मंत्री की मनमानी पड़ेगी भारी...

गरीबों का राशन खाने वाले को बना दिया खाद्य मंत्री

अन्न उत्सव पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस का कहना है कि जिस प्रदेश में गरीबों का राशन खाने वाला खाद्य मंत्री बना है, उस प्रदेश का भला कैसे होगा। कांग्रेस का आरोप है कि अनूपपुर के ग्राम परासी में मंत्री बिसाहूलाल सिंह और उनके परिवार का नाम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की सूची में है। वे इस आधार पर गरीबों के नाम पर मिलने वाला राशन भी लेते रहे हैं।



इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता भुवनेश्वर मिश्रा ने तमाम दस्तावेजों के साथ ईओडब्ल्यू को शिकायत भी की थी। भाजपा ने भी इस मामले को खूब उछाला था, लेकिन बाद में उपचुनाव जीतने के बाद उन्हें प्रदेश का खाद्य मंत्री बना दिया गया। अब एक बार फिर मंत्री थैले को लेकर चर्चा में हैं।

लटका थैला देखेगा या बाद में बाजार ले जाएगा तो प्रचार खुद ब खुद हो जाएगा।

मद्र सरकार हितग्राहियों को 10 किलो राशन थैलों में प्रदान करने जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के परिवार को प्रति व्यक्ति 5-5 किलो निशुल्क राशन और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 5-5 किलो राशन एक रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। इस मेगा उत्सव की तैयारी पूरी है। फिलहाल फाइनल टच देने में जुटे मुख्यमंत्री

मंत्री पुत्र जुटे उगाही में, सरकार की छवि धूमिल

बड़े मिया तो बड़े मिया, छोटे मिया सुभान अल्ला... की तर्ज पर प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह के सुपुत्र इन दिनों भाजपा की छवि तार-तार करने में जुटे हुए हैं। दरअसल, मंत्री पुत्र ने पिता के नाम पर उगाही शुरू कर दी है। सूत्र बताते हैं कि विभाग से जुड़े ठेकेदारों से माल कमाने के साथ ही अन्य विभागों से जुड़े कामों के लिए भी मंत्री पुत्र जुटे हुए हैं। बताया जाता है कि मंत्रीजी जिस जिले का दौरा करते हैं मंत्री पुत्र उनसे पहले वहां पहुंच जाते हैं और सांठगाठ में जुट जाते हैं। इससे मंत्री की छवि खराब हो रही है। यही नहीं मंत्रीजी ने एक चपरासी जो अब बाबू बन गए हैं को अपना निज सचिव बनाया है। वहीं वन मंत्री विजय शाह भांजी को अपना ओएसडी बनाया है। मंत्रीजी की इस जमावट को देखकर हर कोई हैरान है। लोग कहने लगे हैं कि ये वे बिसाहूलाल सिंह नहीं हैं, जो पहले हुआ करते थे।

शिवराज ने उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी शुरू कर दी हैं। उन्होंने रंगाई पुताई और सफाई कराने के निर्देश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बैनर लगाने को भी कह दिया गया है। अभी तक भले ही माप यंत्रों और तुलाई यंत्र की कोई चेकिंग नहीं हुई हो लेकिन अब निर्देश दिए गए हैं कि माप और तौल कांटो का प्रमाणीकरण किया जाए।

● धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया

प्रदेश में बिजली कंपनियों ने घाटे का तिलिस्म ऐसा रचा है कि इसे खत्म करने का हर प्रयास फेल साबित हो रहा है। 2003 में घाटे को खत्म करने के उद्देश्य से ही बिजली बोर्ड को भंग करके बिजली कंपनियों का गठन किया गया था, लेकिन बिजली कंपनियों ने घाटा कम करने की बजाय और बढ़ा दिया। औसतन हर साल तीन से चार हजार करोड़ घाटे का टैरिफ प्रस्ताव बिजली कंपनियां देती हैं। इस आमदनी और खर्च के बीच का घाटा सरकार की 21 हजार करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी और सालाना छह हजार करोड़ से ज्यादा के कर्ज के बावजूद खत्म नहीं होता। यहां तक की केंद्र सरकार की बिजली कंपनियों को आत्मनिर्भर करने की योजना में हजारों करोड़ लेने के बावजूद घाटे का गणित पूरा नहीं हुआ। इस दौरान एक बार फिर बिजली कंपनियों को भंग करके बिजली बोर्ड बनाने की मांग उठी है। इस बिंदु सहित बिजली की अन्य समस्याओं पर मंत्री समूह मंथन कर रहा है, लेकिन सरकार को फिलहाल बिजली के घाटे को खत्म करने की राह नजर नहीं आ रही है।

बिजली के घाटे को कम करने के जितने जतन और दावे किए गए, उतना ही घाटा बढ़ता गया। वर्ष-2000 में विद्युत मंडल के समय घाटा 2100 करोड़ और दीर्घकालीन कर्ज करीब 4892.6 करोड़ दर्ज था। वहीं 2014-15 में घाटा 30 हजार 282 करोड़ और दीर्घकालीन कर्ज बढ़कर 34 हजार 739 करोड़ पार हो गया। वहीं अब वर्ष-2020 की स्थिति में 40 हजार करोड़ से ज्यादा का कुल घाटा हो चुका है। बिजली कंपनियों ने अपने टू-अप प्लान में ही 26 हजार करोड़ से ज्यादा का घाटा बताया है।

बिजली कंपनियों के घाटे की भरपाई के चक्कर में सरकार अलग कर्जदार हो गई है। सरकार ही बिजली कंपनियों को 21 हजार करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देती है, जिसे कम करने के लिए अब उपाय खोजे जा रहे हैं। उस पर हद ये कि चार साल पूर्व सरकार बिजली कंपनियों का करीब 26 हजार करोड़ का घाटा केंद्र सरकार की योजना के तहत खुद पर ओढ़ चुकी है। इसके बावजूद हर साल औसतन 6 हजार करोड़ के कर्ज की गारंटी सरकार बिजली कंपनियों को देती है। इससे सरकार की माली हालत अलग खराब हो रही है।

घाटे के कारण ही बिजली बोर्ड को भंग करके बिजली कंपनियां बना दी गईं। इनमें तीन बिजली वितरण कंपनियां रखी गईं। विद्युत अधिनियम 2003 भी लागू किया गया। इसके तहत राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के लिए सालाना घाटे का पैमाना भी तय किया, लेकिन हर साल बिजली कंपनियां इससे पार चली जाती। लाइन लॉस से लेकर पीएलएफ तक के नुकसान के मापदंड आयोग ने तय किए,

बिजली कंपनियों के घाटे का तिलिस्म



हर बिजली उपभोक्ता 25 हजार के कर्ज में

मप्र में हर बिजली उपभोक्ता 25 हजार के कर्ज में है। यह हम बिजली कंपनियों के आंकड़े नहीं बता रहे हैं। 6 साल में प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों को कुल 36 हजार 812 करोड़ का घाटा हुआ है। प्रदेश में कृषि, घरेलू और व्यवसायिक उपभोक्ताओं की संख्या 1.50 करोड़ है। अब कंपनियों की ओर से पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली जलन कर इसकी भरपाई करने के लिए विद्युत वितरण आयोग के समक्ष सत्यापन याचिका दायर की है। जानकारी के अनुसार प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों को बीते वर्ष 2019-20 में 4752.48 करोड़ का घाटा हुआ है। कंपनियों ने विद्युत वितरण आयोग से अगले टैरिफ आदेश में उपभोक्ताओं से वसूलने की प्रतिबंध याचिका दायर की है। हैरानी की बात ये है कि जबलपुर में बिजली कंपनी का मुख्यालय है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बावजूद सबसे अधिक नुकसान हुआ है। बिजली मामलों के विशेषज्ञ राजेंद्र अग्रवाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर जांच कराने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में सूक्ष्म बिजली होने के बावजूद कंपनी को नुकसान होने के कारण से परे है। बिजली कंपनियों की चोरी रोकने और निपटान तरीके से नहीं कर पा रही है। इसका खामियाजा आम जनता को महंगी बिजली खरीदकर भुगतना पड़ रहा है।

किंतु कंपनियों ने हमेशा बैलेंस शीट में ज्यादा घाटा बताया। नुकसान काबू में नहीं करने के कारण बिजली कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नियामक आयोग उदार बना रहा। नियामक आयोग ने कई बार नुकसान को काबू न करने पर बिजली कंपनियों को फटकार लगाई, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं की।

बिजली कंपनियों को भंग करके वापस बिजली बोर्ड का गठन करने की मांग हाल ही में दो बार उठ चुकी है। 2019 में कमलनाथ सरकार के समय इसकी मांग उठी थी। तब, फ्रांस की कंपनी से समझौता करके बिजली व्यवस्था को रिफार्म करना तय किया गया था। इसके बाद फ्रांस की कंपनी ने बिजली के लिए अलग से एक मॉनीटरिंग बॉडी गठित करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई, तो यह मामला टंडे बस्ते में चला गया। हाल ही में वापस लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने ऊर्जा विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान बिजली कंपनियों को खत्म करके वापस बोर्ड गठित करने पर विचार करने का सुझाव दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों का समूह बनाकर बिजली व्यवस्था की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। यह समूह अभी बैठकों में उलझा है। जानकारों के मुताबिक बिजली के दाम बढ़ाने पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच की मांग भी की गई है। उनसे कहा गया है कि आखिर जब लगातार बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसके बाद भी क्यों कंपनियों को घाटा हो रहा है।

● राकेश ग्रोवर

म प्र देश में सबसे अधिक खनिज संपदा वाले राज्यों में से एक है। लेकिन यहां सरकार को उससे अधिक आय नहीं हो पाती है। जानकारों का कहना है कि प्रदेश में सरकार से अधिक तो माफिया खनिज संपदा से कमाई करते हैं। खासकर रेत का खेल तो निराला है। यहां वैध से अधिक अवैध रेत का खनन होता है। सरकार ने कई बार नीति बदली लेकिन स्थिति जस की तस है। उधर वित्त विभाग ने इस बार खनिज विभाग का राजस्व लक्ष्य बढ़ाकर 5600 करोड़ का कर दिया है। इस लक्ष्य को पूरा करने में विकास को पसीना आ रहा है। एक ओर कम आमदनी के चलते 4 जिलों में रेत ठेकेदारों ने ठेके समर्पित करने के आवेदन कर दिए हैं, वहीं 8 जिलों में कोरोना के कारण रेत खदानों के ठेके निरस्त हो चुके हैं। इसलिए प्रदेश के एक दर्जन जिलों में रेत खदानों के ठेके फिर से किए जाएंगे। अभी तक प्रदेश में रेत खदानों से सरकार को ज्यादा आय नहीं होती थी।

वर्ष 2019-20 में ही 250 करोड़ रुपए के ठेके हुए थे। इस बार रेत नीति में बदलाव किया गया और फिर जब ठेके हुए तो प्रदेश में इस बार रेत खदानों के ठेके 1100 करोड़ से अधिक में गए हैं। इस बार प्रदेश में खनिज विभाग को 5 हजार 600 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को पूरा करने में विभाग को दिक्कत आ रही है। एक तो कोरोना के चलते पहले ही राजस्व वसूली कम हो रही है उस पर रेत समूहों के ठेके ठेकेदार समर्पित कर रहे हैं। 4 जिलों पन्ना, भिंड, शाजापुर और रतलाम के ठेकेदारों ने कम आमदनी के अनुमान से अपनी रेत खदानें समर्पित कर दी हैं जबकि 8 जिलों में कोरोना के चलते खदानें शुरू ही नहीं हो पाईं। कोरोना के कारण 8 जिलों मंडसौर, अलीराजपुर, रायसेन, रीवा, शिवपुरी, राजगढ़, धार और छतरपुर में रेत का ठेका निरस्त हो चुका है। पन्ना, भिंड, शाजापुर और रतलाम के ठेकेदारों ने खदान सरेंडर करने का आवेदन दे दिया है। इन जिलों में नए सिरे से ठेके हो सकते हैं। अब खनिज विभाग यहां नए सिरे से रेत खदानों के ठेके देने फिर से टेंडर जारी करेगा।

बारिश में वैसे भी रेत खनन पर प्रतिबंध रहता है और ठेके की प्रक्रिया पूरी होने में भी एक से डेढ़ माह का समय लग जाता है। इस बीच सरकार खनन से राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करा रही है। इसके बाद फिर से नए सिरे से एक दर्जन स्थानों पर रेत खदानों के ठेके किए जाएंगे। ये ठेके जल्द ही होने की संभावना है।

मप्र में रेत कारोबारियों के साथ अब खनिज विभाग के जिलों में पदस्थ माइनिंग अफसर एग्रीमेंट करेंगे। इन्हीं अफसरों के पास अभी रेत के अवैध उत्खनन को रोकने और अवरोध के

मप्र खनिज और वन संपदा से परिपूर्ण राज्य है। लेकिन नीतिगत तरीके से खनिज का खनन नहीं होने के कारण राज्य को पर्याप्त राजस्व नहीं मिल पाता है। देर से ही सही सरकार एक बार फिर नई रणनीति के साथ खनिज से राजस्व प्राप्त करने की रणनीति पर काम कर रही है।



टारगेट पूरा करने का टशन

हर दिन दर्ज हो रहे अवैध खनिज परिवहन के 10 से अधिक मामले

प्रदेश में गुना, छिंदवाड़ा, जबलपुर, छतरपुर और मुरैना जिलों में 4 माह में अवैध परिवहन के सर्वाधिक केस दर्ज किए गए हैं। सीहोर और होशंगाबाद समेत नर्मदा नदी से सटे कई जिलों में इस तरह के मामले अपेक्षा के अनुरूप काफी कम हैं। अवैध परिवहन के 1200 केस खनिज विभाग ने दर्ज किए हैं। सरकार के रिकार्ड में पिछले चार माह में अवैध खनन और भंडारण के औसत 44 और 40 केस ही हर माह दर्ज हुए हैं। प्रदेश में खनिज के अवैध परिवहन के मामले 4 माह में सबसे अधिक सामने आए हैं। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 1199 केस दर्ज किए गए हैं। इसमें अप्रैल में 291, मई में 289, जून में 543 और जुलाई में 76 केस रजिस्टर हुए हैं। सबसे अधिक 64 मामले शहडोल जिले में कायम हुए हैं। इसके बाद सीहोर में 55, इंदौर में 53, बालाघाट में 47, रतलाम में 45, छिंदवाड़ा में 43, बड़वानी व बैतूल में 40-40 अवैध परिवहन करने के मामले दर्ज हुए हैं। खनिज विभाग के मुताबिक अप्रैल 21 से जुलाई में अब तक अवैध भंडारण के 162 केस 27 जिलों में दर्ज किए गए हैं। 25 जिलों में इसको लेकर कोई केस ही दर्ज नहीं हैं। सबसे अधिक 29 मामले गुना और 28 केस छिंदवाड़ा जिले में दर्ज किए गए हैं।

बिना उसके परिवहन का काम है। खनिज विभाग ने कैबिनेट सब कमेटी के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा है जिस पर फिलहाल सहमति नहीं बनी है। वर्तमान में खदानों की नीलामी के साथ रेत कारोबारियों से एग्रीमेंट खनिज निगम करता है।

रेत खदानों का ताजा ठेका करीब 1250 करोड़ रुपए में उठा है। इससे पहले जब जिलों की पंचायतों के अधिकार में ये खदानें थीं तो सिर्फ 250 करोड़ के करीब राजस्व सरकार को मिला था। प्रस्तावित नई व्यवस्था में तीन साल के लिए नीलामी तो खनिज निगम करेगा, लेकिन जिलों में अलग-अलग समूहों के साथ माइनिंग अधिकारी एग्रीमेंट करेंगे। कमेटी के सामने विभाग ने प्रस्ताव दिया है कि अभी रेत का ऑफसेट प्राइज 125 रुपए प्रति घनमीटर है। इसे बढ़ाकर 250 रुपए किया जा रहा है।

वैसे देखा जाए तो सरकार ने अब तक खनिज से राजस्व कमाने के जितने प्रयास किए हैं, सारे विफल रहे हैं। इसकी एक वजह यह है कि प्रदेश में रेत, बाक्साइट, चूना-पत्थर समेत अन्य खनिजों की अवैध खनन, भंडारण और परिवहन पर रोक लगाने में खनिज महकमा नाकाम साबित होता रहा है। इस विभाग को सुरक्षा के लिए होमगार्ड के जवान दिए जाने के गृह विभाग के आदेश के बाद भी अब तक इस पर अमल नहीं हो पाया है। उधर खनिज के अवैध कारोबार में लिप्त माफिया अपनी मनमानी पर उतारू है। इस कारण अवैध कारोबार के सभी मामले पकड़ में नहीं आते हैं और उन पर कार्यवाही नहीं हो पाती है।

● अरविंद नारद

‘ प्रदेश की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में टिकट के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों में दावेदार कतार में लग चुके हैं। फिलहाल दोनों पार्टियाँ सहानुभूति की लहर पर सवार होने की तैयारी कर रही हैं। यानी दिवंगत नेताओं के परिजनों पर दांव लगाने पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

इमोशनल कार्ड या सक्रियता पर दांव...?

मप्र में एक बार फिर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। प्रदेश में खंडवा लोकसभा और पृथ्वीपुर, जोबट तथा रैगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन चार सीटों में दो कांग्रेस की और दो भाजपा की सीट रहीं हैं। कांग्रेस कम से कम तीन सीट जीतकर लोहा मनवाना चाहती है। इन चारों सीटों पर कोरोना संक्रमण के कारण नेताओं की मौत हुई। अब दोनों ही सियासी दल सहानुभूति के वोट बटोरने के प्लान में जुटे हैं। दोनों तरफ से प्रबल दावेदारों के नाम सामने आए हैं। उससे साफ है कि उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सहानुभूति के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश में हैं।

चार सीटों के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो खंडवा लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा था। यहां से 2019 के चुनाव में नंदकुमार सिंह चौहान चुनाव जीते थे और अब भाजपा की कोशिश है कि उपचुनाव में नंदकुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन को टिकट दिया जाए। हालांकि यहां पर भाजपा में अर्चना चिटनिस और कृष्ण मुरारी मोघे भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। भाजपा यहां **कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है।** इसलिए संभावनाओं पर मंथन चल रहा है।

वही रैगांव विधानसभा सीट पर 2018 के चुनाव में जुगल किशोर बागड़ी ने चुनाव जीता था और भाजपा यहां पर बागड़ी के बड़े बेटे पुष्परज को टिकट देने की तैयारी में है। टिकटों को लेकर भाजपा में अभी मंथन का दौर जारी है। मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा हर बार सहानुभूति के सहारे चुनाव लड़ना सफल साबित नहीं होता है। अगर सीट इसका उदाहरण है। लेकिन फिर भी यह देखा जाता है कि चुनाव में सहानुभूति अपना असर दिखाती है। पार्टी सभी पहलुओं पर मंथन करने के बाद ही टिकट

अब कमलनाथ के गढ़ में संघ लगाने की तैयारी

मप्र के 29 लोकसभा क्षेत्रों में से छिंदवाड़ा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। नाथ के इस गढ़ को भेदने के लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है। सिंधिया लगभग 13 साल बाद 18 अगस्त को एक दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा जाएंगे। उनका आधिकारिक दौरा प्रदेश भाजपा की तरफ से जारी किया गया है। सिंधिया के छिंदवाड़ा जाने की खबर से राजनीतिक हलकों में सरगमी तेज हो गई है। दरअसल, मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस सरकार गिराने के बाद सिंधिया का यह पहला दौरा है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेसी सिंधिया के दौरे में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। मप्र में छिंदवाड़ा ही एकमात्र संसदीय जिला है जहां भाजपा सबसे कमजोर है। छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ सांसद हैं। वहीं जिले की सातों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। भाजपा की रणनीति है कि 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस को जोरदार टक्कर दी जाए। इसके लिए सिंधिया को वहां सक्रिय किया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2008 में छिंदवाड़ा गए थे। वे वहां दशहरा मैदान में कमलनाथ द्वारा आयोजित किए गए शंखनाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस शंखनाद कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आए थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत सिंह भी शामिल थे।

फाइनल करेगी।

अब कांग्रेस के कब्जे वाली 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया था। पृथ्वीपुर सीट पर बृजेंद्र सिंह राठौर ने जीत हासिल की थी। उनके निधन के बाद कांग्रेस पार्टी बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा जोबट विधानसभा सीट पर कलावती भूरिया के रिश्तेदार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रान्त भूरिया को टिकट देने की तैयारी में हैं। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि पार्टी सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। हो सकता है, जिन सीटों पर पार्टी का कब्जा था उसी परिवार के सदस्य को उपचुनाव में पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए। भले ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो लेकिन यह तय है उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों का भरोसा सहानुभूति से मिलने वाले वोटों पर होगा।

उधर, उपचुनाव में जिताऊ उम्मीदवार तलाशने कांग्रेस सर्वे करा रही है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ चारों सीटों पर सर्वे करा रहे हैं। उन्होंने कहा, सर्वे के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। सर्वे में कमलनाथ का फोकस जातिगत समीकरणों पर है। देश में भले ही जाति आधारित चुनाव नहीं होते, पर जीत-हार में बड़ा आधार माना जाता है। चुनावी क्षेत्र में जाति-वर्ग को देखते हुए ही उम्मीदवार तय करते हैं। कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि उपचुनाव वाले क्षेत्र खंडवा, रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट में सर्वे के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। खंडवा में वरिष्ठ नेता अरुण यादव तैयारी कर रहे हैं, उम्मीदवारी के लिए सर्वे में नाम आना जरूरी होगा। कमलनाथ ने उपचुनाव वाले जिलों के

प्रभारियां को ड्यूटी पर लगा दिया है। इन जिलों में मंडलों, सेक्टर में नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। साथ ही बूथ स्तर तक की तैयारियां करने को कहा गया है। कमलनाथ भी आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में दौरा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सर्वे के आधार पर ही जिताऊ उम्मीदवार का फैसला किया जाएगा। जातिगत समीकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा।

फिलहाल सत्ता-संगठन के लिए सबसे अहम खंडवा लोकसभा सीट है। यह सीट पूर्व सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के कोरोना से निधन के चलते खाली हुई है। इस सीट पर नंदकुमार के बेटे हर्ष की दावेदारी है। लेकिन, साथ ही क्षेत्रीय पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस और इंदौर के नेता कृष्णमुरारी मोघे के नाम भी सामने आए हैं। कांग्रेस से यहां पर पूर्व सांसद अरुण यादव का नाम चल रहा है। भाजपा इस क्षेत्र में मंत्रियों व अन्य नेताओं को सक्रिय कर चुकी है। मंत्री कमल पटेल, ऊषा ठाकुर सहित अन्य यहां दौरे कर चुके हैं। अगले हफ्ते से पार्टी नेताओं के दौरे भी होंगे। यहां टिकट का फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सलाह करके उनकी राजमंदी के हिसाब से ही होगा।

उपचुनाव वाली तीनों विधानसभा सीटों पर टिकट के लिए रस्साकशी के हालात हैं। कोरोना के कहर के कारण उपजे नकारात्मक माहौल को कवर करने के लिए संगठन की टीमों इन सीटों वाले इलाकों में काम कर रही है। इनमें पृथ्वीपुर सीट बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन से खाली हुई थी। वहीं जोबट सीट कलावती भूरिया के निधन और रेगांव सीट जुगल किशोर बागरी के निधन से खाली हुई थी। तीनों का ही कोरोना संक्रमण के चलते निधन हुआ था। अब भाजपा इन सीटों पर जातिगत व स्थानीय समीकरणों के हिसाब से नेटवर्किंग कर रही है। पिछली बार हारे दावेदारों के साथ इन सीटों पर नए दावेदारों की भी फौज है। हर सीट पर तीन से चार नेता दावेदारी के लिए भोपाल में सत्ता-संगठन के चक्कर काट रहे हैं। फिलहाल इन सीटों पर मंत्रियों को भी सक्रिय किया गया है। साथ ही इन सीटों के विकास कार्यों को भी प्राथमिकता से करना तय किया है। इसके बाद सत्ता-संगठन के संयुक्त आकलन के आधार पर टिकट फाइनल होंगे।

खंडवा लोकसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव की घोषणा होना है। कांग्रेस और भाजपा अपनी तैयारी कर ही रही हैं, वहीं बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने यहां से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है। शेरा के इस पैंतरे के बाद कांग्रेस और भाजपा के जीत के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं, क्योंकि इस सीट पर शेरा के परिवार के लोग निर्दलीय चुनाव भी जीत चुके हैं।

कांग्रेस की ओर से खंडवा में अरुण यादव को उम्मीदवार के रूप में उतारा जाना तय है,



भाजपा ने उतारी माननीयों की फौज

भाजपा ने प्रदेश में आगामी दिनों में संभावित एक लोकसभा क्षेत्र और तीन विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की दृष्टि से दायित्व तय किए हैं। यह दायित्व सरकार और संगठन के समन्वित स्वरूप में तय किए गए हैं। खंडवा लोकसभा क्षेत्र का विस्तार जिन चार जिलों तक है, उन चारों जिलों के अनुसार संगठनात्मक रूप से दायित्व सौंपे गए हैं। जिसमें बुरहानपुर जिले में प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा, खंडवा जिले में प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार, देवास जिले में प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय तथा खरगोन जिले में प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती जिला स्तर पर दायित्व संभालेंगे। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्रवार विकेंद्रित दायित्व भी सौंपे गए हैं। इस लोकसभा क्षेत्र के नेपालगर विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री तुलसी सिलावट एवं संगठनात्मक दृष्टि से प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह सौधिया। बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री इंदर सिंह परमार तथा संगठनात्मक दृष्टि से वरिष्ठ नेता गोपीकृष्ण नेमा। मांधाता विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री विजय शाह और संगठनात्मक दृष्टि से प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार। खंडवा विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री कमल पटेल एवं संगठनात्मक दृष्टि से पूर्व विधायक जसवंत सिंह हाडा और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर। पंधाना विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री मोहन यादव तथा संगठनात्मक दृष्टि से प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन और सांसद शंकर लालवानी। बागली विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री उषा ठाकुर एवं संगठनात्मक दृष्टि से प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय। भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री जगदीश देवड़ा एवं संगठनात्मक रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती। बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री जगदीश देवड़ा एवं संगठनात्मक रूप से राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष एवं सांसद सुधीर गुप्ता को दायित्व सौंपे गए हैं।

लेकिन पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अरुण यादव ने उन्हें नहीं बताया कि खंडवा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, के बाद कांग्रेस की अंदरूनी सियासत गरम है। अरुण यादव खुलकर नहीं बोल रहे हैं और कह रहे कि पार्टी जो कहेगी वह करूंगा, लेकिन उनके लगातार चल रहे दौरे उनकी दावेदारी की ओर इशारा कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा की ओर से अभी कोई नाम स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा है। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस और पूर्व महापौर कृष्णमुरारी मोघे के साथ दिवंगत नंदकुमारसिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धनसिंह के नाम की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। चुनाव की तारीख जल्द घोषित होना है, लेकिन इस बीच बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्रसिंह शेरा ने स्परेआम आकर अपनी पत्नी को यहां से

चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उससे भाजपा और कांग्रेस दोनों आश्चर्य में हैं। सुरेंद्रसिंह के परिवार के शिवकुमार सिंह 1980 और महेंद्रकुमार सिंह 1991 में यहां से सांसद रह चुके हैं। शेरा के अचानक सक्रिय हो जाने से भाजपा और कांग्रेस के चुनावी समीकरण बिगड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा की अगली रणनीति का इंतजार है, जिससे शेरा को टक्कर दी जा सके। कांग्रेस को लगता है कि कोरोनाकाल और महंगाई के मुद्दे पर जनता सरकार के खिलाफ है। लोगों की नाराजगी को वोट में बदलने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ उपचुनावों का चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। इसमें हर सीट पर कम से कम 10 विधायकों की टीम तैनात की जाएगी।

● जितेंद्र तिवारी

फंड का अभाव... विकास कार्य रुके

म प्र में कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था को बदहाल कर दिया है। इसका असर विकास कार्यों पर भी दिखने लगा है। फंड के अभाव में लोक निर्माण विभाग की कई परियोजनाएं आधी-अधूरी पड़ी हुई हैं। खासकर ज्वाइंट वेंचर सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। आलम यह है कि विकास के नए कार्यों के लिए टेंडर भी जारी नहीं हो रहे हैं। जिन परियोजनाओं को बारिश से पहले पूरा किया जाना था, वे अभी भी अधूरी पड़ी हुई हैं। उधर, निर्माता कंपनियों पर तरह-तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। लेकिन फंड न होने के कारण कंपनियां भी बेबस हैं।

प्रदेश के चर्चित ई-टेंडरिंग घोटाले के आरोपी श्रीनिवास राजू मेंटेना की मेंटेना कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई बड़े प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं। इससे सरकार को हर साल करोड़ों रुपए की राजस्व हानि हो रही है। सूत्रों की माने तो कंपनी ने प्रदेश में नियमों को ताक पर रखकर कई प्रोजेक्ट हथियाए हैं। कमलनाथ सरकार में कंपनी की खूब मनमानी चली है। अब मांग उठ रही है कि कमलनाथ के शासनकाल में कंपनी को जितने प्रोजेक्ट दिए गए हैं उनकी जांच कराई जाए और उन्हें निरस्त किया जाए। जानकारी के अनुसार कंपनी ने 1550 करोड़ की बीना, 120 करोड़ की जुडी और 100 करोड़ की गुड़ परियोजना को अफसरों के साथ मिलीभगत से पाया है।

हैदराबाद की इस कंपनी ने मद्र को चारागाह बना लिया है। इसकी बानगी इससे मिलती है कि प्रदेशभर में कंपनी के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वे आधे-अधूरे पड़े हैं। मेंटेना कंपनी को मर्जी के मुताबिक टेंडर मिले और उसी मनमानी के अनुसार काम कर रही है। 12 अप्रैल को बीना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया कि कंपनी को गोपालपुरा केनाल परियोजना का वर्क आर्डर 21 अगस्त 2015 को दिया गया था। आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। बारिश से पहले काम पूरा करना था लेकिन कंपनी ने नहीं किया। वहीं 15 अप्रैल को सुठालिया प्रोजेक्ट ब्यावरा राजगढ़ को समय पर पूरा नहीं करने के कारण कंपनी को टर्मिनेट और ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी गई थी, उसके बाद भी कंपनी ने काम पूरा नहीं किया है।

कंपनी पर टेंडर में फिक्सिंग के आरोप लगते रहे हैं। रीवा में भी नहर परियोजनाओं के कई कार्यों के लिए हुए टेंडर में फिक्सिंग के आरोप शुरू से लगते रहे हैं लेकिन जांच को दबाया जाता रहा है। रीवा में करीब दर्जनभर की संख्या में बड़े कार्य इस ग्रुप की कंपनी ने कराए हैं। कुछ प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं तो कुछ अब भी चल रहे हैं। वर्ष 2010 के बाद सरकार ने टेंडर प्रक्रिया के नियमों में बदलाव किया, तब से लगातार मेंटेना ग्रुप को ठेके मिलते रहे हैं। कुछ कार्य तो ऐसे भी रहे हैं जिनका टेंडर होने से पहले ही कंपनी ने



धांधली कर झटके अरबों के ठेके

जब ईडी ने ई-टेंडर सिस्टम में हेराफेरी करके फर्जी तरीके से टेंडर अपनी कंपनी के नाम करा लेने के आरोप में श्रीनिवास राजू मेंटेना और उसके साथी आदित्य त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था तब यह बात सामने आई थी कि इसने किस तरह मद्र में अपना काला कारोबार जमाया है। ईडी की जांच के मुताबिक मद्र सरकार अपने हर सरकारी काम के लिए ई-टेंडर के जरिए ठेके जारी करती हैं। टेंडर लेने वाली सभी कंपनियों को इसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। जांच में पता चला था कि श्रीनिवास राजू की कंपनी और हैदराबाद की कुछ कंपनियां पिछले कुछ समय से लगातार टेंडर जीत रही थी और ये सब टेंडर संभालने वाली कंपनियों की मिलीभगत से हो रहा था। इस काम में श्रीनिवास राजू की मदद आदित्य कर रहा था, जो कि एक तरह से फ्रंट कंपनी के तौर पर काम कर रही थी। इसी के जरिए श्रीनिवास राजू सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने और हवाला का पैसा इधर-उधर करने में इस्तेमाल करता था। इस साल मार्च में विधानसभा में शून्यकाल के दौरान विधायक दिनेश राय मुनमुन ने मेंटेना कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। दिनेश राय ने आरोप लगाया था कि बिना काम किए ही कंपनी को 500 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। दिनेश राय ने आरोप लगाया है कि इस कंपनी को सिवनी में नहर बनाने का टेंडर दिया गया था लेकिन कंपनी नहर का काम आधा छोड़कर चली गई, फिर भी पेमेंट जारी कर दिया गया।

काम शुरू कर दिया था और बाद में उसे ही टेंडर भी मिला। इन कार्यों को अपनी मर्जी के अनुसार कंपनी ने कराए और गुणवत्ता पर सवाल उठे तो जांच नहीं हुई। यहां तक कि बीच-बीच में भोपाल से टीमें भेजी जाती थीं जो ठेकेदार को ही क्लीनचिट देकर चली जाती थीं। जब मेंटेना के प्रमोटर श्रीनिवास राजू की गिरफ्तारी हुई थी तब से रीवा, सतना एवं सीधी में मेंटेना और उसकी करीबी ठेका कंपनियों को मिले ठेके की जांच करने की मांग उठाई जा रही है।

मेंटेना ग्रुप को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों में छूट दी जाती रही है। रीवा जिले के कई ऐसे ठेके हैं जिसमें ठेका कंपनी को पहले से पता था कि उसे ही काम मिलेगा। सतना जिले में स्थित मझगवां डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए ई-टेंडर का समय आखिरी दिन शाम 5:20 बजे तक निर्धारित था। उस समय पर वेबसाइट का सर्वर बंद कर दिया

गया। इसके बाद बिना किसी सूचना के दो दिन निविदा की अवधि और बढ़ा दी गई, जिसका फायदा सीधे मेंटेना को ही मिला। मेंटेना ग्रुप के लोगों ने दूसरे नाम की फर्मों से ठेका लेकर काम कराया है। बहुती-फलो परियोजना में सद्भाव ग्रुप को ठेका मिला। मेंटेना और उसकी सहयोगी फर्मों को रीवा जिले में कई प्रमुख कार्य ई-टेंडरिंग के जरिए दिए गए। जिस पर कंपनी की ओर से कई परियोजनाओं का अधूरा कार्य छोड़ दिया गया है। जिसकी वजह से नहरों का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। कई ऐसे कार्य हैं जिनमें 80 से 90 प्रतिशत कार्य पूरा करने का दावा किया गया है और भुगतान भी हो चुका है लेकिन इस पर जो कार्य अधूरा छोड़ा गया है वह किसी बीच के हिस्से में है। जिसकी वजह से नहरों का पानी आगे की ओर नहीं जा रहा है।

● बृजेश साहू

मद्र में एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार औद्योगिक विकास पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के पुराने उद्योग-धंधे बंद हो रहे हैं। ऐसे में उद्योगों में कार्यरत लोगों का कहना है कि सरकार नए उद्योग खोलने के साथ ही पुराने उद्योगों को भी संभाले।



नए भूमिपूजन, पुराने हो रहे बंद

पिछले दिनों मद्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस शहर में कपड़े की मिल्स का उद्घाटन करके कोरोनाकाल में ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था और रोजगार को संजीवनी पिलाने की कवायद कर रहे थे, उससे 150 किलोमीटर दूर एक कारखाने के तकरीबन हजार से ज्यादा मजदूर अपनी बंद पड़ी कपड़ा फैक्ट्री को चालू करवाने की मांग लेकर गेट पर धरना दे रहे थे। कर्मचारी चाहते हैं कि कंपनी में कामकाज चालू हो, पर कंपनी उन्हें वीआरएस का ऑफर देकर अपना पिंड छुड़ाना चाहती है। इस आंदोलन को अब देश के विभिन्न संगठनों-आंदोलनों का भी साथ मिल गया है।

नए कारखानों के भूमिपूजन और पहले से स्थापित कारखानों को चालू करने की मांग से विचित्र स्थिति बन रही है, अजीब बात है कि एक तरफ नए उद्योगों को जमीनें आवंटित कर प्रोत्साहित किया जा रहा है, दूसरी ओर बंद कारखानों को चालू करने को लेकर कोई हस्तक्षेप नहीं है। महाकाल की नगरी उज्जैन को एक नए औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत के रूप में मुख्यमंत्री ने होजरी कारखाने का भूमिपूजन किया। अगले कुछ महीनों में 6 और कारखाने शुरू हो जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि इससे तकरीबन 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

रोजगार में ज्यादा हिस्सेदारी महिलाओं की

होगी। उद्योगों के निवेश की यह पहली कवायद नहीं है। मद्र में शिवराज सिंह चौहान के लगभग हर कार्यकाल में इंवेस्टर्स मीट करके देशभर से उद्योगों को मद्र आने का न्यौता देते रहे हैं। कई उद्योग आए भी, लेकिन बहुत सारे उद्योग एमओयू करने के बाद भी अब तक जमीन पर नहीं उतर पाए हैं।

अजीब बात है कि खरगोन जिले में सेंचुरी यार्न और डेनिम का कारखाना मजदूर चलाते रहना चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि उन्हें इससे रोजगार मिलता रहेगा, लेकिन कंपनी इसके लिए राजी नहीं है। 2017 से इस कंपनी में उत्पादन ठप्प पड़ा है। इन कंपनियों में तकरीबन 900 नियमित कर्मी और 600 से ज्यादा ठेकाकर्मी काम करके अपना परिवार पालते थे। यह मजदूर पिछले 44 महीनों से लगातार कारखाने के दरवाजे पर धरना दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से अपील कर रहे हैं, इसके लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें वेतन आदि भी नियमित रूप से देना पड़ रहा है, लेकिन कंपनी अपना काम शुरू नहीं कर रही।

आंदोलन करने वाले संगठन के प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि इस कंपनी ने कोरोनाकाल में भी अपने बहीखातों में लाभ को दर्शाया है, फिर आखिर क्या वजह है कि जिस प्रदेश में होजियारी और दूसरे कपड़ों के कारखानों को पलक-पांवड़े बिछाकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसी प्रदेश में एक स्थापित कारखाना मांग

करने के बावजूद चालू नहीं किया जा रहा है। मद्र के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बात को समझना चाहिए। आखिर, उन्होंने उज्जैन में उद्घाटन करते हुए यह कहा भी कि निवेश ऐसे ही नहीं आ जाता, उसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है। उन्होंने खुद ही कहा कि उज्जैन आने वाली कंपनियों को वे पिछले चार सालों से लगातार निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, तब जाकर यह उपलब्धि हासिल हुई। उन्हें जाकर बंद होने जा रहे कारखानों से भी पूछना चाहिए कि उन्हें क्या दिक्कत है और वे कैसे इस दिक्कत को दूर कर सकते हैं जिससे कारखाना चलता रहे और हजारों मजदूरों को वीआरएस की कुछ रकम लेकर घर न बैठना पड़े।

बात केवल सेंचुरी कारखाने की ही नहीं है। मद्र में ऐसे कई उद्योग हैं जिन्हें भारी-भरकम निवेश करके लगाया गया था, लेकिन वह धीरे-धीरे बंद होते गए। होशंगाबाद जिले के बानापुरा में तिलहन संघ का सोयाबीन प्लांट भी एक समय रोजगार की बड़ी उम्मीद लेकर आया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कार्यकाल में स्थानीय विधायक हजारीलाल रघुवंशी ने इसे अपने गृहनगर में स्थापित करवाने में सफलता हासिल की। सोयाबीन की बंपर पैदावार के बाद यह कुछ साल चला भी, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट पिछले 20 सालों से ज्यादा से बंद पड़ा है।

● श्याम सिंह सिकरवार

कोरोना के बाद बढ़ी पलायन की समस्या

दूसरी ओर मद्र में पलायन की बहुत बड़ी समस्या रही है जो कोरोना के बाद और भी बढ़ी हो गई है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्य, निमाड़, मालवा, तकरीबन हर क्षेत्र से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। पिछले साल, कोरोना की लहर में इसका एक रूप देखने को मिला था, जब हजारों की संख्या में मजदूर पैदल चलकर अपने घरों को लौटे थे। इसकी बड़ी वजह, स्थानीय स्तर पर रोजगार का नहीं मिलना है। मनरेगा का ढुलमुल क्रियान्वयन भी मजदूरों को मनरेगा में काम करने से हतोत्साहित करता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि स्थानीय स्तर पर भी छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया जाए। इस रूप में मद्र सरकार की यह कोशिश अच्छी है, लेकिन सवाल यह है कि इसी प्रदेश में दूसरे कारखानों के बंद करने पर वह हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकती। आखिर ऐसे उद्योगों की समीक्षा क्यों नहीं की जाती है।

म प्र सरकार ने ग्वालियर-चंबल संभाग में बनने वाले अटल प्रोग्रेस वे यानी चंबल प्रोग्रेस-वे की जिस दावे के साथ शुरुआत की थी, वह हवा-हवाई साबित हो रहा है। चंबल के बीहड़ों में बनने वाला मेगा हाइवे अटल चंबल प्रोग्रेस-वे का नाम अब तक तीन बार बदला जा चुका है, लेकिन इसका निर्माण फाइलों से निकलकर धरातल पर नहीं आ पा रहा है। प्रोग्रेस-वे के लिए जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन तो आवंटित कर दी है, लेकिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण अब तक नहीं हो पा रहा है। कारण यह है कि निजी जमीन के अधिग्रहण को लेकर शासन ने कोई गाइडलाइन या स्पष्ट आदेश-निर्देश ही जिला प्रशासन को नहीं दिए हैं।

गौरतलब है कि भारत माला परियोजना के तहत नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) द्वारा राजस्थान के दीगोद से लेकर श्योपुर, मुरैना और भिंड होते हुए उप्र तक को जोड़ने के लिए 404 किलोमीटर लंबा अटल चंबल प्रोग्रेस-वे बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेस-वे की लंबाई मप्र के श्योपुर, मुरैना व भिंड जिले में 309.08 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण पर 6 हजार 58 करोड़ 26 लाख रुपए का खर्च आंका जा रहा है। मुरैना जिले में प्रोग्रेस-वे का हिस्सा 144 किलोमीटर का होगा, इसके निर्माण में 980 हेक्टेयर जमीन सरकारी आ रही है, जिसका आवंटन मुरैना जिला प्रशासन ने एनएचएआई को कर दिया है। सरकारी जमीन के अलावा लगभग 475 हेक्टेयर जमीन निजी भी है, जो किसानों से अधिग्रहण करने के बाद एनएचएआई को दी जानी है, पर मुरैना के अलावा श्योपुर व भिंड जिले में अभी तक एक भी किसान की जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है।

इसका कारण यह है कि जमीन अधिग्रहण को लेकर जितने भी आदेश मिले हैं वह मौखिक रूप से दिए गए हैं। स्थिति यह है कि श्योपुर जिले में जमीन के बदले किसानों को दोगुनी जमीन देने को कहा गया, मुरैना व भिंड में जमीन के बदले जमीन देने की बात प्रशासन ने किसानों के बीच जाकर कही, पर हकीकत यह है कि अब तक सरकार ने निजी जमीन के अधिग्रहण को लेकर स्पष्ट आदेश किसी भी जिले को नहीं दिए हैं।

अटल चंबल प्रोग्रेस-वे के निर्माण की आहट के बाद से ही बीहड़ों में अतिक्रमण बढ़ गया है। भूमाफिया बीहड़ों को समतल करके खेत बना रहे हैं। जौरा क्षेत्र के तिंदोखर से लेकर देवगढ़, कोटरा और कोल्हूडाडा तक जिन बीहड़ों में



फाइलों में ही दबी है चंबल प्रोग्रेस-वे

ऐसा होगा चंबल प्रोग्रेस-वे

अटल प्रोग्रेस-वे कुल 394 किमी का होगा। यह मप्र में 309 किमी का बनेगा। राजस्थान में 85 किमी का हिस्सा होगा। इसके तहत 100 फीट चौड़ा फोरलेन मेगा हाईवे होगा। जिस पर 100 किमी रफ्तार से वाहन चले ऐसा डिजाइन बनेगा।

जिसमें से मुरैना जिले में 144 किमी, श्योपुर जिले में 97 किमी और भिंड जिले में 67 किमी का हिस्सा होगा। श्योपुर एसडीएम रूपेश उपाध्याय कहते हैं कि जब से चंबल एक्सप्रेस-वे प्रस्तावित हुआ है तब से बीहड़ों में अतिक्रमण बढ़ गया है। श्योपुर में मानपुर, ढोढर से लेकर श्यामपुर, वीरपुर क्षेत्र में

100 से 115 हेक्टेयर बीहड़ों पर अतिक्रमण होकर खेत बन गए हैं। हम इसका पूरा डाटा जुटा रहे हैं, जिससे कार्रवाई हो सके। मुरैना संयुक्त कलेक्टर संजीव जैन कहते हैं कि चंबल प्रोग्रेस-वे लिए हमने सरकारी जमीन तो एनएचएआई को पहले ही आवंटित कर दी है। इसके लिए 475 हेक्टेयर के करीब प्राइवेट जमीन भी है, जिसका अधिग्रहण करना है। अधिग्रहण को लेकर शासन से स्पष्ट आदेश-निर्देश नहीं आए हैं, इसलिए किसी किसान की जमीन अधिग्रहित नहीं की है। अधिग्रहण की प्रक्रिया लंबी होती है, सरकार से जैसे निर्देश आएंगे, उस तरह इस परियोजना के लिए निजी जमीन का अधिग्रहण कर निर्माण एजेंसी को दे देंगे।

मिट्टी के पहाड़ नजर आते थे वहां अब सैकड़ों बीघा समतल जमीन और कईयों जगह उस जमीन पर खेती नजर आ रही है। तिंदोखर के अलावा खाड़ौली, मथुरापुरा, गड़ोरा, जखोना, बरवाई, रायपुरा, नगरा, कनेरा से लेकर भिंड के अटेर, खैरी, खिपैना, बिजौरा क्षेत्र में बीहड़ों को समतल किया जा रहा है। श्योपुर जिला प्रशासन के अनुसार बीते एक से डेढ़ साल में 700 बीघा से ज्यादा बीहड़ों में अतिक्रमण करके खेत बना लिए गए हैं। मुरैना में चंबल एक्सप्रेस-वे की लंबाई सबसे अधिक 144 किमी है, इसलिए मुरैना के 2200 से 2500 बीघा बीहड़ों में अतिक्रमण हो चुका है। इस अतिक्रमण के पीछे भूमाफिया की सोच यह है कि अगर सरकार जमीन के बदले जमीन देगी तो उन्हें इस अतिक्रमण की जमीन के बदले सरकार द्वारा दी जाने वाली जमीन मिलेगी, जिस पर उनका सरकारी रिकार्ड में भी मालिकाना हक होगा।

अटल चंबल एक्सप्रेस-वे की हालत यह है कि अभी तो यह चुनावी मुद्दा बन गया है। पहले विधानसभा चुनाव में जब इसका नाम चंबल एक्सप्रेस-वे हुआ करता था तब भाजपा ने इसका खूब प्रचार किया। चुनाव बीतते ही इसका नाम बिसरा दिया, इसके बाद उपचुनाव से पहले चंबल प्रोग्रेस-वे की याद नेताओं के साथ प्रशासन को भी आई। तत्कालीन संभाग आयुक्त आरके मिश्रा मुरैना के अलावा भिंड व श्योपुर तक खुद दौरा करके ग्रामीणों को जमीन अधिग्रहण के लिए समझा रहे थे। चुनाव से पहले एक्सप्रेस-वे के निर्माण और उसके फायदों का ऐसा प्रचार-प्रसार हुआ कि लग रहा था कि 2021 में निर्माण काम शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही चुनाव बीते इस परियोजना का कोई नाम ही नहीं ले रहा।

● नवीन रघुवंशी

प्रदेश

सरकार ने बिना सतही

योजना के चंबल प्रोग्रेस वे के लिए जमीनों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है उसके परिणाम सुरवद नहीं हैं।

सरकार ने सरकारी जमीनें अधिग्रहित कर

ली लेकिन निजी जमीनें लेना

मुश्किल लग रहा है।

ग्राम पंचायतों में जनता द्वारा चुने गए पंच-सरपंच का कार्यकाल 2020 में पूरा हो चुका है। बीते डेढ़ से पंचायतों में समितियां गठित की गई हैं, जिनकी कमान निवर्तमान सरपंचों के ही हाथ, लेकिन अब यह सरपंच

की बजाय पंचायत के प्रधान कहलाते हैं। सरपंच के नाम के साथ ग्राम पंचायतों में कामकाज के तौर-तरीके ऐसे बदले हैं, कि जॉबकार्ड धारी मजदूरों से मनरेगा योजना दूर हो गई है। मजदूरों की जगह जेसीबी, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि मशीनें काम कर रही हैं। मनरेगा का नियम है कि स्वीकृत बजट का 60 फीसदी हिस्सा मजदूरों पर खर्च हो और 40 फीसदी बजट से निर्माण सामग्री (पत्थर, सीमेंट, रेत, सरिया, गिट्टी आदि) खरीदी जाए। जब पंचायतों में पंच-सरपंच थे तब काफी हद तक ऐसा ही हो रहा था, लेकिन अब हकीकत यह है कि जॉबकार्डधारी मजदूरों तक 60 तो क्या 30 फीसदी बजट नहीं पहुंच पा रहा। इसका कारण यह है कि ग्राम पंचायतों के प्रधान (सरपंच) को अब जनपद या जिला पंचायत का खास डर रहा नहीं। क्योंकि उनकी नियुक्ति कलेक्टर ने की है। पहले जिला पंचायत सीईओ धारा 40 में वसूली और धारा 92 के तहत पद से पृथक कर सकते थे, अब जिला पंचायत सीईओ को यह अधिकार नहीं रहे, संभवतः यही कारण है कि सरपंच बने प्रधान कई जनप्रतिनिधि पंचायत की बजाय खुद का विकास करने में जुटे हैं। हैरानी इस बात की है कि पंचायतों में भ्रष्टाचार की शिकायतें बीते एक साल में चरम पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन मुर्ना जिला प्रशासन, जिला पंचायत या जनपद इस दौरान किसी एक भी पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक व उपयंत्री पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इससे अधिकारियों की नीयत पर भी संदेह बढ़ना लाजिमी है।

जौरा जनपद की देवगढ़ ग्राम पंचायत में बीते दो साल में कोई नया निर्माण कार्य नहीं हुआ, फिर भी ग्राम पंचायत ने निर्माण कार्यों पर 39.99 लाख रुपए खर्च कर डाले हैं। करीब 40 लाख के इस घपले के लिए सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक व इंजीनियर ने मिलकर ओछापुरा, छत्तरपुरा व देवगढ़ में सालों पहले बनी सीसी सड़कों, बिंडवा गांव में पहले बन चुके सामुदायिक शौचालय सहित कई पुराने निर्माणों को नया बताकर लाखों रुपए निकाल लिए हैं। इसी तरह मजरा ग्राम पंचायत ने 20 साल पुराने तालाब का नया निर्माण बताकर 15 लाख से ज्यादा का गबन किया है। पोरसा जनपद की पिपरई ग्राम पंचायत में खेल मैदान के लिए 10 लाख का बजट मिला। गांव में कहीं खेल मैदान नहीं



कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान मनरेगा मग्न के प्रवासी मजदूरों के लिए सजीवनी बनी थी। लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने सरकार के सारे प्रयासों पर पानी फेर दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सरपंच जबसे प्रधान कहलाने लगे तब से मजदूरों को मनरेगा से दूर कर दिया गया है।

मजदूरों से दूर हो गई मनरेगा

कई पंचायतों ने फर्जी मनरेगा मजदूर ही बना दिए

पोरसा जनपद की सिलावली पंचायत में मतदाता 3368 हैं, जबकि पंचायत ने मनरेगा मजदूरों 3933 बना दिए हैं। यानी 565 मजदूर की बढ़ा दिए हैं। इसी तरह मुर्ना जनपद की भानपुरा पंचायत में करीब 400, पहाड़गढ़ जनपद की बहरारा-जागीर पंचायत में 1287 मतदाताओं की तुलना में 1401 मनरेगा मजदूर बना दिए गए हैं। सबलगढ़ जनपद की सेमना पंचायत में 1147 मतदाता और 2664 मनरेगा मजदूर एवं बनवारा पंचायत में 2511 मतदाता और 2751 मनरेगा मजदूर बना दिए गए हैं। इन सभी फर्जी मजदूरों को कागजों में काम दिया जाता है और उनके नाम से हर महीने लाखों रुपए का भुगतान निकाला जाता है। मुर्ना जनपद की धनेला ग्राम पंचायत ने तो मृतकों को ही मनरेगा मजदूरी देकर लाखों का गबन कर दिया है। पोरसा जनपद की पिपरई पंचायत के विजयगढ़ में सड़क निर्माण हो रहा है, जिसमें मजदूरों की जगह चार-चार जेसीबी दिन-रात काम कर रही हैं। सबलगढ़ जनपद की बामसौली ग्राम पंचायत में तालाब का निर्माण हो रहा है, जिसमें मजदूरों की जगह जेसीबी काम कर रही है। तालाब की पार बनाने के लिए मनरेगा योजना से 15-15 लाख के तीन अलग-अलग काम (सहजने वाले नरा, हीरामन-बामसौली और देववाली नरी) स्वीकृत करवाए, पर यह पूरा बजट एक ही जगह खर्च हो रहा है।

बना पर 10 लाख का बजट खर्च हो गया है।

पिपरई ग्राम पंचायत के मनरेगा मजदूर उमाकांत पुत्र मुन्नालाल दुबे, मुन्नीबाई पत्नी कालीचरण, शंकरदयाल पुत्र गिराज कुमार आदि ने शपथ पत्र देकर एसडीएम से लेकर जिला पंचायत सीईओ से शिकायत की है, उनके मोबाइल में सिर्फ मजदूरी का पैसा आने का मैसेज आता है, उन्हें आज तक न तो पंचायत ने काम दिया है न ही एक रुपए की मजदूरी का भुगतान। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के सभी जॉबकार्डधारी मजदूरों के बैंक खाता खुलवाने के बाद उनके एटीएम सरपंच-सचिव ने रख लिए हैं। एटीएम से मजदूरों से खातों का पैसा निकालकर बंदरबांट होता है। ऐसी हालत कई पंचायतों में है और कुछ पंचायतों के सरपंच-सचिव ने अपने परिचित के नाम से कियोस्क बैंक खुलवा लिए हैं, जिससे मनरेगा मजदूरों का पैसा फर्जी तरीके से खुद निकाल रहे हैं। जिला पंचायत सीईओ, मुर्ना रोशन कुमार सिंह कहते हैं कि जिन-जिन पंचायतों की शिकायतें आ रही हैं, वहां की जांच करवा रहे हैं। हां यह सही है कि कई पंचायतों ने मनरेगा मजदूर, गांव की बालिग जनसंख्या से ज्यादा बढ़ा दिए हैं। कुछ पंचायतों की पुराने कामों के नाम पर लाखों की राशि खर्च करने की शिकायतें हैं। इन पंचायतों में जांच के लिए संबंधित जनपदों को निर्देश दिए हैं।

● विकास दुबे

को विड-19 के चलते बीते शिक्षा सत्र में बेपटरी पर रही महाविद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था को इस साल पटरी पर लौटने की उम्मीद है। इसी को ध्यान में रखते हुए व कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र 2021-22 की प्रवेश शेड्यूल एवं अकादमिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया एक अगस्त से शुरू होगी। लेकिन हॉस्टल के खुलने की कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कॉलेज खुल भी जाएंगे तो छात्र कहां रहेंगे।

दरअसल, कोरोना संक्रमण के कारण अभिभावक नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे भीड़-भाड़ में रहें। वर्तमान में ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। अभिभावक भी चाहते हैं कि जब तक कोरोना का वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता है तब तक कॉलेज ना खोले जाएं। अगर अगस्त में कोरोना के मामले नहीं बढ़े तो भले ही तय शर्तों के साथ कॉलेज खुल जाएं लेकिन पिछले डेढ़ साल से हॉस्टल संचालक लगातार नुकसान उठा रहे हैं। हॉस्टल बंद होने से जहां रखरखाव मुश्किल हो रहा है वहीं अब स्थिति यह है कि टिफिन और इससे जुड़ हुए व्यवसाय भी प्रभावित हुए हैं। हाल में स्कूल खोले जाने के ऐलान के दौरान यह स्पष्ट किया गया था कि अगर कोरोना नियंत्रित रहा और संक्रमितों की संख्या में इजाफा नहीं होता है तो कॉलेज खोलने पर विचार होगा। अब कॉलेज संचालक भी दिशा-निर्देश आने का इंतजार कर रहे हैं। हॉस्टल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के मुताबिक भोपाल शहर में 173 रजिस्टर्ड हॉस्टल हैं। इसके अलावा विभिन्न इलाकों में 400 से ज्यादा हॉस्टल संचालित हो रहे हैं। अब स्थिति यह है कि संचालकों ने स्टाफ भी बहुत सीमित कर दिया है। 1200 से ज्यादा कर्मचारी हटा दिए गए हैं।

भोपाल हॉस्टल ऑनर्स एसोसिएशन के सचिव विकास वीरानी ने बताया कि हालात यह हैं कि कई हॉस्टल संचालक बैंक की किश्त भी नहीं चुका पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली बिल व मेटेंस पर खर्च होता ही है। पूरे कोरोनाकाल में करीब 12 से 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। संचालकों का कहना है कि कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए हॉस्टल खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। कई संचालक ऐसे हैं जिन्होंने इसे तैयार करने में काफी निवेश किया अब वे कुछ और करने की स्थिति में भी नहीं हैं। सवाल उठता है कि अगर हॉस्टल खुल भी जाते हैं तो क्या अभिभावक अपने बच्चों को उसमें रहने की इजाजत देंगे? दरअसल, कोरोना संक्रमण की चपेट में बड़ी संख्या में युवा आए हैं। इसको देखते हुए अभिभावकों में अभी

कॉलेज खुलेंगे... छात्र कहां रहेंगे ?



छात्र पर आपराधिक केस हो तो प्राचार्य नहीं दे सकेंगे दारिद्र्य

कॉलेजों में 1 अगस्त से शुरू हो रही दाखिले की प्रक्रिया में ऐसे छात्रों को प्रवेश देने के लिए प्राचार्य अधिकृत नहीं होंगे, जिन पर कोर्ट में आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं या चालान प्रस्तुत किया जा चुका हो। ऐसे छात्र को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिन्होंने पूर्व सत्र में किसी छात्र, अधिकारी-कर्मचारी के साथ मारपीट की हो। अगर ऐसे छात्रों में चेतावनी देने के बाद भी सुधार नहीं हुआ है तो उन्हें भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है। इधर, प्रदेश के बाहरी छात्रों को कॉलेज में दाखिले के दौरान शपथ पत्र भी देना अनिवार्य किया गया है। इसमें गलत जानकारी पाए जाने की स्थिति में संबंधित छात्र का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। इसी के साथ प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में अगले 3 साल तक प्रवेश नहीं मिलेगा।

भी कोरोना का डर बना हुआ है।

उधर, जारी गाइडलाइन के अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के साथ अन्य पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एक अगस्त से शुरू होगी। महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया तीन चरणों में की जाएगी। जिसमें अंतिम चरण सीएलसी का होगा। इसमें बची हुई सीटों पर प्रवेश महाविद्यालय स्वयं दे सकेंगे। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन प्रवेश के दौरान दस्तावेज के सत्यापन से छूट रहेगी। साथ ही प्रवेश लेने के बाद छात्रों को सभी दस्तावेज कॉलेज में जमा करने होंगे।

उच्च शिक्षा विभाग का कहना है कि तय शेड्यूल के अनुसार स्नातक की सभी कक्षाएं एक सितंबर से शुरू हो जाएंगी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते दो माह देरी से शुरू हो रहे शिक्षा सत्र को समय पर लाने के लिए पीजी प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच होंगी और परीक्षा परिणाम 31 जनवरी तक घोषित किया जाएगा। वहीं पीजी द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 से 22 मई तक होंगी और परिणाम 30 जून 2022 तक घोषित किया जाएगा। इसी तरह यूजी

प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षाएं एक अप्रैल से 21 मई तक कराई जाएंगी और परिणाम 30 जून तक घोषित किया जाएगा।

मप्र में अब रोजगार मूलक कोर्सेस उच्च शिक्षा विभाग शुरू करने जा रहा है। प्रदेशभर के कॉलेजों में जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स नए शिक्षा सत्र से शुरू किए जा रहे हैं। छात्र-छात्राओं की रुचि के हिसाब से ही सर्वे के बाद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। जिस भी कोर्स में छात्र-छात्राओं की रुचि होगी, उसी में उनको दाखिला दिलाया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि इन कोर्स के माध्यम से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि नए शिक्षा सत्र से 107 सरकारी कॉलेजों में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इनमें 117 डिप्लोमा और 282 से ज्यादा सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के 15 कोर्स तैयार किए गए हैं। सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने का और डिप्लोमा कोर्स एक साल का होगा।

● प्रवीण कुमार

बुं देलखंड क्षेत्र इस साल भीषण सूखे की चपेट में है। बारिश न होने और खेतों में नमी न होने के कारण ज्यादातर खेतों में बुवाई नहीं हुई है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने बारिश की उम्मीद से तिल, उड़द आदि बो दी थी लेकिन बारिश न होने के बाद बीज सूख गए और उन्हें हजारों रुपए का नुकसान हो गया। बुंदेलखंड में मानसून सामान्यतः 15 जून तक पहुंच जाता था। लेकिन इस बार एक महीने की देरी के बावजूद मानसून के बादल नहीं बरसे हैं।

जन जल जोड़ो अभियान के संयोजक संजय सिंह कहते हैं कि बुंदेलखंड भीषण सूखे की जद में है। उनका कहना है, 'इस साल कोविड-19 के कारण किसानों की अधिकांश आय इलाज पर खर्च हो गई है। उन्हें मौजूदा फसल से बहुत उम्मीद थी लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। 15 जुलाई तक इतनी कम बारिश बुंदेलखंड में नहीं देखी गई है।' मौजूदा वर्ष की तुलना 2002 के सूखे से करते हुए संजय सिंह कहते हैं कि 2002 में 15 जुलाई तक राज्य में सूखे की घोषणा कर दी गई थी। उनका कहना है कि अगर 15 जुलाई तक 50 प्रतिशत बारिश न हो तो नियमों के अनुसार, सूखे की घोषणा करनी पड़ती है। हालांकि इस साल ऐसी किसी घोषणा की सुगबुगाहट नहीं है। वह बताते हैं कि मौजूदा सीजन में नुकसान का असर अगले फसल चक्र पर भी पड़ेगा। बुंदेलखंड में पृथक राज्य का आंदोलन चला रहे सामाजिक कार्यकर्ता तारा पाटकर ने 16 जुलाई की सुबह एक वीडियो जारी कर बताया, 'महोबा के सिद्धबाबा का सिद्ध कुंड जो कभी नहीं सूखा, इस साल बेपानी है। इस वर्ष हालात बहुत खराब होने के आसार हैं। बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर और जालौन में वर्षा आंशिक भी नहीं हो रही है। पूरा आषाढ़ बीत रहा है। बांदा और महोबा के हालात इस वर्ष जलसंकट से बदतर होने की स्थिति बन रही है। बुंदेलखंड भीषण सूखे की तरफ जा रहा है।'

उप्र के जालौन जिले के मीगनी गांव के माताप्रसाद तिवारी ने अपने 4 हैक्टेयर के खेत में करीब 50 हजार रुपए खर्च कर पिछले महीने जून के मध्य में तिल बोया था लेकिन खेतों में बारिश की एक बूंद नहीं गिरी जिससे खेतों को नमी नहीं मिल पाई और तिल का बीज सूख गया। 60 साल के माताप्रसाद बताते हैं कि उन्होंने 1988-89 में ऐसी परिस्थिति देखी थी। उस साल बुंदेलखंड में भीषण सूखा पड़ा था। यह सूखा बुंदेलखंड के सबसे खतरनाक सूखों में एक था। तब से पहली बार मानसून की बारिश में इतनी देर हुई है। उन्होंने माना कि इस साल सूखे के पूरे आसार हैं। माताप्रसाद के अनुसार, 'अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो किसानों के लिए पूरा सीजन बेकार चला जाएगा।'

महोबा जिले के पुपवारा गांव के निवासी



गंभीर सूखे की चपेट में बुंदेलखंड

अधिकांश जिलों में कम बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, बांदा जिले में औसत से 48 फीसदी कम बारिश, झांसी में 58 प्रतिशत कम बारिश, ललितपुर में 80 फीसदी कम बारिश, महोबा में 69 प्रतिशत कम बारिश हुई है। हालांकि जालौन में 17 फीसदी ही कम बारिश दर्ज की गई है लेकिन यहां भी स्थिति चिन्नकूट जैसी है। बारिश उस समय हुई जब किसानों को इसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी। जालौन जिले के मीगनी गांव के प्रधान राजेश कुमार बताते हैं, 'जुलाई का महीना अब तक सूखा रहा है। किसान बुवाई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जिन खेतों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहां फसल की उम्मीद धूमिल हो गई है।' राजेश कुमार को लगता है कि यह साल खेती के लिहाज से काफी मुश्किल रहने वाला है। मप्र के हिस्से वाले बुंदेलखंड में भी सूखे की स्थितियां बन रही हैं। छतरपुर जिले में सामान्य से 51 फीसदी कम बारिश, पन्ना में 69 प्रतिशत कम बारिश, टीकमगढ़ में 58 प्रतिशत कम बारिश, सागर में 17 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। झांसी निवासी परमार्थ समाजसेवी संस्थान में सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र यादव बताते हैं कि पूरा बुंदेलखंड इस साल भीषण सूखे की चपेट में है। सूखे की एक बड़ी वजह बताते हुए संजय सिंह कहते हैं कि इस साल मप्र के कई हिस्सों में बारिश नहीं हुई है। इन हिस्सों का पानी बहकर बुंदेलखंड की नदियों और नहरों में आता है लेकिन इस साल ये सब सूखी पड़ी हैं।

बिंद्रावन प्रसाद बताते हैं कि इस साल मानसून से पहले वाली बारिश भी नहीं हुई। इस बारिश से खेतों में थोड़ी बहुत नमी आ जाती थी और किसान बुवाई कर देते थे। बिंद्रावन के करीब 25 बीघा खेत हैं। उन्होंने तिल, अरहर और मूंग की फसल की तैयारी की थी। वह बताते हैं कि अगर इस साल अच्छी खेती नहीं हुई तो उनकी माली हालत बहुत खराब हो जाएगी। बिंद्रावन की पिछले साल की सारी बचत परिवार की बीमारी पर खर्च हो गई है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान उनके परिवार के सभी 6 सदस्य बीमार हो गए थे। बिंद्रावन बताते हैं, 'मेरा परिवार पहले से कर्ज में डूबा है। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि मैंने अपने दो बेटों को कमाने के लिए शहर में भेज दिया है क्योंकि इस साल खेती से उम्मीद न के बराबर है।'

बांदा जिले के बसहरी गांव के बच्ची प्रसाद ने भी अपने 10 बीघा के खेत में तिल की बुवाई कर दी थी लेकिन बारिश न होने पर बीज सूख गए। बच्ची प्रसाद के बेटे घनश्याम कुमार बताते हैं कि यह मौसम तो बेकार हो गया। बीज सूखने के बाद खेतों में पैदावार की उम्मीद नहीं है। घनश्याम के मुताबिक, 'इस समय तक तिल की फसल खड़ी हो जाती थी लेकिन इस बार बीज ही नहीं डाला गया। अब रबी के मौसम से ही उन्हें उम्मीद बची है।' बसहरी के अधिकांश किसानों की स्थिति बच्ची प्रसाद जैसी ही है। इस गांव में बहुत से किसान खरीफ के मौसम में तिल की फसल बोते हैं। गांव में बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने किराए के ट्रैक्टर के जरिए दो-दो बार अपने खेतों की जुताई करा दी है लेकिन वे अब तक बुवाई नहीं कर पाए हैं।

● सिद्धार्थ पांडे



जासूसी का जाल देशभर में बवाल

पेगासस जासूसी मामले को लेकर
सड़क से संसद तक विपक्ष हमलावर

भारत सहित दुनियाभर में इन दिनों पेगासस जासूसी कांड छाया हुआ है। देशभर में सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। जहां तक जासूसी का सवाल है तो यह कोई नई बात नहीं है। शायद मानव इतिहास के प्रारंभ से ही जासूसी चलती आ रही है। प्राचीन काल में चाहे राजा रहे हों या आज की सरकारें, उन्हें जनता की टोह लेने या पड़ोसी देश की सैन्य शक्ति की जानकारी हासिल करने के लिए जासूसी का सहारा लेना पड़ता है। जासूसी के बल पर न जाने कितने युद्ध जीते गए होंगे।

● राजेंद्र आगाल

गुलाम अली की गजल... हंगामा है क्या बरपा... की तरह देश में पेगासस जासूसी मामले पर हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष सत्तारूढ़ भाजपा पर जासूसी कराने का आरोप लगाते हुए पिल पड़ा है। सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। उधर, पेगासस

जासूसी मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। वैसे देखा जाए तो अपनों और गैरों की जासूसी कराना कोई नई बात नहीं है। शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसकी जासूसी करने की कोई औपचारिक संस्था न हो। देश के अंदर भी आंतरिक सुरक्षा का आंकलन

करने के लिए जासूस सक्रिय रहते हैं। यह काम खुफिया संस्थाएं करती हैं। इसके अलावा सादे कपड़ों में पुलिस को भी यह जिम्मेदारी दी जाती है। जबसे टेलीफोन का अविष्कार हुआ तभी से फोन टैपिंग का भी सिलसिला शुरू हो गया था। सिद्धि लोग, देश विरोधी तत्व, अपराधी और आतंकी तत्व फोन पर किससे क्या बात करते हैं,

अगर सरकारें फोन टैपिंग करके इसका पता न लगाएं तो वे अपने लोगों को सुरक्षित नहीं रख सकतीं। आज तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि बेहतर जासूसी करना आसान होता जा रहा है। इसका प्रमाण पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर भी हैं। भारत में फोन टैपिंग और जासूसी कराने के आरोप सरकारों पर बराबर लगते रहे हैं। लेकिन पेगासस जासूसी मामले पर जिस तरह हंगामा हो रहा है, उससे एक बात तो तय है कि मामला गंभीर है।

भारत सहित दुनियाभर में पेगासस स्पाईवेयर चर्चा में हैं। इजराइल की सर्विलांस कंपनी एनएसओ ग्रुप के सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के फोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। 50 हजार नंबरों के एक बड़े डेटा बेस के लीक होने की पड़ताल द गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, द वायर, फ्रंटलाइन, रेडियो फ्रांस जैसे 16 मीडिया संस्थानों के पत्रकारों ने की। एनएसओ समूह की ओर से ये साफ कहा जा चुका है कि कंपनी अपने सॉफ्टवेयर अलग-अलग देश की सरकारों को ही बेचती है और इस सॉफ्टवेयर को अपराधियों और आतंकवादियों को ट्रैक करने के उद्देश्य से बनाया गया है। पेरिस के एक गैर-लाभकारी मीडिया संगठन फॉरबिडेन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल को 50 हजार फोन नंबरों का डेटा मिला और इन दोनों संस्थाओं ने दुनिया की 16 मीडिया संस्थानों के साथ मिलकर रिपोर्टों का एक समूह बनाया जिसने इस डेटा बेस के नंबरों की पड़ताल की। इस पड़ताल को पेगासस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है।

जासूसी तो होती है, लेकिन ऐसी नहीं

सरकारी जासूसी का जैसा रहस्योद्घाटन इस बार हुआ है, स्वतंत्र भारत में शायद पहले कभी नहीं हुआ। वैसे, दुनिया की कोई सरकार ऐसी नहीं, जो जासूसी का पूरा तंत्र न चलाती हो, लेकिन लोकतंत्र में जासूसी भी कुछ कानून-कायदों के मुताबिक चलती है। उसे कुछ मर्यादाओं का पालन करना होता है। इस बार हमारी संसद में सरकारी जासूसी का ऐसा मामला उठा है, जिसके कारण सरकार की मुश्किल बढ़ी है। संसद में विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पेगासस की सूची में 300 भारतीयों के नाम हैं। इनमें 40 पत्रकार, दो केंद्रीय मंत्री, तीन विरोधी नेता, एक पूर्व न्यायाधीश, एक पूर्व चुनाव आयुक्त और कई



एनएसओ ने क्यों बनाया पेगासस ?

इजरायल की कंपनी एनएसओ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम करती है। दुनिया में बढ़ते अपराध और आतंकवाद को देखते हुए कंपनी ने इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाने पर विचार किया जो अपराधियों को पकड़ने में खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों की मदद करे। इसे ध्यान में रखते हुए कंपनी ने पेगासस सॉफ्टवेयर तैयार किया। कंपनी अपना यह एप्लीकेशन सम्प्रभु देशों को बेचती है। किसी निजी व्यक्ति के हाथ में यह सॉफ्टवेयर नहीं आता। कंपनी अपने इस सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के लिए भारी मात्रा में पैसे लेती है। पेगासस आईओएस और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर सकता है। एप्पल अपनी डाटा की सुरक्षा के लिए जानी जाती है लेकिन इस एप्लीकेशन ने उसमें भी संघ लगा दी। बाद में एप्पल ने अपने डिवाइसों की खामियों को दूर किया। बताया जाता है कि यह आईपैड और आईफोन को भी हैक कर सकता है। यह फोन के कैमरा और माइक्रोफोन को भी ऑन कर सकता है। एनएसओ अपने इस सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के लिए सलाना सरकारों से 50 से 60 करोड़ रुपए लेती है। यह एप्लीकेशन एक बार डाउनलोड हो जाने के बाद हजारों मील दूर बैठा व्यक्ति आपके फोन को एक्सेस कर सकता है। पेगासस आपके फोन की पूरी सूचना बाहर भेज सकता है। वह आपका पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट, मैसेज, लाइव वॉयस को हैक कर बाहर भेज सकता है। पेगासस के बारे में कहा जाता है कि यह इंक्रीप्टेड संदेशों को भी सुन और पढ़ सकता है। पेगासस एक ऐसा मॉलवेयर या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है जो आपके फोन में आकर आपकी निजी सूचनाओं, बातचीत और वीडियो को आपकी जानकारी के बगैर बाहर अपने हैंडलर को भेज देता है। इसे जासूसी का अब तक का सबसे बेहतर निजी सॉफ्टवेयर माना जा रहा है। फोन में इसे डिटेक्ट करना आसान नहीं होता।

अन्य व्यवसायों से जुड़े लोग भी हैं। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिससे सरकार को गैरों के साथ अपनों की भी जासूसी करवानी पड़ी।

जहां एक तरफ जासूसी मामले को लेकर संसद के दोनों सदन लगातार बाधित हो रहे हैं, वहीं सरकार ने पूरे मामले को निराधार बताया है। विपक्ष के हमलावर रुख के बाद भी सरकार यही कह रही है कि उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं और उसने किसी की जासूसी नहीं की। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस मामले को एक अंतरराष्ट्रीय साजिश करार देते हुए कहा कि इसका मकसद प्रस्तावित डाटा सुरक्षा विधेयक को कानून बनने से रोकना है। सवाल है कि पेगासस नामक उड़न घोड़ा देश को कहां लेकर जाएगा? ग्रीक मिथक के अनुसार पेगासस पंखों वाला एक सफेद घोड़ा है जो पलक झपकते ही यहां से वहां पहुंच सकता है। 21वीं सदी में पेगासस उस जासूसी के सॉफ्टवेयर का नाम है जो पलक झपकते ही हर सूचना को यहां से वहां पहुंचा सकता है। आज इसी पेगासस के चलते देश और दुनिया में हंगामा है।

2 साल पहले भी उठा था मामला

जब यह सवाल पहली बार 2019 में उठा, तब तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गोलमोल सा जवाब दिया था। वही जवाब वर्तमान मंत्री ने दोहरा दिया है। सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं, इस पर सरकारी प्रवक्ता चुप हैं। बस इतना कहते हैं कि कुछ भी अनधिकृत काम नहीं हुआ है। इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि हां, हमने पेगासस खरीदा और जासूसी करवाई लेकिन कागज पर अनुमति दर्ज करके। यह अनुमति किसने और कब दी, इस पर भी सरकार चुप है। मतलब कि दाल में काला है। हर कोई जानता है कि सरकार विदेशों ही नहीं, देश में भी जासूसी करवाती है, सिर्फ विदेशी या अपराधिक तत्वों



पूरी दुनिया पर जासूसी कर सकता है पेगासस

दुनियाभर की सरकारों द्वारा 50 देशों में 50,000 से अधिक लोगों की लंबी सूची की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इजरायली फर्म एनएसओ की सैन्य-ग्रेड पेगासस स्पाईवेयर पर भारत सहित विश्वभर में हंगामा मचा हुआ है। पेगासस एक मेलवेयर है जो आईफोन और एंड्रॉइड उपकरणों को प्रभावित करता है। यह अपने उपयोगकर्ताओं को संदेश, फोटो और ईमेल, कॉल रिकॉर्ड करने और माइक्रोफोन सक्रिय करने की अनुमति देता है। देशभर में 189 पत्रकारों, 600 से अधिक राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों और 60 से अधिक व्यावसायिक अधिकारियों को एनएसओ समूह के क्लाइंट द्वारा लक्षित किया गया था, जिसका मुख्यालय इजराइल में है। यह एक खतरनाक सॉफ्टवेयर है। यह लगभग पूरी दुनिया की आबादी पर जासूसी कर सकता है। ऐसी प्रौद्योगिकियों के निर्माण में कुछ भी गलत नहीं है जो आपको डेटा एकत्र करने की अनुमति देती हैं। यह कभी-कभी आवश्यक होता है। लेकिन मानवता ऐसी जगह पर नहीं है जहां हमारे पास इतनी शक्ति हो जो किसी के लिए भी सुलभ हो। अगर हम सॉफ्टवेयर कंपनियों और सरकारों से अपने स्वामित्व अधिकार वापस नहीं लेते हैं, तो हम डिजिटल दास बन जाएंगे। वे न केवल हमारे स्मार्ट उपकरणों, हमारे घरों, हमारी कारों और यहां तक कि हमारे अपने सॉफ्टवेयर-सक्षम चिकित्सा प्रत्यारोपण का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम होंगे। इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने विशेष रूप से संघीय व्यापार आयोग से तकनीकी दिग्गजों द्वारा निगरानी और एल्गोरिदम के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के डेटा के उनके संचय पर नए नियम बनाने के लिए कहा था। यह पहली बार है कि बाइडन व्हाइट हाउस ने बिग टेक के बाहरी प्रभाव पर लगाम लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय दृष्टिकोण पर अपनी आधिकारिक मुहर लगाई।

पर ही नहीं, अपने राजनीतिक विरोधियों के बारे में भी सूचना इकट्ठी करवाती है। इंदिरा गांधी के समय से इंटेलेजेंस ब्यूरो और रॉ इन कामों के लिए बदनाम रही हैं। अशोक गहलोत ने सरकारी जासूसों का इस्तेमाल सचिन पायलट पर निगाह रखने के लिए किया था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी और उनके गृहमंत्री अमित शाह का नाम भी जासूसी कांड में आया था। यह सब गैरकानूनी है, लेकिन ऐसा होता आया है। तो फिर पेगासस जासूसी कांड में ऐसा क्या खास है, जिस पर हमें विशेष चिंता करनी चाहिए? एक तो इसलिए कि पेगासस की जासूसी कोई सामान्य किस्म की नहीं है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए सरकार सिर्फ आपके फोन कॉल ही नहीं सुन सकती, बल्कि आपके फोन पर रखी तमाम सामग्री देख और रिकॉर्ड कर सकती है। सामान्य कॉल ही नहीं, व्हाट्सएप और सिग्नल के कॉल भी सुन सकती है, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट आपके फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकती है। मतलब आपके सार्वजनिक और निजी जीवन की

पल-पल की जानकारी यह सॉफ्टवेयर रख सकता है।

विशेष चिंता की दूसरी बात यह है कि इस जासूसी के घेरे में अब एक बहुत बड़ा दायरा आ गया है। अब तक जो नाम सामने आए हैं उनमें 40 से अधिक पत्रकार हैं, अधिकांश वे लोग जो सरकार के गलत कामों पर पैनी निगाह रखते हैं। इस सूची में पूर्व चुनाव आयुक्त लवासा का नाम है जो पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा की मर्यादा उल्लंघन पर सवाल उठा रहे थे। और तो और, इस सूची में सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश का नाम है और उस महिला के परिवार के 11 लोगों के भी, जिसने जस्टिस गोगोई पर यौन प्रताड़ना के आरोप लगाए थे।

साइबर सुरक्षा का इजराइली खेल

भारत में पेगासस जासूसी कांड को साइबर सुरक्षा का इजराइली खेल माना जा रहा है। दरअसल, 14 से 19 जनवरी 2018 की राजकीय यात्रा पर बिन्जामिन नेतन्याहू भारत आए थे। जो आर्थिक

डेलीगेशन उनके साथ भारत आया था, उसकी कुल संख्या 147 थी। इनमें जल, कृषि, खाद्य, साइबर सुरक्षा, होमलैंड सिक््योरिटी, डिफेंस, सॉफ्टवेयर, आईटी के प्रतिनिधियों के अलावा 20 स्टार्टअप वाले लोग शामिल थे। बराक ओबामा या ट्रंप भी इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर कभी भारत नहीं आए। 147 इजराइली प्रतिनिधियों की सूची किसी पत्रकार को हासिल नहीं थी। इसलिए यह कहना कठिन है कि उस शिष्टमंडल में एनएसओ ग्रुप के प्रतिनिधि थे या नहीं। यह भी बताया नहीं जा सकता कि 15 जनवरी 2018 को उभयपक्षीय सरकारों के बीच बिजनेस और इंडस्ट्री से जुड़े जो 9 समझौते तत्कालीन प्रधानमंत्री नेतन्याहू की उपस्थिति में हुए, उसमें पेगासस स्पाईवेयर की डील हुई थी या नहीं? 2018 में दोनों सरकारों के बीच साइबर सुरक्षा में सहयोग को लेकर हस्ताक्षर करने वालों में भारत की ओर से विजय कृष्ण गोखले और इजराइल की तरफ से विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल युवाल रोटेम थे। 2020 में रोटेम रिटायर हो गए। इससे पहले फरवरी 2014 में होमलैंड एंड पब्लिक सिक््योरिटी को लेकर इजराइल से एक समझौता हुआ था। उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बेहतर बता सकते हैं कि किसी और इजराइली स्पाईवेयर की एंट्री भारत में हुई थी, या नहीं। एक तीसरा समझौता जुलाई 2020 में इजराइल से हुआ, एमओयू के दस्तावेज पर लिखा है, 'ऑपरेशनल कोलाबोरेशन ऑन साइबर सिक््योरिटी।' दोनों सरकारें चुप हैं, चुनावों के मुश्किल है कि एनएसओ ग्रुप के तकनीशियन पेगासस स्पाईवेयर को ऑपरेशनल करने के वास्ते प्रशिक्षण देने भारत कब आए। निश्चित रूप से साइबर सुरक्षा पर जो तीसरा समझौता 16 जुलाई 2020 को हुआ था, उससे बहुत पहले पेगासस भारत में इंस्टाल हो चुका था। विपक्ष का आरोप है कि जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजराइल गए थे, तब साइबर सुरक्षा को लेकर व्यापक रूपरेखा बनी थी। भारत, 2019 तक साइबर सुरक्षा को गति देने के वास्ते कई प्रतिनिधिमंडलों को इजराइल भेज चुका था।

कोरोना के इस कालखंड में ई-कॉमर्स, ई-लर्निंग, टेली-मेडिसीन, वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्किंग पर लोगों की निर्भरता जिस तरह से बढ़ चली है, सरकार के लिए उसकी सुरक्षा और निगरानी का काम भी कई गुना बढ़ा है। इसलिए यह कहना कि साइबर चौकसी के जो उपकरण ड्रग माफिया या अतिवादी गतिविधियों में संलग्न लोगों पर नजर रखने के वास्ते खरीदे जा रहे हैं, सप्लायर देशों को कहीं न कहीं भ्रमित करने जैसा है। भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में निगरानी का दायरा निश्चित रूप से बढ़ना है। विषय साइबर चौकसी के दुरुपयोग का है, जिसे लेकर संसद से सोशल मीडिया तक बहस में मुब्तला है।

खेल कमाई का

बाहरी दुनिया के विश्लेषक यह मानकर चलते रहे कि जिन देशों से इजराइल वैचारिक और कूटनीतिक रूप से संबद्ध नहीं है, उनसे वह दूर ही रहता है। यह बात साइबर व्यापार में बिलकुल उल्टी साबित हुई है। उदाहरण के लिए इजराइल ने पेगासस सऊदी अरब, यूएई मोरक्को, कजाकस्तान, अजरबैजान, इथियोपिया, बहरीन, बांग्लादेश जैसे मुस्लिम बहुल देशों को बेचे, जबकि बाहर से ये देश फिलस्तीन समर्थक दिखते थे। मगर, इनके शासकों को अपने यहां जम्हूरियत और विचारों की स्वतंत्रता को कुचलना था, तो पेगासस जैसा उपकरण इजराइल से ही प्राप्त हो सकता था।

इजराइल सरकार से जब सौदा होता है, तो पेपर वर्क में बाकायदा इसका उल्लेख होता है कि होम सिक्वोरिटी, साइबर निगरानी, अतिवाद व नशे के कारोबार को नियंत्रित करने के वास्ते पेगासस स्पॉन्सर्स के आयात किए जाएंगे। मगर, क्या सचमुच ऐसा हुआ है? मोजाबिक, अंगोला, इथियोपिया, साउथ सूडान, वोस्तवाना, नाइजीरिया, युगांडा जैसे देशों में प्रतिरोध करने वाले लोगों का जिस तरह दमन हुआ है, वह तकनीक के दुरुपयोग का जीता-जागता उदाहरण है। सरकारें एमओयू का पालन बिलकुल नहीं करतीं। पेगासस की निर्माता कंपनी एनएसओ फिर वही बयान दोहराती है कि हम सरकारों से सौदा करते नहीं, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तय करने की बात इजराइली सुप्रीम कोर्ट तक गई। तब जज का निष्कर्ष था, 'राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के मामले में सरकार और सेना को कठघरे में लाना, उसकी जिम्मेदारी तय करना सही नहीं।' फिर तो पेगासस का घोड़ा पूरी दुनिया में तेजी से दौड़ने लगा!

पेगासस हमारा वाटरगेट कांड!

विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, केंद्रीय मंत्रियों, एक्टीविस्ट जैसे लगता है पेगासस की भेदिया नजर से कोई नहीं बचा, क्या यह अमेरिका के वाटरगेट या उससे भी बड़ा कांड है? इसका नतीजा क्या होगा? यह भारत में वाटरगेट कांड जैसी बड़ी घटना, बल्कि उससे भी बड़ी हो सकती है। धीरे-धीरे खुल रहे 'पेगासस प्रोजेक्ट' में एक हजार से ज्यादा फोन नंबर सामने आ चुके हैं। ये फोन नंबर इजराइली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के निशाने पर थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री, सत्तारूढ़ और विपक्षी दल के नेता, एक्टीविस्ट, पत्रकार, न्यायाधीश और गैर-सरकारी संगठन, किसी को भी बख्शा नहीं गया।

इस जासूसी विवाद ने संसद के मानसून सत्र को हंगामेदार बना दिया है। विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार पर तथाकथित फोन हैकिंग का आरोप लगाते हुए हल्ला बोला है। इस जासूसी



मोदी सरकार की कई नाकामियों को नहीं भुना सकी कांग्रेस

पेगासस विवाद से लेकर कोरोना महामारी में बदइंतजामी और किसान आंदोलन तक कांग्रेस ने एक के बाद एक तमाम मुद्दों को संसद के मानसून सत्र में उठाकर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा करते हुए इस पार्टी ने उजागर कर दिया है कि आज उसकी सबसे बड़ी समस्या एक ऐसा मुद्दा उछालने में उसकी असमर्थता है, जो कारगर हो जाए, जमीनी स्तर गूँज पैदा करे और मोदी तथा भाजपा की छवि को चोट पहुंचा सके। एक क्षण के लिए भाजपा को विपक्ष में खड़ा कर दीजिए और निम्नलिखित मुद्दे उसकी झोली में डाल दीजिए— रक्षा सौदे में अनियमितता का संदेह, सिकुड़ती अर्थव्यवस्था, किसानों में असंतोष, मानवीय त्रासदी, सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में बदइंतजामी, ईंधन की कीमतों में वृद्धि और जासूसी कांड। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह थाली में परोसे इन मुद्दों का क्या करेंगे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन मानो नीम बेहोशी में पड़ी कांग्रेस पार्टी कोशिश करके भी इन मुद्दों को विजयी चुनावी राजनीति में बदल नहीं पा रही है। यहां तक कि संसद भवन तक की ट्रैक्टर यात्रा भी उसे गति नहीं दे पा रही है। 2013 में राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के उत्कर्ष के बाद से ही यह कांग्रेस और उसके नेतृत्व के लिए एक स्थायी समस्या रही है। पार्टी कई विफल तरीके आजमा चुकी है— 'सूट-बूट की सरकार', 'चौकीदार चोर है', 'मोदी के घड़ियाली आंसू' जैसे नारे आजमाने से लेकर बड़े गठबंधन तक कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस वह फॉर्मूला नहीं तैयार कर सकी है जो मोदी को परास्त कर सके, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तैयार करने में सफल रहे हैं।

कांड के राजनीतिक निहितार्थ बड़े हो सकते हैं। पेगासस प्रोजेक्ट ने वाटरगेट स्कैंडल की याद दिला दी है। उस स्कैंडल ने अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। आरोप था कि उन्होंने 1972 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस की टैपिंग करवाई थी। ठीक उसी तरह, राहुल गांधी को टारगेट पर रखा गया था। राहुल 2019 के लोकसभा चुनाव में अध्यक्ष के तौर पर पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। 2018-19 में राहुल गांधी के फोन को दो बार टारगेट बनाया गया। उनके कम से कम पांच करीबियों और कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के फोन भी निशाने पर थे। राहुल गांधी अब वह पुराना फोन इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए उसकी फॉरेंसिक जांच नहीं की गई। उनके दो करीबी अलंकार सवाई और सचिन राव भी लीक हुए फोन नंबरों की सूची में हैं।

आतंकवाद रोकना है मकसद

नए-नए नाम रोज प्रकट होते जा रहे हैं। एनएसओ ने दावा किया है कि वह अपना सॉफ्टवेयर सिर्फ प्रामाणिक सरकारों को बेचती है ताकि वे आतंकवादियों, संगीन अपराधियों, तस्करों और विदेशी जासूसों पर निगरानी रख सकें। भारत में जितने बड़े पैमाने पर जासूसी की बात सामने आई है, उसके मद्देनजर कहा जा रहा है कि खरीदी गई पेगासस की कीमत लगभग 500 करोड़ रूपए होगी। क्या कोई गैर-सरकारी संस्था इस यंत्र पर इतना पैसा खर्च करेगी? भारत सरकार की ओर से इन आरोपों का जवाब देने की जिम्मेदारी आई नव-नियुक्त सूचना तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव पर! दिलचस्प बात यह है कि खुद वैष्णव का नाम भी उस सूची में है, जिनकी कथित तौर पर जासूसी हो रही थी। वैष्णव ने दो-टूक शब्दों में कहा है कि अवैध जासूसी की यह खबर निराधार है। भारत सरकार जासूसी का कोई भी गैर-कानूनी काम नहीं करती।

देश में अब तक के बड़े जासूसी मामले

1969 इंदिरा गांधी बनाम सिडिकेट



वर्ष 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने कांग्रेस आई नामक अलग पार्टी बना ली। के कामराज की अगुवाई में कांग्रेस (संगठन) बनी, जो सिडिकेट के नाम से चर्चित हुई। कामराज, मोरारजी देसाई, एस निजलिंगाया और हितेंद्र देसाई जैसे सिडिकेट नेता लगातार यह शिकायत करते रहे कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उनके फोन टैप कर रही है। इमरजेंसी का दौर 1975-77 विभिन्न नेताओं, पत्रकारों और सिविल सोसायटी के सदस्यों के हवाले से पता चलता है कि इंदिरा गांधी ने उस समय न केवल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों, बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं का भी फोन टैप कराया और दूसरे तरीकों से जासूसी कराई।

एमके धर का खुलासा

2005 इंटरनेट जैस ब्यूरो के पूर्व संयुक्त निवेशक विदगंत मलय कृष्णा धर ने 2005 में प्रकाशित अपनी किताब ओपन सीक्रेट्स इंडियाज इंटरनेट जैस अनवील्ड में इंदिरा गांधी पर आरोप मढ़ा कि वे अमूमन अवैध फोन टैपिंग की इजाजत देने वाली देश की पहली नेता थीं। धर ने पुस्तक में यह भी दावा किया कि 1982 में मेनका गांधी घर छोड़कर गई तो तुरंत बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी और उनकी मां अमृतेश्वर आनंद के फोन टैप करने का आदेश दिया। धर का यह भी दावा है कि जिन अन्य लोगों के फोन इंदिरा के निर्देश पर कई बार टैप किए गए, उनमें गृहमंत्री ज्ञानी जैल सिंह भी थे। धर की किताब में यह भी दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी इंटरनेट जैस ब्यूरो को राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जासूसी करने का आदेश दिया था। धर के मुताबिक, राष्ट्रपति भवन में भी जासूसी के लिए छोटे-छोटे उपकरण लगा दिए गए थे। धर का दावा है कि जैल सिंह राष्ट्रपति भवन के बगीचे में नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों से मिलने पर हमेशा जोर देते थे।

1980 के दशक में कर्नाटक



रामकृष्ण हेगड़े बनाम गुई राव जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को 1988 में एचडी देवेगौड़ा, अजित सिंह और वीरमा मोइली सहित 50 से अधिक नेताजी के टेलीफोन अवैध रूप से टैप करने के आरोप लगने के बाद पद छोड़ने पर मजबूर किया गया। इससे पहले आर मुहुराव के नेतृत्व वाली राज्य की कांग्रेस सरकार पर भी एस बगरमा और देवराज भई जैसे राजनीतिक दिग्गजों की अवैध रूप से जासूसी करने के आरोप लगे थे।

2006 सोनिया गांधी बनाम अमर सिंह



जनवरी 2006 में उग्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने आरोप लगाया कि उनके करीबी सहयोगी अमर सिंह के फोन कांग्रेस और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के कहने पर टैप किए जा रहे हैं। इसके बाद तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने भी यह दावा किया कि उनके फोन भी अवैध रूप से टैप किए गए।



1990 वीपी सिंह बनाम चंद्रशेखर

वीपी सिंह की जगह प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीने पहले चंद्रशेखर ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार 28 अन्य नेताओं के साथ उनका फोन अवैध रूप से टैप कर रही है। हालांकि वीपी सिंह ने आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए और उससे निष्कर्ष निकला कि चंद्रशेखर का कोई भी फोन टैप नहीं किया गया था। सीबीआई जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि राजीव गांधी सरकार में कई नेताओं के फोन टैप किए थे। उनमें कई उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे। पूर्व मुख्यमंत्रियों एआर अंतुले चिमनभाई पटेल और एम करुणानिधि के फोन भी टैप किए गए थे।



1991 चंद्रशेखर बनाम राजीव गांधी



वीपी सिंह पर अवैध फोन टैपिंग के आरोप लगाने के कुछ महीने बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। करीब 4 महीने के बाद उन पर राजीव गांधी की जासूसी करने का आरोप लगा। कांग्रेस चंद्रशेखर की सरकार का बाहर से समर्थन कर रही थी। उसने आरोप लगाया कि हरियाणा के दो पुलिसवालों को राजीव गांधी के 10 जनपथ आवास के पास पकड़ा गया और उनकी जासूसी करने के लिए गए थे। इस प्रकरण के कुछ ही दिनों बाद चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

2010 एनटीआरओ जासूसी घोटाला

अप्रैल 2010 में यूपीए सरकार फिर घिर गई कि कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माकपा महासचिव प्रकाश करात और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार सहित अन्य के मोबाइल फोन अवैध रूप से टैप किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार फोन टैपिंग कथित तौर पर राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ ने की थी।

नीरा राडिया टैप 2010

कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया की तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ए. राजा और कर्द अन्य नेताओं और प्रमुख पत्रकारों के साथ यूपीए-2 के दौर में कैबिनेट गठन से संबंधित लीक हुई टेलीफोनिक बातचीत देश के सबसे बड़े जासूसी घोटालों में से एक है। राडिया पर दयानिधि मारन की जगह राजा को दूरसंचार मंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पैरवी करने और कैबिनेट गठन के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगाया। राजा बाद में जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में मुख्य आरोपी बने। हालांकि बाद में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था।



प्रणब मुखर्जी, एके एंटनी, यशवंत सिन्हा और अरुण जेटली

यूपीए सरकार पर अवैध जासूसी के आरोप कई बार लगे। निसंदेह सबसे शर्मिंदगी का मामला तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से जुड़ा था। जून 2011 में मुखर्जी के नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में जासूसी उपकरण लगाए जाने की खबरों ने राजनीतिक भूचाल ला दिया। विपक्ष खासकर भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री के कार्यालय में गृहमंत्री पी चिदंबरम के कहने पर जासूसी उपकरण लगाए गए। इस मामले में मुखर्जी ने सीधे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा तो यूपीए सरकार के लिए यह मामला परेशानी का सबब बना। आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार चिदंबरम के गृह मंत्रालय को इस प्रकरण की जांच से बाहर रखा गया था। हालांकि जांच में यह बात बेमानी साबित हुई। 2012 में तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी के कार्यालय में जासूसी उपकरण की खबरें आईं। आईबी जांच में बात झूठ निकाली। उसी वर्ष तत्कालीन भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने चिदंबरम पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया। अगले वर्ष सरकार पर राज्यसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता अरुण जेटली की जासूसी करने के आरोप लगे।



...तो 350 साल बाद मिलेगा न्याय

देशभर की अदालतों में 4 करोड़ से अधिक केस लंबित

अ दालतों पर काम का दबाव लगातार बढ़ रहा है। हालत यह है कि देश के विभिन्न न्यायालयों में इस वक्त 4 करोड़ मामले लंबित हैं। पिछले 16 महीने से कोर्ट में सिर्फ अर्जेंट मामले सुने जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही लंबित मामलों का आंकड़ा 5 करोड़ को छू लेगा। जिस गति से न्यायालयों में प्रकरणों का निबटारा हो रहा है उस गति से जीरो पेंडेसी तक पहुंचने में 350 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। कोरोना संक्रमण की वजह से सिर्फ आम आदमी ही नहीं न्यायालय भी प्रभावित हुए हैं। पिछले 70 साल में किसी एक साल में सबसे ज्यादा लंबित मामलों में बढ़ोतरी महामारी के दौरान हुई है।

कानून के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था न्यायाश्रय द्वारा की गई एक रिसर्च में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस रिसर्च में नेशनल ज्यूडिशल डाटा ग्रिड द्वारा जारी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। संस्था अध्यक्ष एडवोकेट पंकज वाधवानी ने बताया कि विश्लेषण से पता चलता है कि आजादी के बाद पहली बार किसी एक साल में सबसे ज्यादा लंबित मामलों में बढ़ोतरी 2020-21 में हुई है। लंबित मामलों की संख्या में सर्वोच्च न्यायालय में 10.35 प्रतिशत, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 20.4 प्रतिशत और जिला न्यायालयों में 18.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी पिछले एक साल में हुई है। इसके पहले हमेशा यह 4 से 6 प्रतिशत के बीच रहती थी लेकिन महामारी की वजह से न्यायालयों में नियमित कामकाज नहीं

हुआ। इसके चलते प्रकरणों का निराकरण नहीं हुआ और लंबित मामलों की संख्या बढ़ गई। 8 मई 2021 तक देश की अदालतों में कुल 3,84,05,718 यानी करीब चार करोड़ मुकदमे लंबित हैं। वाधवानी ने बताया कि कोविड इफेक्ट आन इंडियन ज्यूडिशरी विषय पर हुए इस रिसर्च में पता चला है कि लॉकडाउन के पहले एक मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय में 60469 मामले लंबित थे जो एक मई 2021 को बढ़कर 67898 हो गए। मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक सुप्रीम कोर्ट में 52353 प्रकरणों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। इस अवधि में उच्च न्यायालयों में 20,60,318 और जिला न्यायालयों में 45,73,159 प्रकरण सुने गए। यह बात भी सामने आई है कि लंबित प्रकरणों की लगातार बढ़ रही संख्या के पीछे न्यायाधीशों की कमी भी एक बड़ी वजह है। देशभर में उच्च न्यायालयों के लिए जजों के 1080 पद स्वीकृत हैं लेकिन 661 ही पदस्थ हैं। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय में 34 स्वीकृत पदों के मुकाबले सिर्फ 30 जज पदस्थ हैं।

गौरतलब है कि देश में एक सर्वोच्च न्यायालय है। वहीं 25 उच्च न्यायालय हैं। इनके अलावा 19 हजार से अधिक अधीनस्थ न्यायालय हैं। इन न्यायालयों में प्रकरणों की भरमार है। 25 मार्च 2020 को देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या 3 करोड़ 68 लाख थी जो एक साल में बढ़कर 3 करोड़ 94 लाख हो गई। 25 मार्च 2020 को देश के उच्च न्यायालयों में 46.4 लाख प्रकरण लंबित थे जो 30 जून 2020 तक 48 लाख और 30 जनवरी 2021 तक 56.6

विभिन्न प्रदेशों में लंबित प्रकरणों की स्थिति

● उप्र	88,96,941
● महाराष्ट्र	47,37,559
● बिहार	32,63,819
● पश्चिम बंगाल	24,51,596
● गुजरात	21,19,728
● कर्नाटक	17,60,818
● राजस्थान	19,49,318
● केरल	19,19,144
● ओडिशा	14,26,758
● तमिलनाडु	12,83,921
● दिल्ली	10,29,449
● तेलंगाना	7,24,181
● पंजाब	8,71,382
● आंध्र प्रदेश	6,83,459
● झारखंड	4,66,461
● हिमाचल	4,26,614
● असम	3,65,655
● छत्तीसगढ़	3,52,004
● उत्तराखंड	2,75,895
● जम्मू-कश्मीर	2,32,438
● चंडीगढ़	62,253
● गोवा	58,959
● त्रिपुरा	38,242
● पुदुचेरी	23,260
● मणिपुर	11,761
● मेघालय	10,604
● नागालैंड	2,155
● सिक्किम	1,700
● दमन-दीव	2,857
● दादर नगर हवेली	3,472
● लद्दाख	810

लाख हो गए। इन लंबित मुकदमों की संख्या 30 अप्रैल 2021 तक लगभग 58 लाख पहुंच गई। यानी लॉकडाउन के दौरान उच्च न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या में साढ़े 11 लाख का इजाफा हुआ है। 2018 में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सुनवाई कर निपटारा करने में 350 साल लगने का अनुमान है। अगर मप्र की बात करें तो नेशनल ज्यूडिशल डाटा ग्रिड में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मप्र में वर्तमान में 17,68,734 मुकदमे लंबित हैं जिसमें से 3,74,750 दीवानी और 13,93,484 आपराधिक क्रिम के हैं। यही हाल देश के अन्य राज्यों का है। कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में जिस गति से केसों का निपटारा हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 300 साल में न्याय मिल जाएगा।

● कुमार विनोद

मंत्रिमंडल का विस्तार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल संतुलन साधने की कोशिश की है, बल्कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी जमावट की है। मंत्रिमंडल में जो युवा चेहरे शामिल किए गए हैं, वे प्रदेशों के भावी मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मंत्री पद उनके लिए सीएम का टिकट है।

केंद्र में भावी मुख्यमंत्रियों वाली कैबिनेट



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में जो अपनी नई टीम चुनी है, सबसे युवा मंत्रिमंडल के तौर पर देखा जा रहा है। युवा होने का मतलब ऊर्जावान होना और लंबी पारी के लिए तैयार रहना भी होता है और ये टीम बेहद सधी रणनीति और दूरगामी सोच के साथ तैयार की गई है। भविष्य की राजनीति की राह कैसी होगी और कैसे समीकरण बनेंगे, ये सब बाद की बात है, लेकिन अभी तो नई टीम के सामने कम से कम तीन साल हैं ही काम करने के लिए। और ये परफॉर्म करने के लिए ये कोई कम वक्त भी नहीं होता। ये टीम इस दौरान जो भी काम करेगी, वही उनके आगे के भविष्य की दशा और दिशा भी तय करने वाला है।

सर्बानंद सोनवाल और हिमंत बिस्वा सरमा मौजूदा दौर की भाजपा में ऐसे दो मिसाल हैं, जिन्हें नए नेता अपने रोल मॉडल समझकर अपना प्यूचर प्लान कर सकते हैं। सर्बानंद सोनवाल 5 साल बाद फिर से मंत्री बन गए हैं। 2016 में हुए असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सर्बानंद सोनवाल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था और हिमंत बिस्वा सरमा को कांग्रेस से झपट लेने के बाद सर्बानंद सोनवाल के नेतृत्व में असम में भाजपा की सरकार बनी भी और पूरे कार्यकाल चली भी। हाल के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा सर्बानंद सोनवाल के चेहरे के साथ ही चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक ऐसा फैसला लिया जो भाजपा को लेकर मिथक तोड़ने वाला रहा। हिमंत बिस्वा सरमा को असम का मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने उस धारणा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि ऐसे पद

सिंधिया दमदार

ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरीके से भाजपा में आने के दिन से ही हाथोंहाथ लिया जा रहा है, लगता नहीं कि भाजपा नेतृत्व ने उनके लिए कोई हद बना रखी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाजपा नेतृत्व की अपेक्षाओं पर अब तक खरे ही उतरते आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न सिर्फ मप्र में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार की विदायी की, बल्कि साथ आए ज्यादातर विधायकों को उपचुनाव भी जिता दिया। अपने समर्थक विधायकों को मंत्री तो वो पहले ही बनवा चुके थे। आज भी शिवराज सिंह चौहान सरकार में ज्यादा दबदबा ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही नजर आता है। शिवराज सिंह चौहान को भी भाजपा में वाजपेयी-आडवाणी युग का ही नेता माना जाता है। जिस तरह से मोदी सरकार से पुराने नेताओं की विदायी होती जा रही है, शिवराज सिंह चौहान भी कुर्सी पर तभी तक कायम हैं जब तक भाजपा को उनका विकल्प नहीं मिल जाता। हिमंत बिस्वा सरमा को असम का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद जिन लोगों को सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी उनमें से एक सिंधिया भी निश्चित रूप से होंगे। मप्र में मुख्यमंत्री बनने का सपना तो उनके पिता माधवराव सिंधिया का भी अधूरा रह गया, लेकिन लगता है पिता के साथ-साथ उनको अपना सपना पूरा करने में थोड़ी देर भले हो लेकिन अधेर नहीं है।

भाजपा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि वालों को ही मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस फैसले ने दूसरे दलों से भाजपा में आने वाले नेताओं को बड़ी उम्मीदों से भर दिया है और यही वजह है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मप्र में वो सपना पूरे होते देख रहे होंगे जो कांग्रेस में रहने मुमकिन नहीं होने वाला था। जितिन प्रसाद जैसे नेताओं को भी निराश होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए या फिर सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा जैसे नेताओं को भी भाजपा में अपना उज्वल भविष्य देखने को सिर्फ हवाई किला समझने की जरूरत नहीं है।

अगर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सर्बानंद सोनवाल की तरह केंद्रीय कैबिनेट में जगह बना चुके हैं तो भविष्य में वो भी हिमंत बिस्वा सरमा की तरह मप्र के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं और अगर ऐसा वो सोचते हैं तो कोई उनको गलत भी नहीं समझेगा। सिंधिया की ही तरह अनुराग ठाकुर से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नए मंत्रिमंडल में मीनाक्षी लेखी और अन्नपूर्णा देवी जैसी नेताओं के लिए भी आने वाले दिनों में ऐसी संभावना बन सकती है, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए।

प्रकाश जावड़ेकर जैसे सीनियर भाजपा नेता को कैबिनेट से हटाने के बाद अनुराग ठाकुर को प्रमोशन देकर सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया है। जावड़ेकर को हटाए जाने की जो वजहें समझी जा रही हैं, उस हिसाब से देखें तो अनुराग ठाकुर को मोदी कैबिनेट में अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली हुई है और ये चीज एक बात समझने के लिए काफी है कि अनुराग ठाकुर का

भाजपा में कैसा रुतबा है। हिमाचल प्रदेश से आने वाले नई जिम्मेदारी मिलने से पहले तक अनुराग ठाकुर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विभाग में राज्य मंत्री हुआ करते थे। बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके अनुराग ठाकुर के पास ही खेल और युवा मामलों की भी जिम्मेदारी है।

अनुराग ठाकुर का एक और परिचय ये है कि वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। प्रेम कुमार धूमल को 2017 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। तब खबर ये भी आई थी कि ऐसा अमित शाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन धूमल ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ पुराने रिश्तों के बल पर अपनी मांग पूरी करा ली, लेकिन वो भी कोई मुख्यमंत्री बनने की गारंटी तो थी नहीं।

पिछले साल जम्मू-कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव में भाजपा में जिन तीन नेताओं को जिम्मेदारी मिली थी, अनुराग ठाकुर भी उनमें से एक थे। डीडीसी चुनाव की जिम्मेदारी अच्छी तरह संभालने के बाद जिस तरह **नेपथ्य** में चल रहे सैय्यद शाहनवाज हुसैन को बिहार भेजा गया है, अनुराग ठाकुर भी उसी पथ के राही लगते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान अनुराग ठाकुर की गिनती भाजपा के फायरब्रांड नेताओं में होने लगी थी। जैसे जोशीले भाषण मोदी-शाह को पसंद आते हैं, अनुराग ठाकुर ने अपनी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। बंगाल चुनाव में भी अनुराग ठाकुर खासे एक्टिव रहे और मोदी-शाह-नड्डा की तरह ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी लगातार उनके निशाने पर बने रहे। हिमाचल प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव 2022 में ही होने वाला है और अगर अभी भाजपा का मन जयराम ठाकुर से नहीं भरा, तो आगे चलकर कभी भी अनुराग ठाकुर आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं।

झारखंड से आने वाली अन्नपूर्णा देवी पहली बार 2019 में संसद पहुंचीं। कभी लालू प्रसाद की बेहद करीबी नेता समझी जाने वाली अन्नपूर्णा देवी आम चुनाव से पहले ही भाजपा में आई थीं, और अब मोदी कैबिनेट में शामिल हो चुकी हैं। अन्नपूर्णा देवी के भी झारखंड के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्ता में वापसी के लिए भाजपा को अन्नपूर्णा देवी जैसी ही एक नेता की जरूरत है और वो रघुबरदास की उत्तराधिकारी निश्चित तौर पर हो सकती हैं। 2019 में सत्ता गंवाने के बाद से ही भाजपा नेतृत्व ने रघुबरदास को लेकर मुंह मोड़ लेने जैसा व्यवहार किया। रघुबरदास को न तो प्रदेश भाजपा की कमान दी गई और न ही विधानमंडल दल का नेता बनाया गया। और अब भी भाजपा को झारखंड में एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो अगले चुनाव में हेमंत सोरेन को चैलेंज कर



मनसुख मंडाविया को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना बड़ा संदेश

मनसुख मंडाविया को कोरोना संकट काल में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दिया जाना सिर्फ महत्वपूर्ण या चुनौतीपूर्ण ही नहीं है, बल्कि अपेक्षाएं भी अपार हैं। कोविड-19 के कहर के दौरान बदइंतजामी और तमाम नाकामियों के लिए ही डॉ. हर्षवर्धन की स्वास्थ्य मंत्रालय से छुट्टी कर दी गई, ऐसा समझा गया है। मंडाविया को भी प्रमोशन देकर कैबिनेट दर्जा दिया गया है और माना जाता है कि ये कोरोनाकाल में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के तौर पर किए गए काम का ईनाम भी है। मंडाविया ने जब देखा कि जरूरी दवाओं की किल्लत हो रही है, तो आगे बढ़कर दवा निर्माता कंपनियों से खुद संपर्क किया और सुनिश्चित किया कि तेजी से दवाएं बनाई जा सकें। कैबिनेट मंत्री के तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ-साथ मंडाविया के पास ही केमिकल एंड फर्टिलाइजर की भी जिम्मेदारी आ चुकी है। दरअसल, दवाएं बनाने का काम केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय के पास होता और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय का काम शुरू होता है। आगे से कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत न आए, ये सोचकर दोनों मंत्रालयों की जिम्मेदारी मंडाविया को दी गई है और ये बात ही मोदी-शाह की नजर में उनकी अहमियत का सबूत भी है।

सके। सुदेश महतो के साथ भाजपा का गठबंधन तो चुनावों के दौरान ही टूट गया था। बाद में बाबूलाल मरांडी भी भाजपा में लौट आए, लेकिन लगता नहीं कि भाजपा की अगली बार मरांडी या अर्जुन मुंडा को आगे करने की कोई योजना होगी। ऐसे में उम्मीद की किरण अन्नपूर्णा देवी पर जाकर ही ठहर रही है।

2019 में झारखंड और उसके ठीक बाद 2020 के शुरू में दिल्ली विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख दिल्ली भाजपा को लेकर ही प्रकाशित हुआ था, लेख में दिल्ली भाजपा को साफ शब्दों में समझाने की कोशिश थी कि वे नई लीडरशिप तैयार करें क्योंकि हर चुनाव में जीत के लिए मोदी-शाह के भरोसे रहना ठीक नहीं है और ऐसा वे बार-बार कर भी नहीं सकते। दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों की आबादी और वोट बैंक के मद्देनजर ही मनोज तिवारी को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन विधानसभा चुनावों के दौरान ही महसूस होने लगा था कि भाजपा नेतृत्व ने हटाय़ा भले न हो लेकिन ढो ही रहा है। ऐसा तब साफ हो गया जब अमित शाह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से ही दूसरे सांसद प्रवेश वर्मा से बहस करने की चुनौती दे डाली।

बहरहाल, चुनाव बाद मनोज तिवारी को हटा भी दिया गया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष बनने की उम्मीद में प्रवेश वर्मा भी रहे क्योंकि अनुराग ठाकुर की तरह चुनावों के दौरान उनके बयान भी

विवादित रहे और खूब सुर्खियां बटोरे थे। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही भाजपा को दिल्ली में एक ऐसे चेहरे की जरूरत महसूस हो रही है जो अरविंद केजरीवाल को सीधे-सीधे टक्कर दे सके। वैसे भाजपा नेतृत्व ये भूल गया कि जब दुनियाभर में शोहरत हासिल करके अरविंद केजरीवाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था, तो भी डॉ. हर्षवर्धन ने भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें दिलाई थीं। 2015 के दिल्ली चुनाव में भाजपा ने किरण बेदी को आजमाया, लेकिन सारी कवायद बेकार गई। 2020 में अमित शाह ने भाजपा को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया लेकिन नाकाम रहे। अब भाजपा को दिल्ली में जैसे नेता की जरूरत है, मीनाक्षी लेखी एक दावेदार तो हैं ही।

मीनाक्षी लेखी के बारे में भी खबर रही कि 2019 में उनका टिकट कट सकता है, लेकिन तभी वो सुप्रीम कोर्ट चली गईं और उनकी याचिका दायर करने के बाद ही राहुल गांधी को राफेल के मुद्दे पर अदालत से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। मीनाक्षी लेखी का टिकट तो बरकरार रहा ही, अब मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा या दूसरे नेताओं को दरकिनार कर जिस तरीके से मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है, मीनाक्षी लेखी आने वाले दिनों में दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा का चेहरा बनती हैं तो कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए।

● इन्द्र कुमार

‘जो आरजेडी-कांग्रेस न कर पाई वो ममता बनर्जी ने किया और जो एनसीपी-कांग्रेस-शिवसेना ने मिलकर किया, वो ममता बनर्जी ने अकेले कर दिखाया। पश्चिम बंगाल में भाजपा को हराकर तीसरी बार सत्ता को हासिल कर लिया। शायद यही वजह है कि देश की राजनीति के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में स्थापित हो चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ममता बनर्जी का नाम लिया जाने लगा है। विरोधी खेमे को ममता में उम्मीद नजर आ रही है और विपक्ष भी ‘बंगाल की शेरनी’ के इर्द-गिर्द नजर आ रहा है।’



ममता बनर्जी ने भी बंगाल से बाहर अपने सियासी प्लान का ट्रेलर जारी कर दिया है। 21 जुलाई को शहीद दिवस के मौके पर ममता का वचुंअल संबोधन हुआ। ममता ने इस दौरान विपक्षी एकजुटता का नारा बुलंद किया और 2024 में दिल्ली फतेह करने के लिए बिगुल फूंक दिया। भाजपा को देश से खदेड़ने तक ‘खेला होबे’ नारे वाला ममता का भाषण देश के 8 राज्यों में लाइव टेलीकास्ट किया गया। ममता की स्पीच का लाइव टेलीकास्ट पंजाब, उप्र, दिल्ली, महाराष्ट्र, मप्र, गुजरात, त्रिपुरा और तमिलनाडु में किया गया। ये पहला मौका था जब ममता ने शहीद दिवस को राष्ट्रीय कैनवास पर उतारा और इसी मंच से देश की राजनीति की आवाज उठाई, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को चुनौती दी।

ममता बनर्जी कोलकाता से भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को ललकार रही थीं तो दिल्ली में विपक्षी दलों के कई नेता उनकी स्पीच को सुनकर उनका साथ देने का संदेश दे रहे थे। कांग्रेस से पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह समेत एनसीपी से शरद पवार और सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव और जया बच्चन, डीएमके से त्रुचि शिवा, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी, आरजेडी से मनोज झा, टीआरएस के केशव राव अकाली दल से सरदार

बलविंदर सिंह और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, इन तमाम नेताओं ने ममता की स्पीच सुनी।

ममता ने विपक्ष की दूसरी पार्टियों के नेताओं से एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए मीटिंग का न्यौता दिया। 2024 में बचे तीन साल का इस्तेमाल उन्हें आगे की रणनीति के लिए करना होगा। वहीं, विपक्ष की एकजुटता दिखाने के लिए वो कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ रैली करेंगी। ममता ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि अगर उनका फोरम सत्ता में आता है तो पूरे देश को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने

खेला होबे नारे को दिल्ली पहुंचाने की बात भी कही और ऐलान किया कि 16 अगस्त को खेला दिवस के तौर पर मनाया जाएगा।

ममता बनर्जी को लगता है कि 2024 में प्रधानमंत्री पद का रास्ता लखनऊ की बजाय कोलकाता से होकर भी गुजर सकता है, तो कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस नेता नंदीग्राम वाले टोटके से ही कोलकाता से दिल्ली पहुंचना चाहती हैं, तो वो रास्ते से भटक सकती हैं। कोलकाता में शहीद दिवस के कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने पेगासस के जरिए जासूसी को लेकर केंद्र की भाजपा की

गुजरात बनाम बंगाल मॉडल

चुनावों के बाद भी ममता बनर्जी को भाजपा के हमलों से जूझते रहना पड़ा है। बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी भाजपा के निशाने पर तो रही ही हैं, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ भी नसीहतें देने का कोई भी मौका नहीं चूकते। अब तक तो ममता बनर्जी को सफाई ही देनी पड़ती रही, लेकिन पेगासस जासूसी के खुलासे के बाद थोड़ा खुलकर बोलने का मौका भी मिल गया है। बड़े दिनों बाद पहली बार ममता बनर्जी काफी जोश में नजर आ रही थीं। भाजपा के खिलाफ जंगे ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने गुजरात मॉडल का भी उपहास किया। ममता बनर्जी ने कहा कि गुजरात मॉडल कोई असली मॉडल नहीं है। असल में 2014 के आम चुनाव में भाजपा ने मोदी के गुजरात मॉडल को ही देश में विकास के एकमात्र मॉडल के तौर पर पेश किया था। गुजरात मॉडल के जवाब में ममता बनर्जी ने अब अपना बंगाल मॉडल पेश कर दिया है और दावा किया है कि बंगाल मॉडल ही एक ऐसा है जो सबके लिए है और सभी को फॉलो भी करना चाहिए। ममता बनर्जी ने ये भी दावा किया कि हमारी सरकार मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज मुहैया कराती है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती।

मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला और दिल्ली के तख्त से भाजपा को बेदखल करने के लिए विपक्षी दलों से मोर्चा बनाने का भी आव्हान किया। अब तक ये काम प्रशांत किशोर के माध्यम से चल रहा था, लेकिन वो ऐसी किसी भी कवायद से इनकार करते रहे। पहली बार ममता बनर्जी ने खुद इस बात का खुलासा किया है। ध्यान देने वाली बात ये है कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए ममता बनर्जी ने बंगाल से आगे बढ़कर देश की राजनीति में पैर जमाने के लिए भी प्लास्टर के टोटके के साथ कदम बढ़ाया है। याद रहे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में कहा करती थीं, एक पैर से बंगाल जीतेंगे और दो पैरों से दिल्ली। तब शायद ही किसी ने सोचा हो कि ममता बनर्जी दिल्ली के लिए भी प्लास्टर के टोटके का ही इस्तेमाल करेंगी। नंदीग्राम में



विधानसभा के लिए नामांकन के दिन ही ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद प्लास्टर लगा दिया गया था और पूरा चुनाव प्रचार ममता बनर्जी ने प्लास्टर लगे पांव के साथ व्हील चेयर पर बैठ कर ही किया था। अब पेगासस जासूसी के खिलाफ ममता बनर्जी अपने मोबाइल फोन पर प्लास्टर लगा कर विरोध जता रही हैं। ममता बनर्जी ने शहीद दिवस कार्यक्रम के दौरान अपना मोबाइल भी सबको दिखाया जिसके कैमरे पर ल्यूकोप्लास्ट लगा हुआ था।

पश्चिम बंगाल चुनाव में खेला होबे का नारा देने वाली ममता बनर्जी ने अब भाजपा के खिलाफ देश के हर राज्य में खेला करने का ऐलान किया है और 16 अगस्त को खेला दिवस मनाने का भी। ममता बनर्जी चाहती हैं कि एनसीपी नेता शरद पवार भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों की मोर्चेबंदी के मकसद से एक मीटिंग बुलाएं जिसमें वो भी शामिल हो सकें। शरद पवार कुछ दिन पहले भी विपक्षी दलों की एक मीटिंग होस्ट कर चुके हैं, लेकिन उसके बारे में एनसीपी नेता माजिद मेमन की तरफ से बताया गया था कि शरद पवार की भूमिका आयोजन तक ही सीमित रही। दिल्ली की वो मीटिंग राष्ट्रमंच के बैनर तले हुई थी, जिसके संयोजक के तौर पर टीएमसी उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा सामने आए थे। शरद पवार की ही तरह प्रशांत किशोर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ किसी भी तरह के मोर्चे के खड़े होने और उसकी सफलता की गुंजाइश को खारिज कर चुके हैं। प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि मोदी के खिलाफ विपक्ष का तीसरा या चौथा जैसा कोई भी मोर्चा खड़ा हो ही नहीं सकता।

ममता बनर्जी की कोलकाता में हुई शहीद दिवस के मौके पर वर्चुअल रैली में प्रशांत किशोर ने भी मौजूदगी दर्ज कराई और दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब में शरद पवार के साथ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की मौजूदगी देखी गई। मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी ने अब कांग्रेस को भी विपक्षी नेताओं के जमावड़े में शामिल करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में पवार और

चिदंबरम के साथ समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने भी ममता बनर्जी का भाषण सुना। ममता के भाषण की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि पहली बार वो सिर्फ बांग्ला में ही नहीं बोलें बल्कि, ज्यादा जोर हिंदी पर दिखा और अंग्रेजी पर भी। बस बीच-बीच में बांग्ला भी बोलती रहीं या हिंदी और अंग्रेजी में कही गई बातों को बांग्ला में दोहराती रहीं। पहली बार ये भी देखने को मिला कि शहीद दिवस के कार्यक्रम का दायरा सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा। दिल्ली के साथ ही, तृणमूल कांग्रेस की ये रैली त्रिपुरा के साथ-साथ गुजरात और उप्र में भी प्रसारित की गई।

दिल्ली की तरफ दौड़ लगाने की ममता बनर्जी की ये दूसरी कोशिश है। 2019 के आम चुनाव के पहले से ममता बनर्जी हिंदी के महत्व को समझती और समझाती रही हैं। ममता बनर्जी

विपक्ष का चेहरा होगी ममता ?

पश्चिम बंगाल में खेला होबे का नारा लगाकर भाजपा के अरमानों पर पानी फेरने वाली ममता बनर्जी ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही, सोनिया गांधी, कमलनाथ सहित अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और अपने सांसदों के साथ बैठक की। इससे यह संकेत मिल रहा है कि ममता विपक्ष का चेहरा बन सकती हैं। यास तूफान की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुए विवाद के बाद ये पहला मौका था जब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस मुखिया ने भी भाजपा के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा बनाने की जिम्मेदारी अघोषित तौर पर प्रशांत किशोर के कंधों पर डाली है। शायद यही वजह रही होगी कि प्रशांत किशोर ने हाल ही में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मीटिंग की। बताया जा रहा था कि इस मीटिंग में सोनिया गांधी भी वर्चुअल तौर पर जुड़ी थीं। इस मीटिंग में किस बात को लेकर चर्चा हुई इस पर केवल कयास लगाए गए, जो अभी तक केवल कयास ही साबित भी हुए हैं। लेकिन, ममता बनर्जी के इस दिल्ली दौरे पर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात से काफी हद कर स्थितियां साफ होती नजर आ रही हैं। भाजपा विरोधी दलों के संयुक्त मोर्चे में कांग्रेस को शामिल किए बिना ममता बनर्जी के मिशन 2024 की राह आसान नहीं होने वाली है। इसलिए ममता बनर्जी ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान कांग्रेस को सबसे अधिक महत्व दिया।

का मानना है कि किसी गैर-हिंदी भाषी के लिए देश का प्रधानमंत्री बनना काफी मुश्किल है। कोलकाता रैली में हिंदी में भाषण देकर ममता बनर्जी ने अपना आगे का इरादा जता दिया है। पेगासस को बेहद खतरनाक और क्रूर बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा, आज हमारी आजादी खतरे में है... भाजपा ने हमारी आजादी को खतरे में डाल दिया है, वो अपने मंत्रियों पर भी भरोसा नहीं करती और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि जासूसी के चलते ही वो शरद पवार और केजरीवाल या विपक्ष के दूसरे नेताओं से बात नहीं कर पातीं और इससे बचने के लिए ममता बनर्जी ने अपना मोबाइल फोन भी सबको दिखाया जिसके कैमरे पर ल्यूकोप्लास लगा हुआ था। प्लास्टर लगा फोन दिखाते हुए ममता बनर्जी बोलीं, हमारे फोन टैप किए जाते हैं... मैंने अपने फोन पर प्लास्टर चढ़ा दिया है... हमें केंद्र पर भी प्लास्टर चढ़ा देना चाहिए, वरना पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। 2024 के आम चुनाव को लेकर ममता बनर्जी बहुत आश्वस्त नहीं दिखीं। उन्होंने कहा- 'मैं नहीं जानती 2024 में क्या होगा, लेकिन इसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी। हम जितना वक्त जाया करेंगे, उतनी ही देरी होगी, भाजपा के खिलाफ सभी पार्टियों मिलकर मोर्चा बनाना होगा।' फिर भी ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के नेताओं को भरोसा दिलाने की कोशिश में कहा, 'भाजपा को देश से खदेड़े बिना लोकतंत्र को बचाना मुश्किल होगा... जब तक ऐसा नहीं होता हर राज्य में खेला होगा... हमने बंगाल में एक बार खेला दिखा दिया है, अब फिर से भगवा दल को खेला दिखाएंगे।'

● रजनीकांत पारे

2023 का छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव भाजपा मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किए बिना लड़ेगी। पार्टी के इस निर्णय को राजनीतिक पर्यवेक्षक और प्रदेश भाजपा नेताओं का एक वर्ग, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

डॉ. रमन सिंह के लिए एक झटके के रूप में देख रहा है। हालांकि कुछ प्रदेश भाजपा नेता जिनमें सिंह के वफादार भी शामिल हैं, इसकी

बिना सीएम चेहरा 2023 की जंग

ये व्याख्या कर रहे हैं कि ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है और पार्टी की 'संगठनात्मक नीति' का हिस्सा है (जिसका पार्टी में सिंह की स्थिति से कोई संबंध नहीं है) लेकिन कुछ दूसरे नेताओं ने नाम न बताने की शर्त पर स्वीकार किया कि ये ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है, जिनकी हैसियत को 2018 के छत्तीसगढ़ असेम्बली चुनावों में भाजपा की हार से झटका लगा था। लेकिन, जो बात बहुत से राजनीतिक पर्यवेक्षकों को हैरत में डालती है, वो ये है कि ये घोषणा चुनावों से इतना पहले कर दी गई है।

ये घोषणा कि पार्टी 2023 का चुनाव मुख्यमंत्री उम्मीदवार सामने लाए बिना लड़ेगी, भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पूरदेश्वरी की ओर से की गई। रायपुर में हुई कोर कमिटी की एक बैठक के बाद, पूरदेश्वरी ने कहा, 'अगले विधानसभा चुनावों में हम सिर्फ विकास के मुद्दों के साथ लोगों के पास जाएंगे। विकास ही हमारा चेहरा होगा और विकास ही प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी उसके बाद करेगी।'

प्रदेश भाजपा में बहुत से लोग अपेक्षा कर रहे थे कि सिंह के कद, उनकी लोकप्रियता और जनाधार को देखते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए वो एक स्वाभाविक पसंद होंगे। अब पूरदेश्वरी के ऐलान के ये मायने निकाले जा रहे हैं कि भाजपा आलाकमान संकेत देना चाहता है कि वो छत्तीसगढ़ में कोई नया चेहरा तलाश रहा है और 68 वर्षीय सिंह को शायद पार्टी के मार्गदर्शक या परामर्शदाता की कम सक्रिय भूमिका सौंपी जा सकती है।

2003 से 2018 के असेम्बली चुनावों में भाजपा की पराजय तक सिंह 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने रहे थे। 2018 में पार्टी की हार के बाद भी सिंह राज्य में भाजपा का चेहरा बने रहे और बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरते रहे, जैसे कि सरकार का कोविड स्थिति का प्रबंधन, विकास की गतिविधियों का अभाव और राज्य में नक्सल समस्या से निपटने



रमन के साथ और खिलाफ

पार्टी का सिंह से अलगाव छत्तीसगढ़ असेम्बली चुनाव में भाजपा की हार के बाद जल्द ही शुरू हो गया था। लोकसभा चुनावों में राज्य के किसी भी सिटिंग सांसद को, जिनमें रमन सिंह के बेटे अभिषेक भी शामिल थे, टिकट नहीं दिए गए। इसकी बजाय टिकट बंटवारे में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे जैसे उनके विरोधियों की ज्यादा चली। जब मोदी को फिर से जनादेश मिला तो अपेक्षा की जा रही थी कि सिंह को केंद्र सरकार में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब भी उनके समर्थकों ने इन संकेतों को खारिज किया था कि उन्हें पार्टी में किनारे किया जा रहा है। अब इस घोषणा और पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के विषय ने पार्टी के अंदर खेमाबंदी शुरू कर दी है, और नेता लोग पूर्व मुख्यमंत्री के पक्ष या विपक्ष में अपनी निष्ठा के हिसाब से अपना रुख तय कर रहे हैं। एक दूसरे प्रदेश भाजपा प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा, 'डॉ. रमन सिंह हमेशा से पार्टी के एक सक्रिय नेता रहे हैं, जो शासन में तीन सफल कार्यकाल देख चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय पर निर्भर करता है और हमें उसे मानना होता है।' चंद्राकर जो पार्टी विधायक भी हैं, प्रदेश भाजपा इकाई में रमन सिंह-विरोधी खेमे के नेता माने जाते हैं।

में कथित रूप से प्रयासों की कमी आदि।

वो आमतौर से पार्टी की प्रदेश इकाई से जुड़े फैसली भी लेते रहे हैं और छत्तीसगढ़ भाजपा में सभी प्रमुख पदों पर, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल है, सिंह के निष्ठावान ही बैठे हुए हैं। हालांकि अधिकांश प्रदेश भाजपा नेता खुलकर टिप्पणी करने से बच रहे हैं कि क्या केंद्रीय नेतृत्व सिंह को किनारे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाम न बताने की शर्त पर कुछ नेताओं ने स्वीकार किया कि पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का विकल्प तलाशने की कोशिशें की जा रही हैं।

एक प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने नाम छिपाने की शर्त पर कहा, 'प्रदेश प्रभारी का ऐलान वास्तव में पूर्व मुख्यमंत्री के लिए एक झटका है। जहां पार्टी पिछले 15 वर्षों में उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर वोट मांगेगी जब वो कुर्सी पर थे, वहीं ये भी सच है कि पार्टी उनके संभावित विकल्पों को भी तौल रही है। अंतिम फैसला 2023 चुनावों से पहले किया जाएगा।' सिंह के मुख्यमंत्री काल के दौरान छत्तीसगढ़ में इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े विकास कार्य किए गए

थे, जिनमें सड़कों का निर्माण और बिजली में आत्मनिर्भरता शामिल हैं। नया रायपुर शहर का निर्माण और इस्पात उत्पादन केंद्र के रूप में छत्तीसगढ़ का कायाकल्प भी, उन्हीं के अंतर्गत शुरू हुआ था। इस बीच, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु देव साइ ने, जो सिंह के वफादार हैं, घोषणा के निष्कर्षों को हल्का करने की कोशिश की। 'भाजपा की नीति रही है कि वो चुनावों से पहले, कभी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं करती, 15 वर्षों तक जब डॉ. रमन सिंह सरकार के मुखिया रहे तब भी ऐसा ही था। चुनावों के बाद विधायक उन्हें अपना नेता चुनते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग चीजों से वाकिफ थे और उसी हिसाब से वोट देते थे।' साइ ने आगे कहा, 'डी पूरदेश्वरी ने जो घोषणा की वो पार्टी की नीति का हिस्सा थी और सिर्फ ये है कि 2013 चुनावों के लिए हमारा मुख्य मुद्दा विकास रहेगा और साथ में कांग्रेस का कुशासन और उसकी नाकामियां रहेंगी। मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा, लेकिन पार्टी के लिए रमन सिंह का मार्गदर्शन हमेशा मूल्यवान रहेगा।'

● रायपुर से टीपी सिंह

देश के प्रधानमंत्री के साथ हुई हर मुलाकात महत्वपूर्ण होती है - और जब ये किसी विपक्षी नेता से तो हर किसी के कान खड़े हो ही जाते हैं। वो भी तब जब उस नेता के साथ मुलाकात हो जो सत्ताधारी दल के गठबंधन साथी को छीन कर अपने साथ सरकार बना लिया हो - और अगले आम चुनाव में प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्षी नेताओं को एकजुट कर मोर्चा खड़ा करने की कोशिश कर रहा हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का मिलना तब तो और भी अहम हो जाता है जब उसका सीधा कनेक्शन महाराष्ट्र की उद्भव ठाकरे सरकार से जुड़ता हो। वो भी ऐसे दौर में जब गठबंधन पार्टनर कांग्रेस का महाराष्ट्र अध्यक्ष खुलेआम बोल रहा हो कि उद्भव सरकार का रिमोट तो शरद पवार के पास ही रहता है - और शिवसेना का विधायक उद्भव ठाकरे को फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिला लेने की सलाह दे रहा हो।

राजनीति में किरदार बदल जाते लेकिन उसके निहितार्थ एक जैसे ही निकाले जाते हैं - शरद पवार से पहले जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्भव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे ही कयास लगाये जाने लगे थे। अच्छी बात ये है कि जब भी शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं, दोनों ही तरफ से मुलाकात की तस्वीरें शेयर की जाती हैं - और कम से कम एक मुद्दा तो बता ही दिया जाता है, ये बात अलग है कि बाद में खबर आती है कि मुद्दा तो मुलाकात का औपचारिक विषय था, बातें तो ज्यादा इधर उधर की ही हुईं। जैसे महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार बनने से पहले वाली मुलाकात का विषय किसानों की समस्याएं थीं, लेकिन पता चला राजनीतिक गठबंधन की गंभीर चर्चा हुई थी।

शरद पवार ने प्रधानमंत्री के साथ ताजा मुलाकात की वजह सहकारिता से जुड़े मुद्दे बताये हैं, बाकी बातों के लिए सही मौके का इंतजार करना होगा। बिलकुल वैसे ही जैसे प्रशांत किशोर के ज्वाइन करते वक्त नीतीश कुमार उनको जेडीयू का भविष्य बताते हैं - और अरसा बाद बताते हैं कि वो तो ऐसा अमित शाह के कहने पर किये थे। तभी तो जब नीतीश कुमार ने निकाल दिया तो प्रशांत किशोर ने भी बोल दिया कि वो अपने मन से तो कुछ कर नहीं रहे हैं।

बीती बातें अपनी जगह हैं और अभी लगता तो ऐसा है कि शरद पवार की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की एक वजह प्रशांत किशोर की विपक्षी दलों को लेकर एकजुटता की कोशिश भी हो सकती है - क्योंकि संसद के किसी भी सत्र के शुरू होने से पहले सदन को शांतिपूर्वक चलाने के लिए सर्वदलीय बैठकें तो होती हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच इस कदर संवाद तो कम ही होता है



बन रहे नए समीकरण

विपक्ष की राजनीति दिखाने लगी है दम

पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी ने ये समीकरण बदलने की कोशिश की है। अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को आगे कर ममता बनर्जी ने मीटिंग तो करायी, लेकिन कांग्रेस नेताओं के नाम पर एनसीपी नेता माजिद मेमन ने उन नेताओं का नाम गिनाया था जिनमें ज्यादातर कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बगावत के लिए जाने जाते रहे हैं। सत्ता पक्ष की गांधी परिवार और कांग्रेस नेताओं की जगह ज्यादा मुलाकातें शरद पवार से होना भी देश की राजनीति में बन रहे नये समीकरणों का ही संकेत है - ऐसे समीकरण बन रहे हैं जिसमें शरद पवार विपक्षी खेमे के बीच मजबूत कड़ी के तौर पर उभर कर सामने आये हैं। शरद पवार के साथ सत्ता पक्ष के नेताओं की बारी बारी मुलाकात बता रही है कि बीजेपी नेतृत्व को भी नये सिरे से विपक्ष की अहमियत समझ में आने लगी है।

जैसा मॉनसून सत्र से पहले हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले शरद पवार की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकातें हुई थीं। पीयूष गोयल को राज्य सभा में सदन का नेता बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शरद पवार के साथ ही एके एंटी के साथ भी मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। असल में पवार और एंटी दोनों ही देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं - और बताया गया है कि राजनाथ सिंह ने विपक्षी खेमे के दोनों नेताओं को चीन के मुद्दे पर सरकार के स्टैंड की जानकारी दी है।

अब जितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात है, तस्वीर

का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण लगता है। कांग्रेस की तरफ से एके एंटी ऐसी मुलाकातों को हिस्सा जरूर रहे हैं लेकिन उनका पूर्व रक्षा मंत्री होना बड़ी वजह है - ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऐसी किसी भी मुलाकात का हिस्सा नहीं बने हैं। मोदी-पवार मुलाकात को ज्यादा समझने के लिए हाल की कई मुलाकातों से जोड़ कर भी समझने की कोशिश की जा सकती है। सिलसिले की शुरुआत प्रशांत किशोर की शरद पवार के साथ एक लंबी मुलाकात से होती है - और अंत पीके के गांधी परिवार के साथ हुई मीटिंग से। राहुल गांधी के घर पर प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी और खबरों के मुताबिक सोनिया गांधी से भी वचुअल मुलाकात की थी।

सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि गांधी परिवार से प्रशांत किशोर की मुलाकात यशवंत सिन्हा की पहल पर राष्ट्र मंच के बैनर तले विपक्षी दलों की एक अहम बैठक और उसके ठीक बात कमलनाथ के शरद पवार से मिलने के बाद होती है। समझने वाली बात ये रही कि ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे प्रशांत किशोर ने शरद पवार को आगे कर विपक्ष को एकजुट करने की कवायद शुरू की और कांग्रेस को उससे पूरी तरह अलग रखा गया। लेकिन जब कमलनाथ ने शरद पवार के घर जाकर मुलाकात की उसके बाद ही कांग्रेस को लेकर उनका बयान आया कि विपक्ष की कोई भी मोर्चेबंदी कांग्रेस के बगैर पूरा होना संभव नहीं है। बात भी सही है, लेकिन अब तो यही होता रहा कि विपक्षी खेमे को जुटाने में भी कांग्रेस की तरफ से एक खास सेलेक्शन प्रॉसेस हुआ करता था - और अब तक ऐसी बैठकों से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बाहर ही रखा जाता रहा।

● बिन्दु माथुर

पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी को दरकिनार करते हुए कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हालांकि, कैप्टन और सिद्धू के बीच अभी सुलह हो गई है। गत दिनों अमरिंदर सिंह ने पंजाब भवन में नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की। सिद्धू की ताजपोशी के दिन अमरिंदर सिंह उनसे मिले। हालांकि पहले कैप्टन ने कहा था कि जब तक सिद्धू माफी नहीं मांगेंगे, वो उनसे नहीं मिलेंगे। पंजाब को लेकर किए गए कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के फैसले के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान को लेकर भी ऐसा ही कोई फैसला लिया जा सकता है।

नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले के बाद राजस्थान में सचिन पायलट खेमे को उम्मीद नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ लंबे समय से चली आ रही सियासी खींचतान का अंत हो सकता है। इन उम्मीदों को राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन के एक ट्वीट को रिट्वीट करने से और बल मिल गया है। दरअसल, कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने एक पत्रकार के दो ट्वीट्स को रिट्वीट किया है, जिसमें कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले की तारीफ की गई है। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि इस रिट्वीट ने अशोक गहलोत खेमे की नींद में खलल जरूर डाला होगा।

अजय माकन ने जिन ट्वीट को रिट्वीट किया है, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य में कोई क्षत्रप अपने दम पर नहीं जीतता है। गांधी-नेहरू परिवार के नाम पर ही गरीब, कमजोर वर्ग और आम आदमी का वोट मिलता है। मगर चाहे, वो अमरिंदर सिंह हों या गहलोत या पहले शीला या कोई और। मुख्यमंत्री बनते ही यह समझ लेते हैं कि उनकी वजह से ही पार्टी जीती। 20 साल से ज्यादा अध्यक्ष रहें सोनिया गांधी ने कभी अपना महत्व नहीं जताया। नतीजा यह हुआ कि वे वोट लाती थीं और कांग्रेसी अपना चमत्कार समझकर गैर जवाबदेही से काम करते थे। हार जाते थे, तो दोष राहुल पर, जीत का सेहरा खुद के माथे।



अब तंबर राजस्थान का!

सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नेतृत्व ने सही किया। ताकत बताना जरूरी था। अजय माकन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो इतना आसानी से कहा जा सकता है कि उन्होंने केवल यूँ ही अच्छा लगने पर ट्वीट को रिट्वीट नहीं कर दिया होगा।

इस रिट्वीट के मायने तब और बढ़ जाते हैं, जब उनके पास राजस्थान का प्रभार हो। प्रदेश कांग्रेस के सभी सियासी मसलों को सुलझाने का भार अजय माकन के पास है, तो उनका ये रिट्वीट खुद-ब-खुद ही सारी कहानी कह देता है। अजय माकन ने करीब दो महीने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि सचिन पायलट कांग्रेस के लिए एसेट हैं। राजस्थान में सरकार बनाने में उनका बड़ा योगदान है और पार्टी आने वाले समय में उन्हें कोई भूमिका सौंपेगी। अजय माकन के इस रिट्वीट को अशोक गहलोत के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल, कुछ समय पहले ही सचिन पायलट ने दिल्ली का दौरा किया था। लेकिन, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। लेकिन, माना जा रहा था कि

सचिन पायलट को आश्वासन दे दिया गया है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए पायलट खेमे को संतुष्ट कर दिया जाएगा।

संगठन में मची इस हलचल से इतर अशोक गहलोत काफी समय से कांग्रेस आलाकमान के मंत्रिमंडल विस्तार के फैसले को टालते आ रहे हैं। उन्होंने काफी हद तक अमरिंदर सिंह वाला फॉर्मूला ही अपना रखा है। अजय माकन लंबे समय से सचिन पायलट को मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सांत्वना दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अजय माकन ने अशोक गहलोत से मुलाकात कर उन्हें कांग्रेस आलाकमान के फैसले के अवगत करा दिया था। हालांकि, इसके बावजूद अशोक गहलोत लगातार इसे टालते जा रहे हैं। माना जा रहा था कि अशोक गहलोत ने रणनीति के तहत पंजाब में सिद्धू और कैप्टन के बीच चल रही खींचतान के फैसले का इंतजार किया। अब पंजाब को लेकर फैसला आ चुका है, तो अशोक गहलोत पूरी तरह से वेट एंड वॉच की मुद्रा में आ चुके हैं।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

आलाकमान की बात को अनसुना कर रहे गहलोत

इसी महीने राजस्थान कांग्रेस के कुछ नेता प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मिलने पहुंचे थे। बताया जा रहा था कि ये वो नेता हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव में 13 निर्दलियों और बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों से हार गए थे। इन नेताओं का आरोप था कि गहलोत सरकार और संगठन में इनकी अनदेखी की जा रही है। संगठन संभालने का काम पुराने कार्यकर्ताओं की जगह निर्दलियों और बसपा से आए विधायकों को ही दे दिया गया है। हालांकि, इन नेताओं की अजय माकन से मुलाकात नहीं हो सकी थी। लेकिन, माना जा सकता है कि संगठन में मची इस हलचल से राजस्थान के प्रभारी वाकिफ हो ही गए होंगे। खैर, अजय माकन के रिट्वीट का असर भी काफी हद तक सामने आ गया है। अशोक गहलोत ने एक ट्वीट के जरिए सिद्धू को बधाई देते हुए सचिन पायलट खेमे के लिए नरमी के संकेत दे दिए हैं। दरअसल, पंजाब में सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अशोक गहलोत पर अपने आप ही दबाव पड़ गया है। हालांकि, कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए अशोक गहलोत भी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की तरह ही सचिन पायलट से भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की शर्त रख सकते हैं। लेकिन, ऐसा होता नहीं दिख रहा है।

कांग्रेस महासचिव और उप्र की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड़ा ने संकेत दिया है कि अगले चुनाव में उनकी पार्टी गठबंधन कर सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करेगा कौन या उन्होंने किसके साथ गठबंधन के बारे में सोचा है? उप्र की लगभग सभी पार्टियों ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। सपा ने प्रदेश की छोटी-छोटी पार्टियों के साथ तालमेल करना शुरू कर दिया है तो भाजपा ने सहयोगी पार्टी अपना दल की अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाकर अपना गठबंधन लगभग घोषित कर दिया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की भी सपा के अखिलेश सिंह से बातचीत हुई है। संजय सिंह ने अखिलेश के जन्मदिन पर उनसे मुलाकात की। लेकिन इस दौरान बात क्या हुई किसी को नहीं पता।

उप्र में अब सिर्फ एक पार्टी बची है, जिसके साथ कांग्रेस का तालमेल हो सकता है और वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी! परंतु मुश्किल यह है कि बसपा ने पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन कर लिया है, जिसका मुख्य मुकाबला कांग्रेस के साथ ही है। दूसरी ओर पिछले लोकसभा चुनाव में जब सपा ने बसपा से तालमेल किया था तब कांग्रेस को भी उस गठबंधन का हिस्सा बनाने के प्रस्ताव को बसपा प्रमुख मायावती ने ही खारिज किया था। मायावती की जिद के चलते ही कांग्रेस को अकेले लोकसभा चुनाव में उतरना पड़ा था। राजनीतिक जानकारों की मानें तो अगर कांग्रेस उस गठबंधन का हिस्सा होती तो उप्र की तस्वीर शायद अलग ही होती।

कांग्रेस से मायावती की दूरी का कारण यह धारणा भी है कि अगर एक बार कांग्रेस और बसपा साथ आए और बसपा का दलित वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ तो वह वोट हमेशा के लिए कांग्रेस का हो जाएगा। मायावती की दूसरी चिढ़ राजस्थान से भी बनी है, जहां उनकी पार्टी से जीते 6 विधायक पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बावजूद उप्र में बसपा ही एक पार्टी है, जिसके साथ कांग्रेस का तालमेल हो सकता है। पार्टी के कई नेता मान रहे हैं कि बसपा प्रमुख मायावती एक बार फिर ब्राह्मण वोट अपनी ओर करने की राजनीति कर रही है और इसमें कांग्रेस मददगार हो सकती है। ध्यान रहे

उप्र में कांग्रेस की खेवनहार प्रियंका गांधी ने छोड़ा शिगूफा... विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को चाहिए सहयोगी... पार्टी कर सकती है गठबंधन, लेकिन किससे होगा गठबंधन, लगभग सभी पार्टियां खोल चुकी है पत्ते, बस हाथ को मिल सकता है हाथी का साथ, लेकिन बहनजी का धर्मसंकट भी है बड़ा, अपना जनानाधार खिसकने का लगता है डर।



साथ आने का धर्मसंकट!

‘भूत’ और ‘वर्तमान’ के अनुभव रहे हैं खट्टे!

मायावती ने जोर देकर कहा है कि अब ब्राह्मण कभी भी भाजपा को वोट नहीं देगा। आपको बता दें कि ब्राह्मणों ने 2007 के चुनाव में खुलकर बसपा का समर्थन किया था, जिससे बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। तभी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट एकजुट करने का एक दांव कांग्रेस और बसपा के तालमेल से हो सकता है। कांग्रेस के कई नेता मान रहे हैं कि जिस तरह कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सीपीएम से मिलकर और केरल में सीपीएम के खिलाफ लड़ती है वैसे ही उप्र में बसपा से मिलकर और पंजाब में बसपा के खिलाफ लड़ सकती है। लेकिन कहीं नतीजा केरल और पश्चिम बंगाल जैसा ही हुआ तो क्या होगा? जो हो प्रियंका के बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज होगी और कुछ दिलचस्प घटनाक्रम हो सकता है।

बसपा ने अयोध्या से शुरू करके कई प्रदेश के सभी मंडलों में ब्राह्मण सम्मेलन कराने का ऐलान किया है। बसपा के महासचिव सतीश मिश्र इसकी अगुवाई कर रहे हैं।

भले ही मायावती का सियासी वक्त गर्दिश में हो पर आज की तारीख में उप्र की सक्रिय सबसे परिपक्व पॉलिटिशियन मायावती ही हैं। सपा का गेम प्लान समझते हुए मायावती ने अखिलेश का खेल बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी। मोहब्बत

और सियासत में कुछ हलचलें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं हैं। उप्र में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती में संग्राम छिड़ा है। मोहब्बत और सियासी अनुष्ठान में ना को हां भी माना जाता है। उप्र में योगी सरकार का कार्यकाल जब समाप्ति की ओर है तब बसपा सुप्रीमो मायावती विपक्षी तैवरों में नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि उनका विरोध भाजपा को टॉनिक देने के लिए है। बसपा हाशिए पर थी इसलिए भाजपा के खिलाफ वोट एक तरफा सबसे बड़े विपक्षी दल के पाले में आ गया तो पश्चिम बंगाल जैसे नतीजे दोहरा सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस शंका से बसपा ने अपनी अप्रत्यक्ष दोस्त भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए उसका विरोध करना शुरू कर दिया। नजदीक आते उप्र विधानसभा चुनाव

को देखते हुए बसपा सुप्रीमो बयानबाजी के जरिए अब विपक्षी भूमिका में आ गई हैं। साढ़े चार साल तक भाजपा सरकार का अप्रत्यक्ष समर्थन करने के बाद अब योगी सरकार के खिलाफ बसपा के बयान दरअसल सपा के खिलाफ लड़ाई का एक मजबूत शस्त्र हैं।

साढ़े चार साल योगी सरकार के दौरान मायावती या तो खामोश रहीं या फिर उन्होंने भाजपा के फैसलों का समर्थन करने वाली बसपा अब भाजपा के हर कदम के खिलाफ आक्रामक हो गई हैं। धर्मांतरण या आतंकवाद के खिलाफ योगी सरकार के आपरेशंस हों या जनसंख्या नियंत्रण कानून अथवा संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, मायावती सब के खिलाफ आक्रामक दिखीं और उन्होंने इस धारणा को तोड़ने की भरपूर कोशिश शुरू कर दी कि सत्तारूढ़ दल से लड़ने के लिए सपा ही भाजपा के खिलाफ उप्र में लड़ने के लिए सक्षम है। इस सबसे बड़े विपक्षी दल के बाद कांग्रेस में मजबूत संगठन तक नहीं है और बसपा के बारे में लोगों की धारणा बनती जा रही थी कि बसपा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के साथ है। कहते हैं कि मरा हुआ हाथी भी सौ लाख का होता है। उप्र की सियासत में सबसे सीनियर बसपा सुप्रीमो मायावती को नजरअंदाज करना नादाना होगी। इस वक्त उप्र में दो दलों के बीच जंग में चल रही तलवारों की खनक किसी को सुनाई नहीं दे रही। लेकिन तजुबेकार बसपा सुप्रीमो उप्र की राजनीति में अपने अनुभव के शस्त्र अभी और भी चलाएंगी।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने अच्छी कामयाबी अर्जित की है। राजद अकेले सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है, परंतु नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू से विरोधी दल हमेशा सशक्त रहते आए हैं। राजद में भी टूट की आशंका जताई जा रही थी, किंतु अब लालू के बाहर आ जाने से यह खतरा लगभग टल गया है।

लालू ने जगाई उम्मीदे...



चारा घोटाले में 23 दिसंबर, 2017 को जेल जाने के बाद से राजद प्रमुख लालू प्रसाद चुप रहकर लगातार पर्दे के पीछे से ही राजनीति करते आ रहे थे। अब जमानत मिलने के बाद तमाम बंदिशों से मुक्त और मुखर होकर हस्तक्षेप करेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से तेजस्वी यादव ने अपना कद जरूर बढ़ा लिया है, लेकिन अब भी भाजपा एवं जदयू के बड़े नेताओं के मुकाबले विपक्ष की राजनीति को एक कददावर नेता की जरूरत महसूस की जाती है। लालू इसकी भरपाई कर सकते हैं।

पार्टी की कमान संभाल चुके उनके पुत्र तेजस्वी यादव को लालू की वापसी से खासी उम्मीदे हैं, हालांकि तमाम आरोपों, मुकदमों और जेल में बीते दिनों के बाद बीमारियों से जूझ रहे लालू एक बार फिर करिश्माई साबित होंगे, इस पर सवाल है। वैसे मई में उनकी रिहाई के बाद से बिहार के सियासत में हुए कुछ घटनाक्रम को उनकी सक्रियता से जोड़ा जा रहा है। कहा जाता है कि लालू के जन्मदिन पर बेटे तेज प्रताप की जीतनराम मांझी से मुलाकात के पीछे उन्हीं की मंशा थी। बिहार में विपक्ष में बिखराव के हालात हैं, जबकि दलों और नेताओं को जोड़कर सत्ता से मोर्चा लेने में लालू करिश्माई नेता रहे हैं। ऐसे में उनकी सक्रियता को लेकर सत्तापक्ष भी राजद पर नजर रखे हुए है।

राजद के 25 वर्षों के सफर पर नजर डालें तो ये लालू यादव के प्रभाव के बाहर नहीं दिखता। अब हालात ये हैं कि पार्टी से लोकसभा में सांसद ही नहीं हैं, जबकि राज्यसभा में उनकी बेटे मीसा सहित 5 सदस्य हैं, विधानसभा में 75 विधायक हैं। तेजस्वी ने लालू की गैर मौजूदगी के चुनावों में उनके प्रभाव को समझ लिया है। बीते विधानसभा चुनाव में राजद ने ग्रामीण इलाकों के पोस्टर में लालू को जगह दी, जबकि शहरी क्षेत्रों में परहेज किया। लेकिन अब वह लालू के करिश्मे की शरण में दिख रहे हैं। लालू यादव ने गरीब, पिछड़े, दलित और मुस्लिम को लेकर ऐसा सामाजिक समीकरण तैयार किया कि बिहार में

विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं लालू यादव

तीन दशक तक बिहार की राजनीति की धुरी बने लालू दिल्ली रहें या पटना-रांची या कहीं और, राजनीति उनकी रगों में है। लंबे अंतराल के बाद जेल से बाहर आकर राजनीति को पूरा समय देने का मनोवैज्ञानिक असर पड़ना लाजिमी है। विपक्षी खेमे के साथ-साथ सत्तापक्ष भी लालू के असर से वंचित नहीं रह सकता है। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सीमा से आगे जाकर लालू को अभियान चलाते हुए देखा जा चुका है। तब जेल अस्पताल में होने के कारण उन पर तमाम तरह के पहरे भी थे। फिर भी भाजपा-जदयू के शीर्ष नेताओं को लालू ने अपनी कोशिशों से कुछ समय के लिए हैरत में डाल दिया था। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद स्वास्थ्य कारणों से लालू अभी भले ही घर लौटने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अगले महीने तक वे पटना में हो सकते हैं। इसके साथ ही बिहार की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल बिहार से दूर दिल्ली में बैठकर भी लालू यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेटों के बीच किसी तरह की दरार न पड़े। पार्टी में तेज प्रताप यादव की उपेक्षा को खत्म करने के प्रयास में लालू यादव ने कहा कि तेज प्रताप की बातों में दम है।

नए सियासी युग की शुरुआत हो गई। इससे पहले वह बतौर जनता दल नेता मार्च 1990 से लेकर जुलाई 1997 तक मुख्यमंत्री रह चुके थे। चारा घोटाले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद लालू ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर पत्नी राबड़ी देवी को 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री बना दिया था। राजद ने अपने पहले लोकसभा चुनाव में 1998 में बिहार में 26.6 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 17 सीटें हासिल कीं, जबकि 1999 में उसे 7 सीटें मिलीं। इसके बाद शुरू होता है बिहार में लालू की सोशल इंजीनियरिंग का कमाल। जब

राजद ने 2004 के लोकसभा चुनाव में 21 सीटें जीतीं और लालू यादव यूपीए सरकार में रेलमंत्री बने। इससे पहले वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में राजद को 124 सीटें (28.3 प्रतिशत वोट शेयर) हासिल हुई थी। लोकसभा सीटों की संख्या के बल पर लालू केंद्र की राजनीति में खासी दखल रखते रहे और बतौर मुख्यमंत्री उन्हींने और पत्नी राबड़ी देवी ने बिहार में लंबे समय तक शासन किया। लेकिन इसके बाद राजद ने गिरावट का दौर देखना शुरू किया, जो बाद में नीतीश के साथ गठबंधन करके भी अच्छे दिन में न बदल सका। लालू केंद्र की सत्ता से 2009 के बाद से ही दूर हो गए।

करीब 6 सालों तक सत्ता से विस्थापित रहने के बाद लालू ने 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का साथ लिया। अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में 54 सीटों (23.5 प्रतिशत वोट शेयर) और 2010 में महज 22 सीटों (18.8 प्रतिशत वोट शेयर) पर सिमट जाने वाली लालू की पार्टी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में लंबी छलांग लगाई थी। जेडीयू-कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ते हुए 243 में 80 सीटें (18.8 प्रतिशत वोट शेयर) अकेले अपने खाते में जोड़े थे। तीनों ने मिलकर 178 सीटें झटक ली थीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और लालू पुत्र तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री एवं बड़े बेटे तेजप्रताप स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए, लेकिन जुलाई 2017 में यह गठबंधन टूट गया और नीतीश ने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में नई सरकार का गठन किया। इसके बाद से राजद ने लगातार गिरावट का दौर ही देखा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वोट शेयर बढ़कर 23.5 प्रतिशत हो गया, लेकिन सीटें घटकर 73 रह गईं। चुनाव से पहले कई साथी भी दल छोड़कर चले गए। अब संगठन को मजबूत करना तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती है। वह जानते हैं कि बिहार की जनता से जुड़ाव का जो जादू लालू के पास है, वह उनके पास नहीं है। ऐसे में उम्मीद है कि राजद इंटरनेट के माध्यम से लालू की मौजूदगी को नई ताकत दे सकती है।

● विनोद बक्सरी

भारत के प्रति सकारात्मक रुख रखने वाले शेर बहादुर देउबा के प्रधानमंत्री बनने से उत्तराखंड से लगी नेपाल सीमा पर करीब एक वर्ष से बनी तनावपूर्ण स्थिति के अब सामान्य होने की उम्मीद बढ़ी है।

कालापानी क्षेत्र के साथ ही लिंपियाधुरा, लिपुलेख पर होने वाली तकरार के अंत की भी आस है। झूला पुलों के खुलने के साथ ही आवाजाही भी सामान्य हो सकती है। इसका सीधा असर प्रदेश के तीन जिलों पिथौरागढ़, चम्पावत व ऊधमसिंह नगर पर होगा। पश्चिमी नेपाल का अधिकतर हिस्सा भी इससे लाभांविता होगा।

मई 2020 में तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन के प्रभाव में आकर लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी को अपना बताते हुए नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया। भारत पर अतिक्रमण का आरोप लगाकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बयानबाजी भी की। उन्होंने हालात इस कदर बिगाड़े कि खुली सीमा पर पहरा भी लगा दिया। नेपाल शस्त्र बल की ताबड़तोड़ बीओपी खोलनी शुरू कर दी। उत्तराखंड सीमा पर तनाव **बरकरार रखने के लिए ओली** की हरकत यहीं तक सीमित नहीं रही। कैलाश मानसरोवर मार्ग पर निगरानी के लिए छांगरू में चौकी का निर्माण भी कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है। ऐसे में नेपाल से लगी उत्तराखंड सीमा पर भी बदलाव की उम्मीद है। भारत-नेपाल संबंधों के जानकार मेजर बीएस रौतेला (सेवानिवृत्त) बताते हैं कि देउबा के सत्ता संभालने से सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से भी गहरा प्रभाव पड़ेगा।

गर्बाधार-लिपुलेख मार्ग को अतिक्रमण बता विरोध जता रहे नेपाल ने 18 मई 2020 को नया नक्शा जारी कर दिया। इसमें लिपुलेख और कालापानी को अपना बता नई अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा तय करने का दावा किया। नेपाल ने

देउबा सुधारेंगे बिगड़े संबंध



सिर्फ उत्तराखंड से लगती 805 किमी सीमा में ही बदलाव किया। लद्दाख, हिमाचल, उप्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ ही चीन से लगती सीमा को पूर्ववत् ही रखा।

देउबा सरकार में अहम भागीदार नेपाली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने नई सरकार में बदलाव का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत से हमारे सबसे बेहतर संबंध होने चाहिए। हम इसके लिए लगातार प्रयास भी करेंगे। फिलहाल भारत का सकारात्मक रुख रहा तो सभी मसलों का शांतिपूर्वक समाधान होगा। सरकार का नेतृत्व कर रही नेपाली कांग्रेस का भारत से कभी विवाद नहीं रहा। ऐसे में देउबा के विश्वासमत् हासिल करने के बाद रिश्तों में बदलाव का असर दिखेगा। सीमा विवाद पर दोनों देश मिलकर बैठेंगे तो समाधान जरूर निकलेगा। इसके लिए सोच बदलनी होगी।

ओली की नीतियों का प्रभाव भारत-नेपाल के रोटी-बेटी के मधुर संबंधों पर भी पड़ा। ऐसे में

पिथौरागढ़, चम्पावत, बनबसा, टनकपुर और खटीमा की जिन बेटियों की शादी नेपाल में हुई वह न तो एक वर्ष से अपने घर आ पाई और न ही मायके वाले बेटी के ससुराल पहुंचे। इस सब के बीच जब शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो काठमांडू व तराई के साथ ही सीमावर्ती पिथौरागढ़, चम्पावत व खटीमा में भी जश्न मना। लोगों को लगा कि अब नेपाल से रिश्ते सामान्य होंगे और फिर पुराने सौहार्द के दिन लौटेंगे। रोटी-बेटी के संबंध और प्रगाढ़ होंगे।

देउबा का भारत से पुराना नाता रहा है। चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में देउबा ने अगस्त 2017 में भारत का दौरा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता की थी। देउबा इससे पूर्व 1996, 2004 और 2005 में भी प्रधानमंत्री के रूप में भारत के दौरे कर चुके हैं। देउबा सुदूर पश्चिमी नेपाल के डडेलधुरा जिले के रहने वाले हैं। यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से सटा है। ऐसे में बचपन से उनका पिथौरागढ़ व भारत से खास लगाव रहा। छात्र नेता के रूप में राजनीति की शुरुआत के दौरान भी देउबा इस क्षेत्र में आते रहे। ऐसे में उनके प्रधानमंत्री बनने से सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहद बेहतर की उम्मीद है।

नेपाल में पक्ष और विपक्ष के दरम्यान बीते पांच महीनों से सत्ता को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री की कुर्सी हथियाने के लिए दोनों में युद्ध जैसी जोर आजमाइश हो रही थी। अंत: जंग में आखिरकार सफलता विपक्षी दलों के हाथ लगी। उम्मीद थी नहीं कि शेर बहादुर देउबा को देश की कमान सौंपी जाएगी, ज्यादा उम्मीद तो जल्द संसदीय चुनाव होने की थी। क्योंकि इसके लिए नेपाल चुनाव आयोग ने तारीखें भी मुकर्रर की हुई थीं। संभवत: 12 या 19 नवंबर को संसदीय चुनाव होने थे। पर, सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ उलट-पुलट कर रख दिया। फिलहाल, इसके साथ ही एक बार फिर नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है।

● **राजेश बोरकर**

देउबा के विचार चीन और पाकिस्तान से मेल नहीं खाते

भारत-नेपाल दोनों देशों में देउबा को सूझबूझ वाला जननेता कहा जाता है। उनकी सादगी लोगों को भाती है, मिलनसार तो हैं ही, बेहद ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है वह देशहित के सभी निर्णय सर्वसहमति से लेते हैं। 75 वर्षीय देउबा का जन्म पश्चिमी नेपाल के ददेलधुरा जिले एक छोटे से गांव में हुआ था। स्कूल-कॉलेज के समय से ही वह राजनीति में थे। सातवें दशक का जब आगमन हुआ, तब वह राजनीति में ठीक-ठाक सक्रिय हो चुके थे। राजधानी काठमांडू की सुदूर-पश्चिमी में उनका आज भी बोलबाला है। छात्र समितियों में भी वह लोकप्रिय रहे। कॉलेज में छात्रसंघ के कई चुनाव जीते। वैसे, देखें तो छात्र समितियां सियासत की मुख्यधारा में आने की मजबूत सीढ़ियां मानी गई हैं। सभी जमीनी नेता इस रास्ते को अपनाते आए हैं। बहरहाल, देउबा का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए बेहद सुखद और चीन-पाकिस्तान के नाखुशी जैसा है। देउबा के विचार चीन और पाकिस्तान से मेल नहीं खाते, उनका भारत के प्रति लगाव और हितैषीपन जगजाहिर है। देउबा के जरिए भारत अब निश्चित रूप से नेपाल में चीन की घुसपैठ को रोकने का प्रयास करेगा।

अफगानिस्तान के 85 प्रतिशत भाग पर तालिबान का कब्जा हो गया है, ऐसा दावा खुद तालिबान कर रहा है, जबकि अफगानिस्तान की सरकार ने तालिबान के इस दावे का खंडन किया है। उसने कहा है कि हमारे सैनिक

तालिबान को नियंत्रित करने और नागरिकों को सुरक्षा देने में सक्षम हैं। अफगानिस्तान के नागरिक काफी डरे हुए हैं, उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है, बच्चों की शिक्षा एवं रोजगार की चिंता उन्हें सता रही है। नागरिकों की बड़ी-बड़ी दुकानें हिंसा के बल पर बंद कराने के खतरे उत्पन्न हो गए हैं। इसलिए नागरिकों के बीच में तालिबान की वापसी के खिलाफ चेतना भी आई है। नागरिक संगठन अफगानिस्तानी सैनिकों की मदद के लिए आगे आए हैं, रसद और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, खासकर महिलाएं तालिबान के खिलाफ हथियार उठा रही हैं।

तालिबान पहले से अधिक ताकतवर हुए हैं। तालिबान अफगानिस्तानी सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं। अफगानिस्तान के सैनिक तालिबान के छापामार युद्ध में पराजित हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं पर आमने-सामने की लड़ाई में अभी भी तालिबान कमजोर हैं और अफगानिस्तान के सैनिक तालिबान पर भारी पड़ रहे हैं। जब सब कुछ निशुल्क और बिना परिश्रम मिलता रहता है तो फिर अपने पैरों पर खड़ा होने की आदत छूट जाती है। अफगानिस्तान की विभिन्न सरकारें अगर चाहती तो फिर सैनिक तंत्र का मजबूत ढांचा बन सकता था जो तालिबान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों को काबू में रखने की वीरता दिखा सकता था। अगर भारत ने अपने संसाधनों के बल पर अफगानिस्तान की पुलिस और सैनिक तंत्र को प्रशिक्षित एवं विकसित नहीं किया होता तो फिर अफगानिस्तान की पुलिस और सैनिक तंत्र किसी काम के भी नहीं होते। आखिर तालिबान सत्ता लूटने के नजदीक क्यों पहुंच गए? दरअसल इसके पीछे तालिबान के साथ शांति वार्ता का सिद्धांत और अमेरिका की वापसी है। तालिबान के साथ शांति वार्ता कोई आज से नहीं बल्कि 5 साल से चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता को गति दी थी। ट्रंप ने अफगानिस्तान से निकलने की प्रतिबद्धता जताई थी। अफगानिस्तान सरकार, अमेरिका, पाकिस्तान और तालिबान के बीच शांति वार्ताएं चलतीं। कतर में तालिबान का राजनीतिक कार्यालय खुला। अरब के कट्टरपंथियों और यूरोप के मुस्लिम संगठनों से तालिबान के ऊपर धन की वर्षा होने लगी। धन की बहुलता से हथियारों की कमी दूर हुई, नए

तालिबान फिर खूंखार



तालिबान के पास 75 हजार से अधिक आतंकवादी

चीन पाकिस्तान में आर्थिक गलियारा बना रहा है, जिसके खिलाफ जन विद्रोह जारी है। तालिबानी आतंकवादी घुसपैठ कर पाकिस्तान को और भी हिंसक खतरनाक देश के रूप में तब्दील कर सकते हैं। तालिबान एक सुन्नी इस्लामिक आतंकवादी संगठन है। ईरान में शिया मुसलमानों के वर्चस्व के खिलाफ सुन्नी मुसलमानों का आतंकवाद जारी है। तालिबान के आतंकवादी ईरान में घुसकर शिया-सुन्नी संघर्ष को और भी हिंसक, खतरनाक और अमानवीय बना सकते हैं। तालिबान के पास 75 हजार से अधिक तालिबानी आतंकवादी हैं। अगर तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लेता है तो फिर इन 75 हजार आतंकवादियों को संयमित रखने और गतिशील रखने में वह कैसे सफल हो सकता है? इसलिए माना जा सकता है कि अफगानिस्तान फिर से इस्लाम की अति कूरता और हिंसा में तब्दील रहेगा। चीन, पाकिस्तान और ईरान को भी हिंसा और बर्बरता का सामना करना पड़ेगा। तालिबान उनके लिए भस्मासुर जैसा साबित होगा।

हथियार मिले। शांति वार्ता के कारण अमेरिकी और अफगानिस्तानी सैनिकों को शिथिल कर दिया गया, उनके हाथ बांध दिए गए। इस दौरान तालिबान ने अपने आपको मजबूत किया और हथियारों से लैस हुए।

अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह खोजा जा रहा है कि अमेरिका क्या सफल रहा, अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान कितने दिनों के अंदर सत्ता पर काबिज होंगे? इन सभी प्रश्नों पर कोई एक राय नहीं हो सकती। स्वतंत्र आंकलन यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान में अपने लक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है। उसने कोई एक या दो साल नहीं बल्कि पूरे 20 सालों तक अफगानिस्तान में तालिबान को नियंत्रित किया। अमेरिका ने न केवल तालिबान बल्कि पाकिस्तान को भी नियंत्रित किया। उसने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के साथ ही पाकिस्तान की आतंकवादी नीति की भी गर्दन दबाकर रखी।

अलकायदा के हमले के बाद अमेरिका के दो प्रमुख लक्ष्य थे। एक, अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारना, हमले के लिए सहायता करने वाली तालिबान सरकार को अस्तित्वविहीन करना और तालिबान के सरगना मुल्लाह उमर को मौत के घाट उतारना।

तालिबान का सरगना मुल्ला उमर खुद बीमारी का शिकार होकर मारा गया। ओसामा बिन लादेन का हथ्र भी जगजाहिर है। तालिबान बिना लड़े और बिना प्रतिशोध के ही काबुल छोड़कर भाग गए। अगर तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करने में भी सफल हो जाता है तो भी अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अमेरिका आसानी से तालिबान को नियंत्रित कर सकता है। अमेरिका अपने मिसाइल हमलों से तालिबान सरकार में बैठे लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। इसके अलावा अमेरिका सुरक्षा की कमजोरियां दुरुस्त हो चुकी हैं। अब आतंकवादी हिंसा करने के पूर्व ही पकड़ लिए जाते हैं। यही कारण है कि 9/11 की बड़ी घटना के बाद और कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई। चीन, पाकिस्तान और ईरान अमेरिकी सैनिकों की वापसी तथा अमेरिका की विफलता मानकर खुशियां मना रहे हैं। इनकी खुशियां मातम में तब्दील हो सकती हैं। इसलिए जब फिर से तालिबान की सरकार स्थापित होगी तो फिर अफगानिस्तान में स्थापित पहली तालिबानी सरकार की ही पुनरावृत्ति होगी। तालिबान के आतंकवादी चीन में बैठकर उग्र मुस्लिम आबादी के साथ लड़ सकते हैं।

● ऋतेन्द्र माथुर

हाल ही में फिल्मी दुनिया या बालीवुड में दिलीप कुमार की मृत्यु और आमिर-किरण की शादी का टूटना काफी चर्चा में रहा। इसके अलावा नीना गुप्ता की जीवनी के भी कुछ अंश पढ़ने में आए। नीना का साक्षात्कार भी एक चैनल पर प्रसारित हुआ। नीना का कहना है कि फिल्मों में सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी नई लड़की को किसी शादीशुदा डायरेक्टर से संबंध नहीं बनाने चाहिए क्योंकि एक तो आप उसकी जिंदगी में पहली लड़की नहीं हैं। ऐसी लड़कियां रोज उसके पास आती हैं। दूसरे, वह कभी भी आपके लिए अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा।

बहुत साल पहले मधुर भंडारकर ने फिल्म बनाई थी-फैशन। उसमें लगभग ऐसी ही घटना दिखाई गई थी। नीना ने यह भी कहा कि एक ऐसे ही डायरेक्टर से उनका नाम जोड़ दिया गया था। उन्होंने डायरेक्टर की पत्नी को भी बहुत समझाने की कोशिश की कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसकी पत्नी ने कहा था कि और भी लड़कियां तो उनके साथ काम करती हैं। उनके साथ क्यों नाम नहीं जुड़ा। फिर उस डायरेक्टर ने नीना को कभी काम नहीं दिया। हालांकि मशहूर फिल्म निर्देशक और प्रोड्यूसर सावन कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नीना गुप्ता ने मुझे कहा था कि कुछ भी कर लो मगर मुझे हीरोइन बना दो। उस समय सावन कुमार भी विवाहित थे। ऐसे ही राम गोपाल वर्मा ने एक बातचीत में कहा है कि वह किसी लड़की से कोई जबरदस्ती नहीं करते।

दिलचस्प है न कि जिस दौर में अपने देश में ऐसे कानून हैं, जहां मात्र पंद्रह सेकंड देखने भर से लड़के को सजा हो सकती है। गलत चित्र, कार्टून, अश्लील चुटकुला सुनाने को यौन शोषण के दायरे में रखा गया है, उन दिनों भी फिल्मी दुनिया की स्त्रियों के शोषण से जुड़ी सच्चाइयों पर कोई नहीं बोलना चाहता। वे लड़कियां भी नहीं जो इस तरह के शोषण से गुजरती हैं। और अनेक बार तमाम तरह की मुसीबतें झेलने के बावजूद उन्हें काम नहीं मिलता। यदि उनसे इस बारे में पूछो तो वे बड़ी मासूमियत से कहती हैं कि शोषण कहां नहीं है। 9 से 5 की नौकरी में भी है। सिर्फ फिल्मी दुनिया को ही बदनाम मत करिए। दरअसल वे इस सच्चाई को जानती हैं कि जिस दिन इन बातों पर मुंह खोलेंगी, काम मिलना बंद हो जाएगा। इस तरह के शोषण को



ताक पर मानवीय संबंध

संघर्ष कहा जाता है।

एक बार डिंपल कपाड़िया ने कहा था कि उन्हें काम पाने के लिए तरह-तरह के शोषण से गुजरना पड़ा है, मगर अब बस। हेमा मालिनी ने भी बहुत साल पहले, परवीन बाबी को याद करते हुए कहा था कि एक बार उसने बताया था कि एक फिल्म में काम पाने के लिए उसे कई लोगों को खुश करना पड़ा था। पुराने जमाने की मराठी अभिनेत्री हंसा वाडेकर ने भी अपनी आत्मकथा में इस तरह की बातों का जिक्र किया है। उनकी आत्मकथा पर भूमिका नाम से फिल्म भी बनी थी।

ऐसे में हम दशकों से देखते आ रहे हैं कि बड़ी-बड़ी हीरोइनें युवा लड़कियों को आकर बताती हैं कि वे यौन शोषण से कैसे बचें, वे एमपावर्ड वुमैन कैसे बनें, कैसे जो चाहें सो करें और अपने सपनों को उड़ान देने के लिए परिवार को छोड़ना पड़े तो भी कोई बात नहीं तो लगता है कि जो ज्ञान वे आकर देती हैं, उसमें भी अपने बहुत से व्यापारिक हित छिपे होते हैं। बात बेशक वे समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की कर रही हों। आपने यह भी देखा होगा कि दूसरी लड़कियों को सफलता के लिए परिवार को रोड़ा समझकर तंज देने का ज्ञान देने वाली ये तथाकथित एमपावर्ड हीरोइंस, शादी करते और मां बनते ही अचानक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मां होने का टैग अपने माथे से चिपका लेती हैं और

बहुत-सी जो कल तक अकेले रहने को दुनिया की सबसे अच्छी बात बता रही थीं, कहने लगती हैं कि वे तो बचपन से ही मां बनना चाहती थीं। उनका कैरियर नहीं, परिवार ही उनकी प्राथमिकता है।

बहुत बार जब इनके रिश्ते टूट जाते हैं, शादी नहीं चल पाती है तो भी ये एक डिप्लोमेटिक चुप्पी ओढ़ लेती हैं। आमिर की पत्नी किरण राव ने भी ऐसा ही किया है। हालांकि किरण हीरोइन नहीं है, मगर वह एक बड़े अभिनेता की पत्नी हैं, फिल्म निर्माता भी हैं, इसलिए शायद उन्होंने कुछ मीठे-मीठे बयान दिए और चुप रहना ही बेहतर समझा है। हालांकि हाल ही में जारी एक वीडियो में अभिनेता और फिल्म समीक्षक केआरके ने यह भी बताया कि आमिर और किरण की ये खबर दरअसल एक पीआर एजेंसी जो इन दोनों का काम देखती है, उसकी रणनीति का हिस्सा है। इसी बहाने आमिर की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा का प्रमोशन होने की योजना बनाई गई। जितनी निगेटिव पब्लिसिटी, उतनी ही सफलता। इसी एजेंसी ने आमिर से किरण को भारत में डर लगाने वाला बयान दिलवाया था। यही एजेंसी दीपिका पादुकोण की ब्रांडिंग का काम भी देखती है। इसलिए इसी ने छपाक के प्रमोशन के दौरान दीपिका को विरोध करते छात्रों के बीच भेजा था।

● ज्योत्सना अनूप यादव

यह कितने अफसोस की बात है कि मानवीय संबंधों की गरिमा को व्यापार के हितों को देखते हुए कुर्बान किया जा रहा है। कहां तो संबंधों को चलाने के लिए हर स्वार्थ और लालच की बलि दे दी जाती थी, मगर अब इसका उलटा हो रहा है। दर्शक के हर इमोशन पर व्यापारी वर्ग की नजर लगी हुई है। उसका शोषण करके, भावनाओं में बहाकर, उन्हें भड़काकर, किस तरह अपनी जेब भरी जाए, यह इन दिनों नया नार्मल बन चला

मानवीय संबंधों की गरिमा व्यापार पर कुर्बान

सच कहना, सच की तरह से पेश करना, इस दौर की सच्चाई है। अक्सर ये अभिनेता-अभिनेत्रियां समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, मगर करते इसके विपरीत हैं। क्या यही समाज के प्रति जिम्मेदारी है कि लोगों को भ्रम में डालकर, उनकी भावनाओं का शोषण किया जाए।

है। हर नए विचार को हड़प कर उसे अपने तरीके से तोड़-मरोड़कर पेश करना, झूठ फरेब को सच कहना, सच की तरह से पेश करना, इस दौर की सच्चाई है। अक्सर ये अभिनेता-अभिनेत्रियां समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, मगर करते इसके विपरीत हैं। क्या यही समाज के प्रति जिम्मेदारी है कि लोगों को भ्रम में डालकर, उनकी भावनाओं का शोषण किया जाए।

गो स्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीरामचरितमानस केवल भक्तिमार्ग के साधकों का भाव ही पुष्ट नहीं करती, वरन उनका अध्यात्मिक, सामाजिक तथा व्यावहारिक जीवन का मार्गदर्शन भी करती है। एक संपूर्ण व्यावहारिक जीवन दर्शन को समेटे हुए एक ऐसा ग्रंथ है जिसने हम संसारी जीवों के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विभिन्न अंगों के लिए आदर्श स्थापित किया है।

एक संपूर्ण व्यावहारिक जीवन दर्शन को समेटे हुए ग्रंथ के रूप में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीरामचरितमानस पर जितनी भी चर्चा, आलोचना-समालोचना और समीक्षा हुई है उतनी शायद ही किसी अन्य लिपिबद्ध ग्रंथ की हुई होगी, और हो भी क्यों न? ऐसा और कौन सा ग्रंथ है, जिसने हम संसारी जीवों के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विभिन्न अंगों को इतने मर्मस्पर्शी एवं स्पष्ट ढंग से छुआ हो, चाहे वह परिवार के सदस्यों के परस्पर संबंधों की गरिमा-मर्यादा हो, समाज के विभिन्न वर्गों के आपसी संबंधों की मर्यादा हो अथवा राजकीय काम-काज व राजा के कर्तव्यों की।

श्रीरामचरितमानस में निरूपित जीवन-व्यवस्था एक आदर्श समाज एवं आदर्श राज्य की कोरी कल्पना मात्र न होकर पूर्णतः अनुभवगम्य और व्यावहारिक है। इस ग्रंथ के माध्यम से गोस्वामीजी ने परस्पर स्नेह-सम्मान के साथ कर्तव्य-परायणता के माध्यम से न केवल जीवन को समृद्ध-सुखी बनाने में असंख्य-अप्रतिम योगदान दिया है वरन मानस के पात्रों के माध्यम से ढेरों सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में अभूतपूर्व कार्य किया है।

आज के संदर्भ में हमारे समक्ष विद्यमान विशालतम चुनौतियों में जो अग्रणी हैं उनमें सामाजिक व्यवस्था में समरसता का उत्तरोत्तर ह्रास प्रमुख है। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि इक्कीसवीं सदी के उन्नीस वर्ष और भारतीय संविधान लागू होने के उनहत्तर वर्ष बाद भी वर्ण-व्यवस्था और रुढ़ियों के कुचक्र को भेदने में सफल होने की अपेक्षा हम उसमें और उलझते जा रहे हैं और अपने वर्तमान को संभालने के संकट से जूझ रहे हैं।

सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता-अखंडता के लिए रामचरितमानस ने जो योगदान कई सौ वर्ष पूर्व किया था वह आज भी उतना ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक प्रासंगिक तथा आवश्यक है।

मानस के रचना काल को देखें तो पता चलता है कि उस समय वर्ण-व्यवस्था के अतिरिक्त भारतीय समाज मुख्यतः दो सम्प्रदायों (वैष्णव और शैव) में विभाजित था। तत्कालीन अन्य



वर्तमान संदर्भ में श्री रामचरितमानस की प्रासंगिकता

वैश्विक धर्मों के मतावलम्बियों में विभाजित समूहों-अनुयायियों की भांति, हिंदू धर्म के अनुयायी भी दो वर्गों में विभक्त थे और अपने पंथ (वैष्णव-शैव) तथा आराध्य (भगवान श्री राम एवं भगवान शंकर) को एक-दूसरे से उच्चतर समझने की वजह से प्रायः एक-दूसरे से विद्वेष-विद्रोह में अपना समय व ऊर्जा व्यर्थ करते थे जिसके फलस्वरूप हानि अंततः समाज की होती थी।

साहित्यकार समाज का पारखी होता है, समाज की दिशा-दशा पर दृष्टि रखता है तथा अपनी लेखनी के माध्यम से कुरीतियों का शमन करने और समाज के उत्थान में अपनी भूमिका निभाता है। निश्चित रूप से गोस्वामी तुलसीदासजी ने मानस के माध्यम से तत्कालीन समाज को इस सांप्रदायिक विभाजन के फलस्वरूप होने वाली हानि से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान के दोनों स्वरूपों (भगवान शंकर एवं भगवान श्रीराम) को एक-दूसरे का उपासक बता कर, एक-दूसरे के प्रति सम्मान दिखाकर उनके अवलम्बियों-उपासकों के परस्पर द्वंद्व को निर्मूल कर दिया।

बालकांड में वर्णित प्रयागराज के मुनि-समामग में ऋषि भरद्वाज अपनी जिज्ञासा की शांति हेतु ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ अपने संवाद में भगवान शंकर को भगवान श्रीराम का उपासक बताते हुए कहते हैं कि हर कोई अविनाशी भोलेनाथ की उपासना करता है, वहीं स्वयं भगवान शंकर श्रीराम की महिमा का बखान करते हैं -

‘संतत जपत संभु अविनासी,
सिव भगवान ज्ञान गुन रासी।
सोपि राम महिमा मुनिराया,
सिव उपदेश कीन्ह करि दाया।’
इसके पश्चात-
‘सम्भु समय तेहि रामहिं देखा,
उपजा हियं अति हरष विसेषा।
तिन्ह नृपसुतहिं कीन्ह परनामा,
कहि सच्चिदानंद परधामा।।’

तथा ‘जासु कथा कुम्भज ऋषि गाई ‘सोइ मम इष्ट देव रघुबीरा’ के माध्यम से बार-बार शंकर का राम के प्रति सम्मान दिखाना निश्चित ही शैवों के मन से वैष्णवों के प्रति विद्वेष भाव समाप्त करने और दोनों संप्रदायों के बीच की खाई को भरने और उनमें परस्पर सौहार्द स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया अत्यावश्यक, सार्थक, सफल प्रयास था। यही नहीं बालकांड में माता पार्वती को श्रीराम जन्म-प्रसंग की कथा सुनाते हुए भगवान शंकर जन्मोत्सव का आनंद देखने के लिए कागभुशुण्डि के साथ मनुष्य रूप में चोरी से अपने अयोध्या विचरण तथा बाल-लीला देखने की चर्चा करते हैं, जिससे उनके मन में भगवान राम के प्रति आदर परिलक्षित होता है।

मानस में किष्किंधाकांड का प्रसंग रखने की पृष्ठभूमि में गोस्वामी जी के मन में केवल मित्रता मात्र का वर्णन करना नहीं था वरन इसके माध्यम से वह यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि राजा (शासक) को किसी बड़े काम की सफलता के लिए (चाहे वह शत्रु-विजय हो अथवा कोई अन्य बड़ा सामाजिक-राष्ट्रव्यापी अभियान), जन-सहभागिता (सबके विकास के लिए सबका साथ) परम आवश्यक है। मानस के उपर्युक्त प्रसंग इस बात की पर्याप्त पुष्टि करते हैं कि समरसता (सोशल हारमनी) के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण (नेशनल इंटीग्रेशन) रामचरितमानस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है।

● ओम

गजल



आदमी बनने से जुदा होना।
और इंसान का खुदा होना।
ऐब यह आदमी में पुशतों से,
मतलबी बनकर बेवफा होना।
जड़ो को भूल गया है अहमक,
अब तो तय है तेरा फना होना।
कई सालों से देखता आया,
मंजिलों का यूँ रास्ता होना।
सांप मेंढक की हिफाजत में है,
सोच लो अब भला है क्या होना?
'गंजरहा' टूटकर बहुत रोया,
बहुत मुश्किल है बावफा होना।
- डॉ. दिवाकर दत्त त्रिपाठी 'गंजरहा'

अ चानक एक दिन कॉलेज में चन्द्रविजय ने कहा, 'सुनो, चकोरी, पापा मुझे आगे की पढाई के लिए टोक्यो भेज रहे हैं, एक महीने में मैं यहाँ से चला जाऊंगा।'

'कैसे तुमने ये सोच लिया, कि मैं तुम्हें बिना देखे, बिना मिले भी जीवित रहूँगी।' ये चकोरी के शब्द थे।

'अरे, डिअर, दिल मे मेरे भी रह-रहकर टिस उठ रही है, ये वो दर्द है, जो कोई पेनकिलर से भी खत्म नहीं होगा। क्या करूं, पापा की ख्वाहिशों को मैं झुठला नहीं सकता। देखो मेरी आंखें, कल से एक सेकंड को भी तुम दूर नहीं हुई।'

एक वादा करता हूँ, चकोरी, जब भी तुम आकाश के चांद को देखोगी, तुम्हें मेरी सूरत दिखाई देगी, तुम ये गाना जरूर गुनगुनाना 'जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला' और चकोरी का चंदू उससे भविष्य में जरूर मिलेगा, ये

चांद और चकोर



बोलकर चला गया।

भाग्य की रेखाएं बिना सोचे समझे कहीं भी मुड़ जाती हैं, और चकोरी के पापा ने उसकी शादी एक सूरज नामक लड़के से कर दी, चकोरी सिर्फ सूनी नजरों से अपना श्रृंगार देखती रह गई। सूरज के ताप से प्यार तो नहीं

सिर्फ एक धन वैभव का संसार पाया।

आज पूर्णमासी थी, गार्डन में घूमते हुए, अपने चंदू को देखते हुए, फिर गुनगुनाने लगी 'जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला'

- भगवती सक्सेना गौड़

जब से कामिनी का फोन आया था कि मैं सबकुछ छोड़कर तेरे पास आ रही हूँ, उसके मन में हलचल सी मची थी।
प्यार! एक शब्द है? नहीं-नहीं प्यार एक अहसास है, एक भरोसा है, विश्वास है।

'हे प्रभु! आज जब मेरा प्यार मेरी बाहों में सिमटने आ रही है तो मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूँ?'

कंचन, संग कामिनी उससे ब्याह करने के लिए अपना घर त्यागकर आ गई। आते ही कामिनी बाहों के घेरे में समा गई।

स्पर्श विद्रोह पर उतारू हो गया! अरे! विवेक यह तुम क्या करने जा रहे हो? एक स्त्री की आबरू तेरी बाहों में है।

क्या तुम चोर हो, डाकू हो या लुटेरा हो? उसके हाथ ढीले पड़ने लगे। नहीं-नहीं; कामिनी मेरा प्यार है, मेरी दुनिया है।

ओह! यह मैं क्या करने जा रहा था?

यह भी किसी की संतान है, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी प्यार के लिए सारे जीवन की जमापूँजी सामाजिक प्रतिष्ठा सब लेकर चली गई है तो उन पर क्या बीतेगी?

कामिनी बाहों में कितने सूकून से सिमट कर गले से लिपटी है! कामिनी का भरोसा अपना प्यार आज सब कुछ दाव पर लगा था।

बाहों के घेरे



दिलोदिमाग की जद्दोजहद में किसकी जीत होगी, यह सोचने का वक्त नहीं था। एक टैक्सी बुला कर कामिनी के साथ नए सफर की ओर चल पड़ा।

कामिनी आंखें बंद कर लेट गई। गाड़ी रुकते ही आसपास नजर दौड़ाई- 'अरे! विवेक यह तुमने क्या किया?'

विवेक बिना कुछ जवाब दिए उसकी बाहें थाम घर के अंदर कदम बढ़ाया।

आधी रात में घर के सभी सदस्य जाग रहे थे। सामने विवेक के संग बेटी को देखकर सब समझ में आ गया।

विवेक उन लोगों से मुखातिब होकर बोला- 'माफ़ किजिए; मैं आपकी अमानत वापस लौटाने आया हूँ। प्यार हमने किया है, फिर आजीवन सजा आप लोग क्यों भुगतें?'

कहते हुए वह वापस लौटने लगा।

उसके बढ़ते कदमों को रोकने के लिए कामिनी के माता-पिता ने अपनी बाहें फैला दी- 'बेटे दिलोदिमाग की जंग में तुमने हमें हरा कर भी जीत लिया।'

बाहों के घेरे में कैद होकर भी मानों पंख लग गए, अहा! स्पर्श की ताकत में कितना कुछ समाहित है!!!

- आरती रॉय

टोक्यो ओलंपिक के शुरू होते ही भारत में अचानक से खेलों के प्रति नजरिया बदल गया है। पुरुषों के वर्चस्व वाला क्रिकेट खबरों में पीछे चला गया है। ओलंपिक में भी लड़कियों के बाजी मार लेने की चर्चा है। टोक्यो ओलंपिक के पहले ही दिन वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर इतिहास बना दिया। असम की लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल हार जाने के बावजूद पीवी सिंधू बैडमिंटन कांस्य पदक की रेस में बनी हुई हैं। कमलप्रीत कौर, वंदना कटारिया ने भी नाम किया है। उधर, दर्जनों खेलों में भारतीय लड़के पदक पाने की कोशिशों में हैं।

लवलीना बोरगोहेन



टोक्यो ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए एक और पदक पक्का कर दिया है। 23 वर्षीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने वेल्टरवेट वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन चेन निएन-चिन को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन का पदक तय हो चुका है। लेकिन, उन्होंने इसे गोल्ड में बदलने की हुंकार भर दी है। सेमीफाइनल में प्रवेश के बाद लवलीना ने कहा कि मेडल तो सिर्फ एक होता है, वो है गोल्ड।

पीवी सिंधू



भारतीय शटलर पीवी सिंधू गोल्ड की रेस से भले ही बाहर हो चुकी हों, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में अभी भी उनके पास पदक की उम्मीद बची हुई है। महिला एकल में शटलर पीवी सिंधू का सेमी-फाइनल मुकाबला वर्ल्ड नंबर-1 चीनी ताइपे की ताइ जू यिंग के बीच था। जिसमें उन्हें टोक्यो ओलंपिक की पहली हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले के सभी क्वालीफाईंग और क्वार्टर फाइनल मैचों में पीवी सिंधू ने शानदार प्रदर्शन किया था।

टोक्यो में छापीं भारतीय लड़कियां

टोक्यो ओलंपिक के पहले ही दिन मीराबाई चानू ने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। पूर्वोत्तर भारत के एक छोटे से गांव की इस 26 वर्षीय

मीराबाई चानू

लड़की ने वेट लिफ्टिंग की प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए स्नेच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में

115 किलोग्राम का भार उठाकर साबित कर दिया कि भारतीय लड़कियां कोई भी वजन आसानी से उठा सकती हैं। बशर्ते इसके लिए उन्हें माहौल दिया जाए। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में भारत की ओर से सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए एक और पदक पक्का कर दिया है।



वंदना कटारिया



टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम की ओर से हैट्रिक लगाने वाली उत्तराखंड की वंदना कटारिया का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। दक्षिण अफ्रीका के साथ करो या मरो के मैच में वंदना कटारिया ने लगातार तीन गोल दागकर भारतीय महिला हॉकी टीम को 4-3 से जीत दिलाई। वंदना कटारिया गोल की हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इसी साल मई में वंदना के पिता का निधन हो गया था और वो बेंगलुरु में ओलंपिक की तैयारी करने के चलते हरिद्वार नहीं आ सकी थीं।

मैरी कॉम

छह बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम टोक्यो ओलंपिक में पदक की रेस से भले ही बाहर हो चुकी हों। लेकिन, वो हर भारतीय लड़की के लिए एक आइकॉन बन गई हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम फ्लाईवेट के प्री क्वार्टरफाइनल में तीन में से दो राउंड जीतने के बाद भी जजों के खराब फैसले के चलते बाहर हो गईं। मैरी कॉम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के मुक्केबाजी कार्यबल की 10 सदस्यीय एथलीट ग्रुप का हिस्सा हैं और पैनल में एशियाई ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करती हैं। 38 वर्षीय भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने अपने बच्चों की परवरिश के साथ ही अपने खेल पर पूरा फोकस बनाए रखा है।

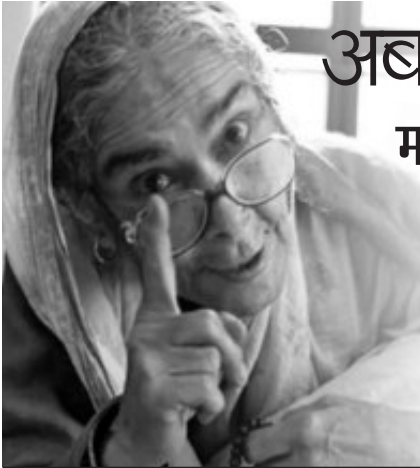


कमलप्रीत कौर

टोक्यो ओलंपिक की डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में भारत की कमलप्रीत कौर ने अपने प्रदर्शन की बदौलत फाइनल में जगह बना ली है। कमलजीत ने डिस्कस थ्रो के तीसरे प्रयास में 64 मीटर का थ्रो कर फाइनल में जगह पक्की की है। पढ़ाई में कमजोर कमलप्रीत कौर ने खेल की ओर ध्यान दिया और आज अपने प्रदर्शन के दम पर ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर ओलंपिक के फाइनल में है। अगर कमलप्रीत कौर अपने प्रदर्शन को बनाए रखती हैं, तो एथलेटिक्स में भारत के लिए मेडल लाने वाली पहली भारतीय बन जाएंगी।



● आशीष नेमा



अब यादों में बालिका वधु की दादी सा

म शहूर एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। वे 75 साल की थीं। सीरियल बालिका वधू में उन्होंने दादी सा की भूमिका निभाई थी। सुरेखा के पास बधाई हो फिल्म के बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया था। इसलिए, पिछले साल उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की ओर से 65 साल से अधिक उम्र के एक्टर्स पर शूटिंग के लिए लगाया बैन हटाने की मांग भी की थी।

मदद पर कहा था- मुझे भीख नहीं चाहिए

सुरेखा सीकरी ने मुश्किलों के दौरान कहा था, 'एड फिल्मों के ऑफर मेरे लिए काफी नहीं हैं, मुझे और ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि मेडिकल बिल के अलावा मेरे भी कई खर्च हैं लेकिन प्रोड्यूसर्स कोई रिस्क नहीं ले सकते। लोगों ने मेरी आर्थिक मदद करने की कोशिश की जिसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। लेकिन मैंने किसी से कोई आर्थिक मदद नहीं ली है। मुझे काम दीजिए और मैं सम्मान से पैसा कमाना चाहती हूँ।'

अभिनय की दुनिया में बिताए 50 साल... सुरेखा सीकरी भारतीय थिएटर, फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम थीं। 1978 राजनीतिक ड्रामा किस्सा कुर्सी का में वे पहली बार नजर आई थीं। इसके बाद, वह कई हिंदी सोप ओपेरा का हिस्सा बनीं। उम्र में जन्मी सुरेखा सीकरी ने 1971 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में से अपनी एक्टिंग को निखारा। वरिष्ठ अभिनेत्री ने 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी जीता। बालिका वधू में कल्याणी देवी के रूप में उनका रोल टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय किरदारों में से एक है। उन्हें आखिरी बार जोया अख्तर की घोरस्ट स्टोरीज के सेगमेंट में देखा गया था, जिसका प्रीमियर नेटपिलक्स पर हुआ था। उन्होंने हेमंत रेगे से शादी की थी और उनका एक बेटा राहुल सीकरी है।

काम की तलाश में पैदल घूमते थे राजपाल यादव, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी जेब में नहीं थे पैसे

बॉ लीवुड की कई फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों को हंसाते हुए नजर आए राजपाल यादव को इस इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा था। साल 2018 में राजपाल यादव लोन ना चुका पाने के चलते भी तीन महीनों की जेल की सजा काट चुके हैं। अब अपने इस उतार-चढ़ाव भरे सफर पर बात करते हुए राजपाल ने बताया है कि आर्थिक तंगी की हालत में उन्हें इंडस्ट्री के कई लोगों का खूब सपोर्ट मिला था, जिससे वो दोबारा वापसी कर पाए हैं। एक इंटरव्यू में राजपाल यादव ने अपने आर्थिक तंगी के दौर पर कहा, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। अगर लोग मेरी मदद नहीं करते तो आज मैं यहां कैसे होता। पूरी दुनिया मेरे साथ थी। मेरा यकीन मेरे साथ था, हमेशा आगे बढ़ने के लिए। मैं जानता था कि मेरे पास सपोर्ट है।



'जब जिंदगी आसान हो तो मिशन मुश्किल लगता है'

अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए राजपाल ने कहा, जब आप मुंबई आते हैं तो एक अनजान शहर मिलता है, जहां आप बोरीवली पहुंचने के लिए कई लोगों के साथ ऑटो शेयर करते हैं। और जब आपके पास ऑटो के पैसे नहीं होते तो आप जुहु, लोखंडवाला, आदर्श नगर, गोरेगांव और कभी-कभी बांद्रा भी पैदल जाते हैं। अपने पास फोटोज रखकर कामयाबी दूढ़ते हैं। जब जिंदगी मुश्किल लगती है तो मिशन आसान होता है और जब जिंदगी आसान होती है तो मिशन मुश्किल लगता है।

फिल्म 'दिल धड़कने दो' में प्रियंका और रणवीर की मां का रोल करने से हिचकिचा रही थीं शेफाली शाह

बॉ लीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस शेफाली शाह ने एक बार खुलासा किया था कि वो फिल्म दिल धड़कने दो को साइन करने को लेकर काफी कंप्यूज्ड थीं। जोया अख्तर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शेफाली ने अनिल कपूर की पत्नी, प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह की मां की भूमिका निभाई थी। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान शेफाली ने कहा कि वे फिल्म साइन करने के बारे में श्योर नहीं थी क्योंकि वो फिल्म में प्रियंका और रणवीर की मां की भूमिका निभा रही थीं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि रीयल लाइफ में दोनों एक्टर्स उनकी उम्र के करीब हैं।

जोया को फिल्म के लिए ना नहीं कर पाई थीं शेफाली

शेफाली कहती हैं, जब जोया ने मुझे फिल्म ऑफर की तो उन्होंने मुझसे कहा मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन यह एक मां की भूमिका है। मैंने



रिफ्ट पट्टी और अपने पति से कहा कि यह मेरे द्वारा पढ़ी गई सबसे अच्छी रिफ्ट्स में से एक है और यह रोल शानदार है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि समस्या क्या है और जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे इसे लेने की सलाह दी। आशंका थी कि प्रियंका और रणवीर मेरी उम्र के करीब हैं। लेकिन जैसा कि मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह से लिखा गया था, मैं ना नहीं कह सकती थी।

मंत्रिमंडल से आपकी निकासी के पीछे क्या कारण रहे?' 'ज्यादा कुछ तो मुझे भी नहीं मालूम, पर सुनने में आ रहा है कि आलाकमान कहता है कि उसे चकमक पत्थर नहीं, पारस चाहिए। ऐसा बंदा हो जो एक साथ कई काम निपटा सके।



कहीं दीप जले, कहीं दिल

लो कतंत्र और संविधान बचाने की कसम खाकर वह जैसे ही बाहर निकले, हम उनकी ओर लपके। वह भारी भीड़ से घिरे थे। हमें देखते ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया। उन्हें शुभकामना देते हुए हमने समय मांगा तो बोले, 'मुझे खुशी है कि आप मेरी आवाज जनता तक पहुंचा रहे हैं। कहिए कहां चलकर बात करें?' उनकी इस उदारता पर निखार होते हुए मैंने तुरंत प्रस्ताव फेंका, 'कोने में ठीक रहेगा?' वह हंसते हुए बोले, 'क्यों नहीं! बस हमें अखबार के कोने में मत धकेल दीजिएगा। मेरी संघर्ष-कथा को यदि मुख्य पन्ने पर स्थान मिले तो जनता का बड़ा हित होगा।'

'आपको मंत्रिमंडल में शामिल होने पर कैसा लग रहा है?'

उनकी यह बात सुनकर मैं दंग रह गया। ऐसे समय में जब जनहित का भयंकर 'टोटा' पड़ा हो, उसकी बात भी करना किसी दुस्साहस से कम नहीं, तब उनका जनता और उसके हित के बारे में सोचना सोने पर सुहागा है। तसल्ली हुई कि सही आदमी से सवाल कर रहा हूँ। बिना देरी किए मैंने बात जारी रखी, 'आपको मंत्रिमंडल में शामिल होने पर कैसा लग रहा है?' 'जी, मंत्री पद मिलना कोई लॉटरी लगने जैसा नहीं है। हमने इसके लिए बकायदा होमवर्क किया है। पुरानी विचारधारा त्यागी। नई निष्ठा पकड़ी। पुरानी पार्टी एवं पुराने समीकरण तोड़े। जातीय, क्षेत्रीय और चुनावी-एंगल वाले कई टेस्ट पास किए। तब यहां तक आए हैं। इतनी मेहनत का फल तो

मिलना ही था। अब मैं सुख और दुख जैसे सांसारिक चोंचलों से परे हो गया हूँ। पहले मुझे जो विकराल समस्याएं लगती थीं, अब जरूरतें लगने लगी हैं। हमारे सोच का दायरा पेट्रोल-पंप के मीटर से भी ज्यादा बढ़ रहा है। हमें साफ और सिर्फ बेहतर दिखे इसलिए चश्मा भी बदल लिया है। इससे भ्रष्टाचार और महंगाई जैसी सारहीन चीजें दिखती ही नहीं। निवेदन है कि सवाल भी आप जरा सलीके वाले करें। ट्विटर जैसा व्यवहार कतई न करें।'

'आप बिल्कुल निसाखातिर रहें। हम बहुत जिम्मेदार हैं। यह सुनने में आया है कि नाराजगी के चलते आपको मौका दिया गया। आखिर किस बात से नाराज थे आप?' अपने सुर को और मधुर बनाते हुए हमने पूछ लिया। 'देखिए, हमें किसी पद की लालसा कभी नहीं रही। हमारा पूरा जीवन संघर्ष में बीता है। संघर्ष करते गए, पद अपने आप मिलते गए। हां, मेरे लोग जरूर नाराज थे। कार्यकर्ताओं ने हमें जिताने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। उनका संघर्ष व्यर्थ हो जाता यदि मैं जनता की सेवा न कर पाता। बड़े दिनों बाद घर में बच्चे बहुत खुश हैं। कार्यकर्ताओं से ज्यादा रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं। इसके लिए हम आलाकमान के शुक्रगुजार हैं। दरअसल जब भी मुझे जनसेवा करने से वंचित किया जाता है, विद्रोही हो उठता हूँ। इसके लिए मैं किसी बात का लिहाज नहीं करता। मेरे लिए जनसेवा सर्वोपरि है। वह हम हर हाल में करके रहेंगे। मेरे इस संकल्प के पीछे खास वजह है। बचपन में ही एक बड़े ज्योतिषी ने बताया था कि

मेरी कुंडली में राजयोग है। फिर इसे नकारने वाले हम और आप कौन होते हैं!' वह अपने मंत्रालय की नई बनी इमारत की ओर निहारते हुए बोले।

आलाकमान को चकमक पत्थर नहीं, पारस चाहिए...

तभी सामने से मास्क लगाए दूसरे सज्जन तेजी से निकलते दिखाई दिए। हमने उनको टोक दिया। 'भई, मैं 39 मिनट पहले तक मंत्री था, अब नहीं। अब मुझसे क्या पूछोगे?' हमने बड़ी मासूमियत से पूछा, मंत्रिमंडल से आपकी निकासी के पीछे क्या कारण रहे?' 'ज्यादा कुछ तो मुझे भी नहीं मालूम, पर सुनने में आ रहा है कि आलाकमान कहता है कि उसे चकमक पत्थर नहीं, पारस चाहिए। ऐसा बंदा हो जो एक साथ कई काम निपटा सके। विपक्षी इतने भर से ही लहालोट हैं कि कुछ पक्षियों के पर कतरे गए हैं। कुछ यह भी कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद आखिरकार सरकार के हाथ मास्टर-स्ट्रोक लगा है। बाकी असल स्ट्रोक किसे लगा है, यह आप लोग ही बताएं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरे प्रदेश में फिलहाल चुनाव नहीं हैं। मेरी किस्मत ही खराब है।' यह कहते हुए वह आगे बढ़ गए।

दूर एक 'चिराग' जल रहा था

तब तक भीड़ छंट चुकी थी। कसम खाने वाले मंत्री भी जा चुके थे। शाम का धुंधलका गहराने लगा था। मैं अखबार के दफ्तर की ओर निकल पड़ा। देखा, दूर अभी भी एक 'चिराग' जल रहा था।

● संतोष त्रिवेदी

विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए



E-Magazine पढ़ने और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं
www.akshnews.com

वार्षिक सदस्यता के लिए संपर्क करें, 150, जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल
फोन: 0755-4017788, 2575777

D-17008

Science House Medicals Pvt. Ltd.



**For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us**

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023

GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5  **Email : shbpl@rediffmail.com**

 **Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687**